R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 14

16 से 30 अप्रैल 2022

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.

आखिर इतना आक्रोश क्यों?

देश में अचानक एकसाथ
एक जैसी वारदात की वजह क्या?

सांप्रदायिक हिंसा के पीछे
विदेशी ताकत या चुनावी षड्यंत्र?

बुन्देलखण्ड में विकास की मजबूत आधारशिला

केन-बेतवा लिंक परियोजना

बदलेगी तकदीर, सँवरेगी तस्वीर

मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा में बहने वाली केन और मध्यप्रदेश का जल लेकर यमुना में मिलने वाली बेतवा को जोड़कर प्रदेश की धरती को शस्य-श्यामला बनाने का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र को केन-बेतवा लिंक योजना की 44 हजार 605 करोड़ रुपये की सौगात देकर पिछड़े क्षेत्र को विकास की धारा में लाने के लिये बड़ा कदम उठाया है। इससे 20 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी और 41 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा।

उद्देश्य

- बुन्देलखण्ड की दो बड़ी नदी केन एवं बेतवा को आपस में जोड़कर बारिश के पानी को उपयोग के लिये संग्रह करना
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना
- परियोजना से किसानों और आमजन के जीवन और खेती में बदलाव लाना
- पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नदी जोड़ने का सपना पूरा करना
- रोजगार के अवसर में वृद्धि से रुकेगा पलायन

परियोजना से लाभ

- बुन्देलखण्ड अंचल में 23733 वर्ग किलोमीटर में फैली 'बेतवा-केन नदियों' की जीवन-रेखा
- घसान, सिंध (काली सिंध) नर्मदा का प्रवाह भी अंचल की आर्थिक समृद्धि में सहायक
- मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को लाभ
- मध्यप्रदेश के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल
- 20 लाख एकड़ क्षेत्र में होगी सिंचाई
- साढ़े नौ लाख किसानों को फायदा
- 41 लाख लोगों को पीने का साफ पानी
- 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट बनेगा
- उद्योग-धंधों को मिलेगा बढ़ावा

इस अंक में

भर्राशाही

9 | मंत्री के ओएसडी की भर्राशाही

सहकारिता विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर पदस्थ अरविंद सिंह सेंगर जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री के ओएसडी हैं, उनका विवादों और घपले-घोटालों से पुराना नाता है। अभी हाल ही में उनके खिलाफ लोकायुक्त...

राजपथ

10-11 | नए चेहरों पर दांव

मप्र में भाजपा और कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अब रिपोर्ट कार्ड से मिशन 2023 फतह होगा। सरकार और विपक्ष का अपना-अपना चुनावी रिपोर्ट कार्ड होगी। भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे का रिपोर्ट कार्ड...

तैयारी

13 | अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से...

मप्र को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। भोपाल और इंदौर के बीच बहुत जल्द ही देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तकनीकी टीम...

मप्र कांग्रेस

18 | कमलनाथ के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल!

मप्र कांग्रेस नेताओं ने पिछले सप्ताह 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान के हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा जैसे निर्णय आमतौर पर गांधी परिवार ही लेता आया है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

सत्य, धर्म, दया और मर्यादा के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम बने भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमीं पर इस बार आधा दर्जन से अधिक राज्यों में जिस तरह की हिंसक वारदातें हुईं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना आक्रोश क्यों? क्योंकि अभी तक धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमीं मनाई जाती थी, लेकिन इस बार सभी जगहों पर हिंसा का पैटर्न एक जैसा था। हिंसा की इन घटनाओं ने संविधान, लोकतंत्र और बहुलतावाद में विश्वास रखने वाले शांतिप्रिय भारतवासियों की चिंता बढ़ा दी है।

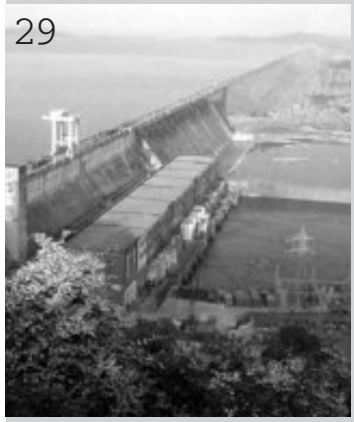

राजनीति

30-31 | कांग्रेस की दुर्गति...

आखिर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? कई जानकारों के अलावा अब पार्टी के भीतर भी इसके लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह निष्कर्ष सच तो है, किंतु यही पूरी सच्चाई नहीं। क्या इस संदर्भ में केवल गांधी परिवार...

महाराष्ट्र

35 | राज ठाकरे का हिंदुत्व

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति दो चीजों पर केंद्रित होती है- एक मराठी मानुष और दूसरा कट्टर हिंदुत्व। मौका देखकर राज ठाकरे का फोकस बदलता भी रहता है। राज ठाकरे की ताजा दिलचस्पी हिंदुत्व की राजनीति में लग रही है, तभी तो मुस्लिमों को नए सिरे से...

बिहार

38 | जंगलराज और सुशासन

नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन बाबू की छवि बना रखी है। लेकिन ये छवि इतनी नाजुक है कि श्रेष्ठता साबित करने के लिए हमेशा ही जंगलराज का नाम लेना ही पड़ता है। पहले चुनाव से लेकर 2020 तक। अब नीतीश कुमार को एक बार भी इतना भरोसा नहीं...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

रिजर्वेशन, रोटेशन, परिसीमन की फांस...

विनोद बक्सरी का एक शेर है...

वोट की चोट के डर ने ऐसा भरमाया
सरकार ने चुनावों को ही दूर भगाया

उपरोक्त पंक्तियां मप्र में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की फिलहाल की स्थिति पर सटीक बैठती हैं। दरअसल, मप्र में पिछले 2-3 साल से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अधर में लटके हुए हैं। पहले कमलनाथ सरकार और अब शिवराज सरकार रिजर्वेशन, रोटेशन और परिसीमन की आड़ में पंचायत और निकाय चुनाव टाल रही है। भाजपा और कांग्रेस आरोप लगाकर चुनाव टालने का जिम्मेदार एक-दूसरे को बता रही हैं। असल वजह यह है कि पहले कांग्रेस और अब भाजपा को वोट की चोट का डर सता रहा है। इसलिए रिजर्वेशन, रोटेशन और परिसीमन का दांव खेला जा रहा है। अभी भी तय नहीं है कि इस साल ये दोनों चुनाव हो पाएंगे कि नहीं। दरअसल, 3 साल से अटके पड़े पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने से सरकार हिचक रही है। पंचायतों में 2 साल कार्यकाल बढ़ाकर सरपंचों को एडजस्ट किया गया। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के चलते निकाय आरक्षण कोर्ट में पहुंच गया, तो पंचायत चुनाव में रोटेशन-परिसीमन के साथ ओबीसी आरक्षण में भी कानूनी पेंच फंस गया। जानकारों का कहना है कि अब इन दांव-पेंच से बाहर आने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में एक से डेढ़ साल का वक्त लगेगा। ऐसे में दोनों चुनाव कोर्ट के फैसले के बाद ही होंगे। हालांकि सरकार भी यही चाहती है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव न हों। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक भले ही चुनाव प्रक्रिया पर काम जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होने में वक्त लगेगा। सरकार 27 प्रतिशत सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व करना चाहती है। ऐसे में आरक्षण की तय सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा के लिए सरकार को कोर्ट में आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। इसके मद्देनजर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का काम शुरू किया है, लेकिन शासन स्तर पर इस प्रक्रिया में तेजी नहीं दिख रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करा सकती है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने में वक्त लगेगा। इसके बाद आरक्षण व अन्य प्रक्रियाओं में ही सालभर का वक्त लगेगा। कमोबेश पंचायत चुनाव को लेकर भी लगभग स्थिति यही है। इससे साफ है कि दोनों चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी स्तर पर फिलहाल यह तय नहीं है कि महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा या फिर पार्षद उन्हें चुनेंगे? पार्टी को पहले लगा कि उसे अप्रत्यक्ष चुनाव तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब भाजपा सत्ता में है। 2019 में, सत्ता में होने के कारण कांग्रेस अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए अधिकांश नगरीय निकायों को कब्जे में लेने के जिन फायदों की आस में थी, वे सारे फायदे अब सत्ता में बैठी भाजपा उठा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम के बजाय रोस्टर के माध्यम से किया था। वह विभिन्न प्रमुख शहरी निकायों में अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए पार्टी के अनुकूल नहीं था। भाजपा सरकार अभी चुनाव कराने से इसलिए हिचक रही है, क्योंकि उसे लगता है कि महंगाई, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमत, चुनाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 14, पृष्ठ-48, 16 से 30 अप्रैल, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अपराध पर लगाम

प्रदेश में गंभीर अपराधों के लिप्त बदमाशों के ठिकानों पर जेसीबी चलवाना हो या अपराधियों के आय के साधनों पर चोट करना। शिवराज सरकार ने अपराध पर लगाम कसने के लिए प्रयासरत सरकार होने का अहसास दिलाने की कोशिश की है। मप्र सरकार को और अधिक सख्त होने की जरूरत है।

● **कीर्ति सोनी,** इंदौर (म.प्र.)

आगे आएं महिलाएं

एक ओर जहां हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं आज भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। महिलाओं को आगे आना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि वे भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं।

● **नीलेश रावत,** भोपाल (म.प्र.)

फैल रहा साइबर क्राइम

प्रदेश सहित देशभर में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2021 में देशभर में दर्ज 50,242 मामलों में कुल 167.03 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। इसमें आम लोगों अधिक शिकार हुए हैं। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सके।

● **ओम यादव,** रीवा (म.प्र.)

सभी के लिए एक ही कानून हो...

देश में एक तरफ लाखों लोग गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ संसद और विधानसभा के माननीय लाखों रुपए की पेंशन पा रहे हैं। देश के माननीयों के लिए भी नियम-कायदे बनाए जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाकर बिल बनाना चाहिए। जिससे करोड़ों रुपए जो माननीयों को पेंशन के नाम पर दिए जा रहे हैं, वे गरीब-मजदूर पर खर्च हो सके। वर्तमान समय में विधायकों से लेकर सांसदों को पेंशन के साथ भत्ता भी मिलता है। जो हर साल बढ़ता ही जाता है। देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं है। सबके लिए एक कानून होना चाहिए।

● **चंदन शर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

कांग्रेस बचाए अपनी साख

आज भाजपा जिस मुकाम पर पहुंच गई है, उसके पीछे पार्टी की सालों की मेहनत है। भाजपा के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की मुख्य वजह बेहतरीन रणनीति, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम, दूसरों की परवाह करने वाला और कार्यकर्ताओं के करीब रहने वाला शीर्ष नेतृत्व और इन सबसे महत्वपूर्ण चुनावी वादों पर अमल करना है। कांग्रेस को भी अपनी साख बचाकर रखनी होगी। अन्यथा कांग्रेस आने वाले समय में गुम हो जाएगी और विपक्ष के रूप में किसी अन्य पार्टी को आगे आना होगा।

● **विक्रांत सिंह,** नई दिल्ली

विदेश में मप्र का गेहूं

मप्र गेहूं के उत्पादन का केंद्र है। इसी बात का फायदा उठाकर प्रदेश सरकार मप्र का गेहूं अब विदेशों में एक्सपोर्ट करने जा रही है, जिससे किसानों को और अधिक राहत मिल सकेगी। इससे सरकार और किसानों दोनों को फायदा होगा। और देशभर में मप्र का गौरव भी बढ़ेगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में गेहूं की भारी कमी पैदा हुई है। इसी कड़ी में विदेशों में गेहूं की मांग बढ़ गई है। मप्र अब विदेशों तक गेहूं पहुंचाएगा।

● **संतोष सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

चिराग तले अंधेरा

चिराग पासवान अपने सियासी कैरियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक के बाद एक झटके लगे हैं रामविलास पासवान के बेटे को। ताजा झटका 12 जनपथ स्थित वह सरकारी बंगला खाली हो जाने से लगा है, जो उनके पिता को 1990 से आवंटित था। चिराग खुद बिहार की जमुई सीट से लोकसभा सांसद हैं। चाहते थे कि पिता के नाम पर आवंटित यह चर्चित बंगला उन्हें मिल जाए। पिता की तो पात्रता थी पर सरकारी नियमों के मुताबिक उनकी नहीं। पासवान तो कई बार न केवल सांसद रहे बल्कि केंद्र में मंत्री भी रहे। जब 2020 में उनका निधन हुआ तब भी वे राज्यसभा के सदस्य ही नहीं केंद्रीय मंत्री भी थे। चिराग पहली बार 2014 में सांसद बने थे। उन्होंने ही अपने पिता को यूपीए छोड़कर राजग में आने की सलाह दी थी। इसके लिए पासवान ने उन्हें श्रेय भी दिया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लोजपा के 6 लोकसभा सदस्य जीते। अगले साल रामविलास बीमार हुए तो उनकी पार्टी में कलह भी बढ़ गई। नीतीश कुमार से उनकी पटी नहीं। नतीजतन 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजग से तो किनारा कर लिया पर यूपीए में भी नहीं गए। अकेले लड़े और भाजपा-जद (एकी) के 20 सीट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भाजपा उम्मीदवारों का तो विरोध किया नहीं पर जद (एकी) के हिस्से की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे।

ममता की महत्वाकांक्षा

गैर भाजपा दलों की एकता की ममता बनर्जी की अपील पर आम आदमी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। ममता केंद्र सरकार के इशारे पर भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को तो मुद्दा बना ही रही हैं, चाहती हैं कि 2024 के चुनाव में सभी दल भाजपा का एकजुट होकर मुकाबला करें। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद ममता ने ऐलान किया था कि वे अब राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगी। त्रिपुरा और गोवा जैसे राज्यों में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी जंग में कूदने के पीछे मकसद ममता की प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा ही मानी जाएगी। वे उप्र विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन के लिए लखनऊ और वाराणसी भी पहुंची थीं। लेकिन अखिलेश यादव का सत्ता हासिल करने का सपना पूरा नहीं हुआ। गनीमत है कि उन्होंने हकीकत को समझते हुए लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। सूबे की सियासत पर फोकस करने की बात कह दी। साफ है कि प्रधानमंत्री पद की हसरत कम से कम 2024 में तो उनकी नहीं है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी छोटी है। नीतीश अब भाजपा के रहमोकरम पर मुख्यमंत्री हैं। साफ है कि गैर कांग्रेसी विपक्ष की तरफ अब मैदान में ममता और अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं। वहीं केजरीवाल का ध्यान अब हिमाचल और गुजरात पर है।

इंतजार-ए-फरमान

कांग्रेस पार्टी के हिमाचल से राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल मार्च-अप्रैल में खत्म हो रहा है। ऐसे में हिमाचल से अब राज्यसभा किसे भेजा जाए यह तय नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनका खेमा और संघ चाहते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे को हिमाचल से राज्यसभा भेजा जाए। जब पांडे हिमाचल में संगठन मंत्री थे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के विरोध के बावजूद इन लोगों को आगे बढ़ाया था। पांडे के एक करीबी बताते हैं कि पांडे जब हिमाचल से चले गए थे तो उन्हें विदाई देने के लिए समारोह में तत्कालीन मंत्रिमंडल के कई मंत्री व नेता शामिल होने जा रहे थे। लेकिन सचिवालय से फोन कर के इन मंत्रियों को वापस बुलाया गया। यह तब की बात है जब धूमल मुख्यमंत्री थे। अब धूमल भी हाशिए पर हैं। लेकिन भाजपाइयों का कहना है कि अब पांडे के रास्ते में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अडंगा डाल रहे हैं। नड्डा और पांडे में भी किसी बात को लेकर छत्तीस का आंकड़ा है। अब सब कुछ पांडे की किस्मत पर है कि क्या होता है। पिछली बार भी राज्यसभा जाने के लिए इंदु गोस्वामी का कहीं कोई नाम नहीं था।

अबके बरस न जाओ

पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली तब से भाजपा और कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को संभालना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, दोनों दलों के आलाकमान भी परेशान हैं कि यह चुनावी साल है और अगर पार्टी के ही नेता खिसक लिए तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। उधर मीडिया है कि रोजाना कोई न कोई शिगूफा छेड़ देता है। पिछले दिनों सुर्खियों में आया कि जयराम सरकार का एक मंत्री और एक विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। मंडी भाजपा के विधायक अनिल शर्मा को लेकर भी अटकलें जारी हैं कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व को सरेआम धमका रहे हैं कि उनकी फलां बात मान लो नहीं तो वे आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। छोटे पदाधिकारी भी हर बात पर पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। दोनों दलों के नेतृत्व के पास एक काम बढ़ गया है कि उसे इन आम आदमी पार्टी में चला जाऊंगा कहने वाले नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की खूब मनुहार करनी पड़ रही है कि अब के बरस न जाओ।

अबूझ पहेली

समय सचमुच ही बलवान होता है। महारानी के बदले तेवर से इसे बखूबी समझ सकते हैं। महारानी यानी राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे। अचानक पार्टी की सियासत में सक्रिय हो गई हैं। अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव जो होंगे। 2018 में विधानसभा चुनाव की हार के बाद विपक्ष का नेता बनने की उनकी हसरत को भाजपा आलाकमान ने पूरा नहीं होने दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद उन्होंने स्वीकार तो जरूर किया पर सक्रिय कभी नहीं हुईं। आलाकमान से नाराजगी का एक कारण सांसद बेटे को 2014 में केंद्र सरकार में मंत्री-पद नहीं मिलना था। वे इस कदर चिढ़ गई थीं कि नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह से पहले दिन विदेश चली गईं। मुख्यमंत्री रहते तो आलाकमान को अपने इशारों पर नाचने को मजबूर कर दिया था। हां, 2018 के बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उनके विरोधी विधायक सतीश पूनिया को आलाकमान ने पार्टी का सूबेदार जो बना दिया।

बाघ के क्षेत्र में बंगला बनाने की तैयारी

राजधानी भोपाल नौकरशाहों के लिए पसंदीदा जगह बनती जा रही है। नौकरशाह मप्र का मूल निवासी हो या किसी अन्य राज्य का, रिटायरमेंट के बाद उसकी कोशिश रहती है कि वह भोपाल की सुरम्य वादियों में अपना आशियाना बनाए। यही कारण है कि राजधानी के रहवासी क्षेत्र में अब खाली भूखंड कम हो गए हैं। ऐसे में रसूखदारों की पसंद वन क्षेत्र होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार बाघों के संरक्षण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के नौकरशाह बाघों के घर में आशियाना बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए कायदे-कानून को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में बाघ क्षेत्र मेडोरो में आशियाना बनाने के लिए आईपीएस अफसरों का एक वर्ग सक्रिय हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि आगामी कुछ वर्षों में रिटायर होने वाले आईपीएस अफसरों ने बाघ के घर में अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन ढूंढने के लिए दलालों को सक्रिय कर दिया है। इस क्षेत्र में आवासीय भूखंड 40 से 50 लाख रुपए के मिल रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि दलालों ने अफसरों को बताया है कि अगर वे लोग एक पुलिस हाउसिंग सोसायटी का गठन कर उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उन्हें आसानी से बाघ के घर के आसपास आशियाने के लिए जमीन मिल जाएगी। बताया जाता है कि दलाल की सलाह पर अफसरों ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि अफसर कब तक सोसायटी का गठन करते हैं।

ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको मैंने ठगा नहीं

उपरोक्त पंक्तियां आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन यह प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री का चरित्र बन गया है। यानी मंत्रीजी अपना हो या बेगाना किसी का भी काम बिना लेनदेन के नहीं करते हैं। आलम यह हो गया है कि मंत्रीजी के विभाग में कोई काम करवाने के लिए लोग पहले ही रेट पूछने लगते हैं। यहां बता दें कि मंत्रीजी जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र के लोगों में हथियार रखने की परंपरा या फिर कहें कि होड़ सी रहती है। इसलिए अक्सर मंत्रीजी के यहां उन लोगों का मजमा लगा रहता है, जिन्हें हथियार के लिए लाइसेंस चाहिए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी ने अपने मातहतों को साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं उन्हीं फाइलों पर साइन करूंगा, जिनके रेट तय हो चुके होंगे। यानी जिनकी रसीद कट चुकी होगी। यह बात जैसे ही मंत्री के मातहतों के माध्यम से बाहर निकली है, लोग इसकी पड़ताल में जुट गए हैं कि आखिर कहां पर रेट तय किए जा रहे हैं और रसीद काटी जा रही है और कौन पैसा ले रहा है। क्योंकि मंत्रीजी हमेशा ईमानदारी का चोला ओढ़े रहते हैं। यहां बता दें कि हथियारों के लाइसेंस में मंत्रीजी का हस्ताक्षर महत्वपूर्ण होता है।

बड़े साहब के नाम पर खेल

नेता और नौकरशाही का ऐसा रसूख होता है कि हर कोई इनका सानिध्य पाने की कोशिश करता है। और मामला तब और रोचक हो जाता है जब दोनों उच्च पदों पर हों। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों ऐसे लोगों की खूब चर्चा हो रही है, जो शासन और प्रशासन के रसूखदार लोगों के नाम पर जमकर कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों में एक व्यवसायी की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल, उक्त व्यवसायी अपने आपको बड़े साहब का करीबी बताकर अपना हित साध रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उक्त व्यवसायी पत्थर का कारोबार करते हैं। कारोबार भी कोई छोटा नहीं है। लेकिन उक्त व्यवसायी का अब अपने कारोबार की बजाय जमीनों के धंधे में मन लग रहा है। इसलिए उन्होंने जमीन खरीदने का धंधा शुरू कर दिया है। इस धंधे में अपनी साख जमाने के लिए उन्होंने बड़े साहब के साथ अपना करीबी रिश्ता बताकर लोगों को चमकाना शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि जब कोई जमीन का बड़ा मामला सामने आता है और पटवारी, अफसर, तहसीलदार, एसडीएम उक्त व्यवसायी को भाव नहीं देती है तो वे साहब के नाम पर उसे चमकाना शुरू कर देते हैं। तरह-तरह के डर दिखाकर वे उक्त जमीन को कम से कम दाम में खरीदने का प्रयास करते हैं। बताया जाता है कि अब तक उक्त पत्थर व्यवसायी ने साहब के नाम पर लोगों को चमकाकर जमीन खरीदने का ऐसा रिकार्ड बना लिया है जिससे वे कईयों की नजरों में चढ़ गए हैं।

किताब में व्यथा और कथा

अक्सर देखा जाता है कि योग्य होने के बाद भी अफसरों को उनकी क्षमता के अनुसार पदस्थापना नहीं मिल पाती है। ऐसे में प्रोटोकॉल के कारण अधिकांश अफसर चुप्पी साध लेते हैं। कुछ अफसर बहक जाते हैं तो उन्हें खरी-खोटी सुननी पड़ती है। लेकिन दो आईएएस अफसरों ने अपनी व्यथा और कथा सुनाने के लिए अपनी लेखनी का सहारा लिया है। एक अफसर ऐसे हैं जिन्हें लगातार तबादलों का दंश झेलना पड़ा है। ऐसे में अपने मन की भड़ास और जज्बात निकालने और दिखाने के लिए उन्होंने कई कविताएं लिख डाली हैं जो अब काव्य संग्रह के रूप में सामने आई हैं। इस किताब में उक्त आईएएस अफसर का दर्द और भेदभाव साफ झलकता है। वहीं दूसरे अफसर ने कोरोनाकाल में रात-दिन काम करके लोगों को न केवल संक्रमण से बचाए रखा, बल्कि महामारी को फैलने से रोकने के इंतजाम भी किए। ऐसे में उक्त अफसर को पुरस्कृत करने की बजाय लूपलाइन में डाल दिया गया है। इसका फायदा उठाते हुए अफसर ने महामारी के दौरान अफसरों के संघर्ष को किताब का रूप दे दिया है, जो काफी चर्चा में है।

...तो दो-दो बुलडोजर दे दें

देश का हृदय प्रदेश इन दिनों बुलडोजर प्रदेश बन गया है। बात-बात में सरकारी बुलडोजर घरों पर दौड़ पड़ता है। शासन और प्रशासन बिना देर किए बुलडोजर चलाने में हिचक नहीं कर रहा है। आलम यह है कि अब तो हर सभा और बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपराधियों और माफिया पर लगातार बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार के इन निर्देशों से अफसर पसोपेश में हैं कि हम सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करें या बुलडोजर चलवाएं। एक जिले के एक बड़े साहब का कहना है कि सरकार बुलडोजर चलाने के आदेश-निर्देश के साथ हर जिले को दो-दो बुलडोजर भी आवंटित करा दे। ताकि अफसरों को किराए पर लेकर बुलडोजर न चलाना पड़े। वहीं एक अन्य अफसर कहते हैं कि प्रदेश में जिस तरह ताबड़तोड़ बुलडोजर चलवाया जा रहा है, उससे अदालत कभी भी हमें कटघरे में खड़ा करवा सकती है। लेकिन करें भी तो क्या हमारी स्थिति तो इधर कुआं, उधर खाई वाली हो गई है। मरता क्या न करता की तर्ज पर हम भी बुलडोजर चलवाने को मजबूर हैं।

पाकिस्तान आने वाले दिनों में भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करेगा। इमरान के शासनकाल में पड़ोसी देशों से जिस तरह संबंध खराब हुए हैं, उसे अब सुधारा जाएगा। लेकिन भारत के साथ कश्मीर पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा।

● **शाहबाज शरीफ**

कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि कोरोना के नए वैरिएंट से भारत पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार महामारी से निपटने के लगातार प्रयास कर रही है। जो लोग महामारी का टीका लेने से वंचित रह गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द टीका लगवा लेना चाहिए, ताकि महामारी से बच सकें।

● **मनसुख मंडाविया**

2011 में भारत ने जब वर्ल्डकप जीता तो कहा गया कि महेंद्र सिंह धोनी ने देश को यह कप दिलाया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि टीम में शामिल 10 अन्य खिलाड़ी क्या कर रहे थे। जीत माही ने दिलाई तो सचिन पाजी और गंभीर क्या कर रहे थे, बाकी खिलाड़ी क्या लस्सी पीने गए थे। इस जीत में सभी खिलाड़ियों का योगदान बराबर का था।

● **हरभजन सिंह**

पुतिन हमारे देश के दक्षिणी हिस्से को लेना चाहते हैं और क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देना चाहते हैं। मैं इसे मंजूर नहीं करूंगा। मुझ पर दबाव बनाने के लिए रूस लगातार नरसंहार कर रहा है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने देश का कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं हूं।

● **वोलोदिमिर जेलेंस्की**

फिल्म दसवीं में अपने किरदार के लिए मुझे 15 किलो वजन बढ़ाना पड़ा। यह बढ़ा हुआ वजन मेंटली और फिजीकली बहुत दुखदायक था। इसी से समझा जा सकता है कि एक आर्टिस्ट को किन-किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। जब मेरा वजन बढ़ा था, तब ऐसा लग रहा था कि मैं कहां फंस गई हूं। मुझे सोने में तकलीफ होती थी, मेरे घुटने और ज्वाइंट्स दर्द होते थे, खुद को पॉजिटिव रखती थी यह सोचकर कि ये दिन भी निकल जाएगा। जब शूटिंग खत्म हुई, तब मैंने वजन घटाना शुरू किया। एक रोल के लिए इतना कुछ किया जाता है यह किसी बड़े त्याग से कम नहीं है।

● **निमृत कौर**

वाक्युद्ध

कांग्रेस और दिग्विजय सिंह प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की पोल खोल दी है। ये कौनसी खाल ओढ़े रहते हैं, सबने देख और समझ लिया है। अब इनके बहाने काम नहीं आने वाले हैं। जनता ही इनको जवाब देगी।

● **नरोत्तम मिश्रा**

सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से अगर मेरे खिलाफ एक नहीं एक लाख भी एफआईआर दर्ज हो जाए तो मुझे अफसोस नहीं है। जो मेरा ट्वीट था उसमें भी मैंने प्रश्न ही पूछा था, वो तस्वीर खरगोन की नहीं थी, इसलिए मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। भाजपा मेरे खिलाफ नहीं पूरे देश के खिलाफ एजेंडा चला रही है।

● **दिग्विजय सिंह**

मंत्री के ओएसडी की भर्राशाही

सहकारिता विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर पदस्थ अरविंद सिंह सेंगर जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री के ओएसडी हैं, उनका विवादों और घपले-घोटालों से पुराना नाता है। अभी हाल ही में उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई है और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो मामला सबसे अधिक चर्चा में है, वह है संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी कर स्वयं एवं परिवारजनों तथा अन्य को आर्थिक लाभ पहुंचाने का। अरविंद सिंह सेंगर ने सहकारिता के नियमों को दरकिनार कर किस तरह अपनों को उपकृत किया है, इसका उदाहरण भोपाल की दानिश गृह निर्माण संस्था में देखने को मिलता है।

सहकारिता विधान के प्रावधानों के अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को गृह निर्माण समिति से भूखंड की पात्रता नहीं है, लेकिन अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अरविंद सिंह सेंगर ने अपने बेटे लोकेंद्र सिंह सेंगर को दानिश गृह निर्माण संस्था भोपाल की सदस्यता दिलाई तथा दिनांक 30/03/2019 को गृह निर्माण संस्था द्वारा इन्हें भूखंड क्रमांक डीएचवी 3/17 की रजिस्ट्री कराई गई। वहीं दिनांक 30/3/2019 को ही अनुश्री सिंह पत्नी लोकेंद्र सिंह द्वारा अपने पति के नाम का उल्लेख ना करते हुए पिता के नाम शपथ पत्र देते हुए लोकेंद्र सिंह सेंगर के आवंटित भूखंड से लगे हुए दूसरे भूखंड की रजिस्ट्री कराई है। जबकि इनका लोकेंद्र सिंह के साथ विवाह हो चुका है, जिसमें नगर निगम द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 907/बीपीएल/2014 दिनांक 30/05/2014 को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में निवास का पता 115/40 शिवाजी नगर भोपाल जो की अरविंद सिंह सेंगर के शासकीय आवास का पता दिया गया है। वहीं जन औषधि संघ का सदस्य बनने के लिए हीरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित ग्वालियर अनुश्री सिंह द्वारा अपना पता एफ-10 सिटी सेंटर साइट नंबर 1 ग्वालियर का दिया गया। भूखंड लेते समय दानिश गृह निर्माण संस्था में अपने वैवाहिक होने की जानकारी छुपाई और निवास का पता डी1/202 फॉर्च्यून डिवाइन सिटी मिसरोद भोपाल बताया गया। इस प्रकार अनुश्री सिंह द्वारा जन औषधि संघ में फर्जी जानकारी देकर उपाध्यक्ष पद अरविंद सिंह सेंगर की पुत्रवधू होने के कारण अवैध रूप से संवैधानिक पद प्राप्त किया और दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था में झूठी जानकारी का शपथ पत्र देकर भूखंड प्राप्त किया।

दानिश गृह निर्माण संस्था के आवंटित दोनों भूखंडों पर एक ही भवन का निर्माण कराया जा रहा है जबकि दोनों के निर्माण की अलग-अलग अनुज्ञा अनुमति ली गई है नगर एवं ग्राम निवेश की धारा 30ए में रहवासी भूखंडों से संयुक्तिकरण करना प्रतिबंधित है। आरोप है कि गृह निर्माण संस्था में पति-पत्नी दोनों भूखंडों को लेकर अरविंद सिंह सेंगर ने परिवारजनों को एवं स्वयं करोड़ों रुपए का नियम विरुद्ध आर्थिक लाभ अर्जित किया है।

दानिश गृह निर्माण संस्था में पति-पत्नी दोनों के नाम से आवंटित भूखंडों की शिकायत भी की गई परंतु गृह निर्माण शाखा के प्रभारी स्वयं अरविंद सिंह सेंगर हैं। लोकेंद्र सिंह और उनकी पत्नी अनुश्री सिंह भी अरविंद सिंह सेंगर के घर में ही रहती हैं। अरविंद सेंगर मुख्यालय में गृह निर्माण शाखा के प्रभारी हैं। गृह निर्माण समितियों पर उनका नियंत्रण है। उनके प्रभाव एवं दबाव में सभी गृह निर्माण समितियों ने संगमत होकर पति-पत्नी के भूखंड की रजिस्ट्री कराई। अत: इस शिकायत की कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। आयुक्त सहकारिता द्वारा आज तक इस पर कोई कार्यवाही भी नहीं की गई, क्योंकि वे खुद सेंगर के नियंत्रण में है। यही नहीं अरविंद सिंह सेंगर द्वारा जन औषधि संघ के अध्यक्ष पद के लिए जागृत प्रभात मिश्रा जो मूलत: दिल्ली निवासी हैं, को फर्जी किरायानामा से निवास का पता होशंगाबाद बताकर उन्हें शिव शक्ति प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति होशंगाबाद में सदस्य प्रतिनिधि बनाकर सेंगर द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जनऔषधि संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इन मामलों को लेकर लोकायुक्त में शिकायत की गई है। इस संदर्भ में जब अरविंद सिंह सेंगर मोबाइल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई घपले-घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि साहब इसके पूर्व भी सहकारिता मंत्री के ओएसडी रह चुके हैं।

● **राकेश ग्रोवर**

सेंगर के खिलाफ आरोपों की भरमार

आरोप है कि अरविंद सिंह सेंगर संयुक्त आयुक्त सहकारिता के पद पर कार्यालय आयुक्त सहकारिता में विगत 5 वर्षों से पदस्थ होकर सखाकक्ष, और गृह निर्माण कक्ष के प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। विभाग के अधिकारियों की वरदहस्त होने के कारण मप्र राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक तथा संभागीय संयुक्त आयुक्त ग्वालियर और चंबल संभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सेंगर के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 213/2012 भारतीय दंड संहिता की धारा-13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा 109, 120बी, 201, 420, 467, 468, 471 धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत है। सेंगर के विरुद्ध दिनांक 4/11/2011 को मप्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसका प्रकरण क्रमांक-32/2011 है। वहीं आर्थिक अपराध अनुसंधान ग्वालियर में भी इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है, जिसका अपराध क्रमांक 1/2010 धारा 406, 409, 420, 120बी 467, 468 471, 13डी में बरसों से विचाराधीन है। इनके राजनीतिक प्रभाव के कारण विवेचना पूर्ण नहीं की जा रही। आर्थिक अपराध अनुसंधान द्वारा अपराध क्रमांक 271/2010 में अरविंद सिंह सेंगर के विरुद्ध प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई थी। इस प्रकरण में 50 करोड़ रुपए का आर्थिक घोटाला हुआ था जिसमें लगभग 10 आरोपियों को सजा हो चुकी है, परंतु इनकी राजनीतिक पहुंच के कारण इस प्रकरण में विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। सहकारिता विभाग के स्तर पर स्पीड स्टार एजेंसी से 6500 करोड़ रुपए का ऋण लेने संबंध में विभागीय जांच का आरोप पत्र जारी करना वर्षों से लंबित है।

मप्र में भाजपा और कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अब रिपोर्ट कार्ड से मिशन 2023 फतह होगा। सरकार और विपक्ष का अपना-अपना चुनावी रिपोर्ट कार्ड होगी। भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। दोनों ही पार्टी एक-दूसरे की नाकामियों और खामियों को दिखाएगी। उधर, भाजपा की रणनीति यह है कि इस बार आधा सैकड़ा से अधिक सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया जाए। यानी आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकांश उम्रदराज नेता चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे।

नए चेहरों पर दांव

मप्र में सत्ता और संगठन में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा सूत्रों की मानें तो पार्टी के शीर्ष नेताओं में कई दौर की बात हो चुकी है। सरकार में जहां कुछ नए मंत्री बनाए जाएंगे, वहीं संगठन में भी कुछ बदलाव होगा। इन बदलावों के साथ ही पार्टी नेताओं को संदेश देना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा अभी से हर स्तर पर काम जोर-शोर से करने लगी है। इसके लिए पार्टी ने एक गाइडलाइन लगभग तैयार कर ली है। अगर इस पर पूरी तरह से पालन हुआ तो कोई बड़ी बात नही हैं कि मौजूदा पार्टी के आधा सैकड़ा विधायकों व बड़े नेताओं को टिकट ही नहीं मिले। इनमें पार्टी के वे चेहरे भी शामिल रहेंगे, जो बेहद बड़े माने जाते हैं, लेकिन या तो बीता चुनाव हार चुके हैं या फिर उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो पार्टी द्वारा तय की गई आयु सीमा से अधिक है।

इसके अलावा पार्टी द्वारा अभी से हर विधानसभा सीट का अपने स्तर पर आंकलन कराया जा रहा है। इस आंकलन में जो विधायक खरे नहीं उतरेंगे उनके भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। पार्टी ने इसके लिए संगठन स्तर पर नए व प्रभावी चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। यह वे चेहरे होंगे जो न केवल साफ-सुथरी छवि के होंगे बल्कि मतदाताओं के बीच भी अच्छी पकड़ रखते होंगे। इस बार पार्टी अपने जिलाध्यक्षों को भी चुनाव में उम्मीदवार बनाने से परहेज करने जा रही है। इसके पीछे की वजह है चुनाव के समय जिलाध्यक्ष के प्रत्याशी होने की वजह से वह सिर्फ एक सीट पर ही पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है जिससे जिले की अन्य सीटों पर अव्यवस्था की स्थिति बनती है। यही नहीं इस बार भाजपा संगठन कई अन्य तरह के भी कदम उठा रही है, जिसमें निगम मंडल की कमान संभालने वाले नेताओं को भी अगर चुनाव लड़ना है तो उन्हें पहले पदों से इस्तीफा देना होगा। भाजपा में इन दिनों वैसे भी पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से ही संगठन में अधिकांश पदों पर युवा चेहरों को ही जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल भाजपा में यह पूरी कवायद दूसरी मजबूत पंक्ति तैयार करने के लिए की जा रही है।

जानकारों की माने तो मिशन 2023 के लिए जो क्राइटेरिया तय किया जा रहा है, उसमें पार्टी के ऐसे विधायकों को अगली बार टिकट नहीं देगी, जो न केवल उम्रदराज हो चुके हैं, बल्कि उनकी पकड़ भी अब मतदाताओं पर कमजोर होती जा रही है। खास बात यह है कि इस बार उन विधायकों के टिकट पर भी खतरा बना हुआ है, जो बेहद कम मतों से जैसे-तैसे जीत हासिल कर सके हैं। यही नहीं पार्टी के उन नेताओं के टिकट पर भी इस बार संकट खड़ा हो गया है जो मंत्री रहते पिछला चुनाव हार चुके हैं। ऐसे नामों में जयंत मलैया, ओम प्रकाश धुर्वे, रुस्तम सिंह, अर्चना चिटनिस, उमाशंकर गुप्ता, अंतर सिंह आर्य, जयभान सिंह पवैया, नारायण सिंह कुशवाहा, दीपक जोशी, लाल सिंह आर्य, शरद जैन, ललिता यादव और बालकृष्ण पाटीदार जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें से किसी को टिकट मिलेगा भी तो अपवाद स्वरूप। वैसे भी इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं, जिन्हें श्रीमंत समर्थकों की वजह से टिकट मिलना बेहद मुश्किल है। कहा जा रहा है कि पार्टी इन नेताओं के अनुभव का लाभ लेगी। यह लाभ किस तरह से लिया

लगातार की जा रही है कामकाज की समीक्षा

दरअसल जिस तरह से प्रदेश में बीते कुछ माह में लगातार मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठकें संगठन के अलावा मुख्यमंत्री द्वारा ली गई हैं, उससे भी मंत्रिमंडल विस्तार को बल मिला है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों के साथ पचमढ़ी में बैठक की है। दो दिन तक चली इस बैठक को भले ही चिंतन शिविर का नाम दिया था और विभागीय कामकाज के लिए योजनाओं पर मंथन करने का दावा किया गया था, लेकिन वास्तव में इस बैठक में कामकाज की समीक्षा भी की गई। इसके पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंत्रियों के साथ अलग से बैठक कर चुके हैं। उनके पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्हें पार्टी की अपेक्षाओं के बारे में बताया था। यही नहीं जनवरी में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 3 से लेकर 10 जनवरी तक विभागों की समीक्षा की गई थी। माना जा रहा है कि लगातार की कई विभागों के कामकाज की समीक्षा में कई विभागों के कामकाज से संगठन व सरकार खुश नहीं है। इसकी वजह से संबधित विभागों के मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होना तय माना जा रहा है। कुछ मंत्री तो ऐसे हैं, जो अब तक अपने विभागों में पकड़ ही नहीं बना पाए हैं। इसकी वजह से सरकार की जनहितैषी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। माना जा रहा है कि ऐसे मंत्रियों से महत्वपूर्ण विभाग लेकर उनका कद कम किया जाएगा। उनके विभाग अन्य मंत्रियों को दिए जाएंगे।

जाएगा यह अभी तय नहीं है। बताया जा रहा है कि परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए प्रदेश संगठन जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों को टिकट देने का मामला केंद्रीय संगठन पर छोड़ेगा।

पार्टी इस बार अभी से उन सीटों पर खास फोकस करने जा रही है, जिन पर कांग्रेस के विधायक हैं। यही नहीं बीते चुनाव में जिन तीन जिलों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था, उन सीटों पर भी अभी से पार्टी चुनावी तैयारियों में लगने की योजना पर काम कर रही है। यह बात अलग है कि इन तीनों ही सीटों पर श्रीमंत के आने के बाद उनके समर्थक विधायक जीतकर भाजपा के लिए राह आसान बना चुके हैं। इनमें खरगौन, मुरैना और भिंड जिला शामिल है।

भाजपा मप्र में भी हाल ही में संपन्न हुए उप्र की तर्ज पर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। जिसमें एक-एक विधानसभा क्षेत्र का आंकलन किया जाएगा। वहां यदि पार्टी का विधायक है, तो उसकी क्षेत्र की जनता से जुड़ाव, लोकप्रियता, भ्रमण और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यक्तिगत भागीदारी का भी पता लगाया जाएगा। सूत्रों की मानें तो पार्टी संगठन इसी साल जिला संगठन से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए पांच-पांच नामों का पैनल मांगेगा। इनमें मौजूदा जहां विधायक हैं, वहां उनका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। युवराज महाआर्यमन सिंधिया **इस वर्ष से अपने पिता के साथ** कई कार्यक्रमों में मंच भी साझा करने लगे हैं, हालांकि उन्हें राजनीति का ककहरा विरासत में मिला है। उनकी परदादी स्व. राजमाता विजयाराजे सिंधिया से लेकर दादा स्व. माधवराव सिंधिया भी राजनीति में थे, वहीं उनके पिता भी राजनीति में ऊंचाईयों पर हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी के जनाधार के बावजूद उमाशंकर गुप्ता, रुस्तम सिंह, हिम्मत कोठारी **जैसे 70 से ज्यादा** उम्र वाले नेताओं को नकार दिया गया। हालांकि इनकी हार की अन्य वजह भी रही हैं। अब ये नेता फिर अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन से निर्देश मिलने पर उम्रदराज नेताओं को चुनाव के लिए टिकट देने से इनकार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है।

उधर बीते साल ही भाजपा प्रदेश संगठन ने पहले से चली आ रही संभागीय संगठन मंत्री की व्यवस्था के सभी पद समाप्त कर दिए थे, जिसके बाद इन पदों पर काम कर रहे लोगों को निगम मंडलों की कमान देकर उन्हें सत्ता में भागीदारी प्रदान की जा चुकी है। इसके बाद तय किया गया था कि प्रदेश को तीन अलग-अलग प्रांतों में बांटकर उनकी जिम्मेदारी तीन सह संगठन मंत्रियों को प्रदान कर दी जाए। इन पदों पर नियुक्तियों के लिए तभी से इंतजार किया जा रहा है। वहीं मंत्रिमंडल में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। दरअसल अभी शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के चार पद रिक्त चल रहे हैं। इन चार पदों के लिए कई वरिष्ठ भाजपा विधायकों की दावेदारी बनी हुई है। इनमें कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो पहले भी लगातार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन श्रीमंत समर्थकों की वजह से उन्हें इस बार मौका नहीं मिल सका है। माना जा रहा है कि विस्तार में दो से लेकर तीन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसके लिए जिन नामों की चर्चा बनी हुई हैं उनमें मुख्य तौर पर विंध्य क्षेत्र के राजेंद्र शुक्ला, केदार शुक्ला तो वहीं महाकौशल से अजय विश्नोई, संजय पाठक, जालम सिंह पटेल, मध्य क्षेत्र से रामपाल सिंह और निमाड़ मालवा से रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं। यह बात अलग है कि जिस तरह से भाजपा सरकार और उसके संगठन का प्रदेश में इन दिनों अनुसूचित जाति व जनजाति पर फोकस बना हुआ है, उससे यह भी अटकलें लगाई जा रहीं हैं कि इस बार इन दोनों वर्ग के नेताओं को ही शपथ दिलाने में प्राथमिकता मिलनी तय है।

उधर, मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा के लिए ग्वालियर-चंबल अंचल टेंशन बना हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 34 में से 26 सीटें जीत ले गई थी। हालांकि उसके स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा में हैं। लेकिन इस इलाके के जातीय समीकरण भाजपा को बेचैन किए हुए हैं। मप्र के लिहाज से ग्वालियर-चंबल अंचल की अहमियत इस लिहाज से समझी जा सकती है कि 2018 के चुनाव में ग्वालियर-चंबल से कांग्रेस के खाते में गई 26 सीटों ने प्रदेश का सियासी समीकरण बदल दिया और सत्ता भाजपा के हाथ से निकलकर कांग्रेस के पास चली गई। कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई थी। हालांकि कांग्रेस नेताओं का पाला बदलने के बाद स्थिति बदल गई है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में यही स्थिति बनी रहेगी इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।

● **कुमार राजेन्द्र**

70+ नेताओं को दिया जाएगा आराम

नर्मदापुरम के विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा चार बार से विधायक हैं। उन्होंने पहला चुनाव 1993 में लड़ा था। इसके बाद 1998 में भी विधायक रहे। 2003 के चुनाव में उनका टिकट काटा गया तो उनके भाई पं. गिरिजाशंकर शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया। वे दो बार विधायक रहे। 2013 में डॉ. शर्मा को फिर पार्टी ने टिकट दिया और वे जीतकर विधानसभा के स्पीकर भी रहे। 2018 में उन्हें एक बार फिर विधायक बनने का मौका मिला। डॉ. शर्मा बंद कमरे में चुनाव नहीं लड़ने की बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बार और चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। इन नेताओं की खास बात यह है कि ये अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। अब पार्टी के सामने समस्या यह है कि नए कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए इन नेताओं को कैसे इनकार किया जाए। आने वाले चुनावों में भाजपा के एक दर्जन विधायक 70 की उम्र पार कर चुके होंगे। पार्टी के लगभग 13 विधायक अगले साल होने वाले चुनाव के दौरान 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे। अगर पार्टी के नए विचाराधीन फॉर्मूला पर अमल होता है तो 70 साल से अधिक की उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने के क्राइटेरिया में कई नेताओं को माननीय बनने का मोह त्यागना पड़ेगा।

विदेशों में बिकेगा मप्र का गेहूं

गेहूं के विदेश में निर्यात के बाद इतिहास रचेगा प्रदेश

मप्र एक प्रमुख निर्यातक राज्य बनता जा रहा है। प्रदेश से अनाज सहित कई आवश्यक वस्तुएं विदेशों में निर्यात की जाती हैं। इसका परिणाम यह है कि पिछले 6 साल में प्रदेश की निर्यात दर तेजी से आगे बढ़ी हैं। आज मप्र की निर्यात दर में राष्ट्रीय औसत दर से भी अधिक वृद्धि हुई है। माना जा रहा है कि अब गेहूं के विदेश में निर्यात के बाद प्रदेश निर्यात का इतिहास रच देगा। गौरतलब है कि प्रदेश गेहूं के विदेश में निर्यात के लिए अब कदम उठा रहा है। विश्व के कई देश मप्र के गेहूं को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अभी तक की स्थिति देखें तो बीते 6 सालों में भी निर्यात की रफ्तार सरपट रही है। बीते 6 सालों में मप्र की निर्यात दर में औसत 9.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत दर वृद्धि से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय निर्यात दर वृद्धि महज 0.6 फीसदी है। इससे आगे चलकर मप्र के निर्यात के मामले में और बेहतर होने की संभावना बनती है। निर्यात के मामले में देश के 24 प्रमुख औद्योगिक सेक्टर में 5 मप्र के हिस्से में आते हैं। मप्र में इन 5 क्षेत्रों में बेहतर स्थिति है। इस कारण प्रदेश औद्योगिक क्लस्टर के तहत निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें गैरधातु खनिज, कपड़े और खाद्य उत्पाद शामिल हैं। प्रदेश से विदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए एक जिला-एक उत्पाद योजना को लेकर भी काम हो रहा है।

आपदा को अवसर बनाकर मप्र आज देश ही नहीं विदेशों में भी मिसाल बना हुआ है। यही कारण है कि आज मप्र देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य बना हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के इस दौर में पूरे विश्व में गेहूं की कमी हो गई है। ऐसे में मप्र बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। कई देश मप्र से गेहूं खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक देश इजिप्ट ने मप्र का गेहूं खरीदने में रुचि दिखाई है। मालवा सहित प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पैदा होने वाले गेहूं की इजिप्ट (मिस्र) में निर्यात होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसी सिलसिले में इजिप्ट सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल गत दिनों इंदौर आया और मालवी और शरबती गेहूं की खूबियां जानीं। दल में आए अधिकारियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र पहुंचकर गेहूं की अलग-अलग किस्में देखीं। साथ ही वेयर हाउस पहुंचकर गेहूं के नमूने देखे। इजिप्ट के दल ने शहर के एक निजी होटल में जिला प्रशासन, मंडी बोर्ड, कृषि विभाग और गेहूं निर्यातक व्यापारियों से चर्चा की।

दरअसल, यूक्रेन में युद्ध के कारण भारत से गेहूं निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इसलिए यूक्रेन पर निर्भर रहने वाले इजिप्ट जैसे देशों ने गेहूं आयात करने के लिए भारत का रुख किया है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार और इजिप्ट सरकार के बीच गेहूं के निर्यात को लेकर सहमति बनी है। दरअसल मप्र का शरबती और मालवी गेहूं गुणवत्ता और पोषक तत्वों के मामले में देशभर में मशहूर है। इसलिए केंद्र सरकार ने इजिप्ट के दल को सबसे पहले मप्र भेजा। मप्र के गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संभावना को हाथोंहाथ लिया और इजिप्ट के दल को मप्र में आमंत्रित किया।

इंदौर आए प्रतिनिधिमंडल में इजिप्ट सरकार के कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी इस्लाम फरहत अब्देल अजीज, डॉ. सलेह अब्देल सत्तार बहिग अहमद, इंजीनियर अहमद राबिया अब्दुल्ला अब्देल कादर, भारत सरकार की संस्था एपीडा के क्षेत्रीय प्रभारी डॉ. सीबी सिंह और पादप सुरक्षा सलाहकार डॉ. रविप्रकाश और डॉ. संजय आर्य शामिल थे। कलेक्टर मनीष सिंह, मंडी बोर्ड के अतिरिक्त संचालक डीके नागेंद्र, मंडी के भारसाधक अधिकारी राजेश राठौर, संयुक्त संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठ, कृषि उपसंचालक एसएस राजपूत ने प्रतिनिधिमंडल के साथ गेहूं निर्यातकों की बैठक कराई। गेहूं अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉ. केसी शर्मा ने मप्र में पैदा होने वाली शरबती और मालवी (ड्यूरम) गेहूं की अलग-अलग किस्मों की खूबियों का प्रस्तुतिकरण दिया। साथ ही बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के गेहूं में करनाल बंट नाम की बीमारी आती है, लेकिन मप्र का गेहूं इस बीमारी से मुक्त है। वहीं जिम्बाब्वे ने भी मप्र का गेहूं खरीदने में रूचि दिखाई है। उधर, इजिप्ट के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख इस्लाम फरहत ने बताया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए हालात के बाद हम भारत से गेहूं आयात की संभावनाएं तलाशने के लिए आए हैं। हमारी यह यात्रा पहले भी प्रस्तावित थी लेकिन कोरोना के कारण यह स्थगित हो गई थी। भारत इस समय इजिप्ट के निर्यातक देशों की अधिमान्य सूची में शामिल नहीं है। उम्मीद है कि इस यात्रा के बाद हम भारत को निर्यातक देशों की सूची में जोड़ सकते हैं।

दरअसल, भारत सरकार ने दूतावासों से कहा है कि वे स्वयं राज्यों से बात करें और राज्यों को कहा है कि वे दूतावासों से बात करके आयात-निर्यात करें। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार मप्र ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तुर्की, वियतनाम, नाइजीरिया, थाइलैंड, अलजीरिया, सुडान जैसे देशों में मप्र गेहूं निर्यात करने की संभावनाएं तलाश रहा है। वहीं पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में भी निर्यात करने का अच्छा समय है। इससे जहां प्रदेश के किसानों को उनके उत्पाद का सही भाव मिल जाएगा, वहीं व्यापारियों, प्रदेश और देश का भी फायदा होगा। प्रदेश में सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए 11 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, वहीं मंडी ने भी 11 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत निर्यातकों को सुविधाएं दी जाएंगी।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रोजगार की बहार

मप्र को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। भोपाल और इंदौर के बीच बहुत जल्द ही देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तकनीकी टीम को जगह दिखा दी गई है। यह जमीन सोनकच्छ, चापड़ा, हाटपिपल्या के बीच है। यहां 30 हजार एकड़ क्षेत्र में मेगा इंडस्ट्रियल रिजन भी तैयार किया जाएगा। इस जगह एयरपोर्ट बनने की वजह से कई युवाओं को रोजगार उपलब्ध होंगे। अभी तक यहां पर कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जिन्हें इस जगह रोजगार मिल जाएंगे। भोपाल और इंदौर के बीच बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने का काम मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की वजह से यहां कई शहरों से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। इसके साथ ही हाईस्पीड कनेक्टिविटी होगी और जिलों से सीधा संपर्क भी जुड़ जाएगा। इस क्षेत्र को रेलवे से भी जोड़ने की योजना है। यहां एक रेलवे स्टेशन भी बनाया जा सकता है।

केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र में निवेश को लेकर यह कदम उठाए हैं जिसके बाद अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एयरपोर्ट को आष्टा से सोनकच्छ के बीच बनाया जाएगा। इसमें कई रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। वहीं जिलों से संपर्क भी जुड़ेगा। आने-जाने वाले को भी इससे कई फायदे होंगे। इसके साथ दूसरे जिलों से यहां निवेश करने में भी फायदा होगा। दरअसल इंदौर-भोपाल के बीच बनने वाले इस एयरपोर्ट से कई जिलों को फायदा होने के साथ ही शाजापुर से देवास, एबी रोड, इंदौर-भोपाल रोड के साथ ही नरसिंहगढ़ को इन जिलों से जोड़ने की वजह से कई तरह के फायदे भी मिलेंगे। इस एयरपोर्ट को जोड़ने की वजह से देश-विदेश से आने-जाने वालों को काफी फायदा भी होगा। इसके साथ ही निवेश करने में भी आसानी रहेगी।

आष्टा और सोनकच्छ के बीच बनने वाले देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बन जाने से निवेश के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही इसमें करीब दो लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली चीजें रियायत दरों में मिल जाएंगी। आष्टा में बड़ा औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो जाता है, तो सरकार का पूरे इंदौर-भोपाल कॉरीडोर को औद्योगिक कॉरीडोर बनाने का प्रोजेक्ट भी सफल हो जाएगा। इंदौर-भोपाल रूट प्रदेश का सबसे कमर्शियल और बेहतर रूट है। अभी इंदौर और उसके आसपास ही सबसे ज्यादा विकास हुआ है। यह विकास देवास तक आ चुका है, लेकिन इसके बाद सोनकच्छ से विकास नहीं दिखता। वहीं भोपाल व आसपास भी विकास है, लेकिन सीहोर के बाद गेप है। आष्टा में बड़ा क्लस्टर विकसित हो जाता है, तो यह दोनों ओर से बेहतर तरीके से जुड़ा होगा। भोपाल-इंदौर एयरपोर्ट भी होने से कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी। इससे आष्टा से इंदौर-भोपाल दोनों ओर विकास हो पाएगा। इसलिए आष्टा को बेहतर पाइंट माना जा रहा है।

उधर, पीथमपुर, रतलाम के बाद अब देवास प्रदेश का तीसरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एरिया घोषित होगा। इसके लिए प्रारंभिक रूप से देवास के आसपास 12 हजार एकड़ जमीन ली जा रही है। इसकी मंजूरी का प्रस्ताव एमपीआईडीसी ने सरकार को भेज दिया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही दावे-आपत्ति बुलाए जाएंगे। इंडस्ट्री को जमीन देने के साथ ही पीथमपुर में जिस तरह से सेक्टर डेवलपमेंट हुए हैं, उसी तरह से इसे भी विकसित किया जाएगा। इससे हजारों नौकरियों के साथ करोड़ों का निवेश आएगा। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के रूप में इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया 400 वर्ग किमी क्षेत्र का हो जाएगा। पीथमपुर, सांवेर रोड, पालदा, बेटमा के साथ अब देवास की सीमा भी औद्योगिक दृष्टि से इंदौर को उन्नत करेगी। इंदौर-भोपाल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की दिशा में यह बड़ा कदम होगा।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए मप्र से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरगन भी जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे दक्षिण भारत से कुछ इंडस्ट्री लाने का निवेदन किया है। जिस पर केंद्रीय मंत्री कार्य में जुट गए हैं। इससे मप्र औद्योगिक हब बनने की ओर अग्रसर है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

प्रदेश का पहला ऑटो एक्सपो 28 से 30 अप्रैल तक

देश और दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब बन चुके इंदौर के पीथमपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इंदौर के सुपर कॉरीडोर में आयोजित ऑटो एक्सपो में देश-विदेश की 900 कंपनियां पहली बार अपने-अपने वाहनों का डेमो देंगी। 28 से 30 अप्रैल तक होने जा रहे इस तीन दिवसीय आयोजन के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंदौर स्थित पीथमपुर देश का प्रमुख ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहां इस सेक्टर के कई बड़े ब्रांड मौजूद हैं। अब जबकि यहां ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कई कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं तो राज्य सरकार की कोशिश है कि दुनियाभर के कई बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड को इस आयोजन का हिस्सा बनाया जाए। लिहाजा मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमपीआईडीसी) के इस भव्य आयोजन में मर्सिडीज, मारुति सहित कई अन्य कार कंपनियां भागीदारी करेंगे। इसके अलावा इन कंपनियों के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और मैनेजमेंट से जुड़े लोग इस आयोजन में शामिल होंगे।

मप्र में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की नीतियों का असर अब पूरी तरह दिखने लगा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास, योजनाओं-परियोजनाओं के क्रियान्वयन और रोजगार सम्मेलनों के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। इसका असर यह पड़ा है कि मप्र में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। मप्र की बेरोजगारी दर 1.4 प्रतिशत हो गई है। देश में इससे कम केवल छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मप्र में सरकार ने इस साल अब तक 13,65,000 युवाओं को रोजगार दिया है। जनवरी में 5,26000 व 16 फरवरी को 5,04000 लोगों को रोजगार मिला है। 30 मार्च को यानी 3,35000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के ताजा आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की स्थिति देश में सबसे बेहतर बताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही। वहीं मप्र दूसरे स्थान पर है। मप्र की बेरोजगारी दर 1.4 प्रतिशत हो गई है। मप्र सरकार का दावा है कि नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर राज्य में उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 3 अप्रैल 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही।

प्रदेश में अधिक औद्योगिक निवेश लाकर नियोजन के अवसरों में वृद्धि की जा रही है। आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण एवं अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। नए क्षेत्रों जैसे-वन, पर्यटन, श्रम, खनिज, सहकारिता आदि में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। रोजगार के लिए हमारी 8 सूत्रीय रणनीति है। नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कर कक्षा 6वीं से ही रोजगार मूलक शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा और उद्योग जगत की मांग में गैप को भरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। रोजगार चाहने वालों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए ऑनलाईन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा। जिला एवं विकासखंड स्तर पर रोजगार मेलों का नियमित आयोजन होगा। सरकारी भर्तियों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।

कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से मप्र की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी मप्र में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नए आंकड़ों के मुताबिक मप्र 1.4 प्रतिशत के साथ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत है।

मप्र आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहले पर अब युवाओं को मिशन मोड़ में रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए विभागों ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की मंशानुसार वर्ष 2022 मप्र के युवाओं के लिए रोजगार वर्ष बनेगा। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मप्र के निर्माण में युवा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। रोजगार आज एक प्रमुख आवश्यकता है। प्रतिमाह एक लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक उन्नयन का लाभ देने के लक्ष्य के मुकाबले दोगुनी उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्रतिमाह ढाई लाख लोगों को लाभान्वित करने में सफलता मिली है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए तरह-तरह के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां सरकारी विभागों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन शुरू किया जा चुका है तो वहीं निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन शुरू किया जा चुका है।

● **जितेंद्र तिवारी**

निकलेंगी बंपर भर्तियां

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सभी विभाग नौकरियां निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही सरकारी व नीति क्षेत्रों में भारी संख्या में भर्ती निकाली जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पहले ही भर्ती करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इनमें ऐसी भर्तियों को भी शामिल किया जा रहा है, जिन पर लंबे समय से भर्ती नहीं की जा सकी है। इसी तरह से सरकार द्वारा सरकारी विभागों में बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए भी अभियान संचालित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार के इन प्रयासों से सरकारी महकमों में इस साल करीब एक लाख युवाओं को नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा सरकार का स्वरोजगार पर भी फोकस है। यही वजह है कि केंद्र के अलावा राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर भी मप्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न विभागों एवं बैंको के माध्यम से कई स्वरोजगार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

इन्वेस्टर्स समिट में बनेगा निवेश का इतिहास

घोषित किया जाएगा निवेश क्षेत्र

बता दें कि इंदौर-भोपाल के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है। इस लिहाज से भी यह प्रोजेक्ट अहम रहेगा। कहा जा रहा है कि एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक रोहन सक्सेना ने बताया कि सरकार के निर्देश पर ही देवास को निवेश क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। कोशिश यह है कि इंदौर से देवास, सोनकच्छ, आष्टा, सीहोर और भोपाल को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाए। यहां उद्योग विभाग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क, कमर्शियल, रेसीडेंशियल, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट लाएगा। हालांकि क्षेत्र के हिसाब से यह पीथमपुर से एक चौथाई होगा। पीथमपुर का इंडस्ट्रियल एरिया करीब 50 हजार एकड़ में फैला है। यह देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां पर अलग-अलग क्षेत्र की 1500 से ज्यादा कंपनियां हैं। यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इधर प्रदेश में 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया। बैरसिया जिला भोपाल परियोजना लागत 25.88 करोड़, आष्टा (झिलेला) जिला सीहोर 99.43 करोड़, धार (तिलगारा) जिला धार 79.43 करोड़ मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है। इन 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होना संभावित है। साथ ही 38 हजार 450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

म प्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश कराना चाहते हैं। इसके लिए शासन और प्रशासन स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में 4 से 6 नवंबर तक इन्वेस्टर्स समिट रखी गई है। सरकार की कोशिश है कि इस समिट में निवेश का नया इतिहास बनाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका सहित कई देशों का दौरा कर उद्योगपतियों को निवेश के लिए न्यौता देंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे मई के दूसरे हफ्ते में अमेरिकी की यात्रा करेंगे। इस दौरान इंदौर में नवंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अमेरिकी उद्योगपतियों को मप्र आने का न्यौता देंगे। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खासी मेहनत कर रहे हैं। पचमढ़ी में चिंतन शिविर के बाद अब उनका फोकस उद्योगों पर होगा। दरअसल, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को काफी नुकसान हुआ था। इस पर भी विपक्ष बेरोजगारी पर मुखर है। लिहाजा, इससे उबरने के लिए इंदौर में 4 से 6 नवंबर तक इन्वेस्टर्स समिट रखी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अमेरिकी यात्रा के शेड्यूल की जानकारी दी। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री अमेरिका में करीब 10 दिन रहेंगे। उनकी यात्रा में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग और अन्य कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। इस यात्रा का मकसद प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करना है।

कोरोना की वजह से इन्वेस्टर्स समिट टल रही थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मप्र सरकार 4-6 नवंबर 2022 को इसका आयोजन करेगी। इन्वेस्टर्स समिट के पहले होने वाले रोड शो में दिल्ली और मुंबई में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय रोड शो दावोस और जर्मनी में करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अक्टूबर 2017 में भी अमेरिकी यात्रा की थी। बतौर मुख्यमंत्री यह उनकी आखिरी यात्रा थी। तब उन्होंने मप्र की सड़कों को अमेरिका से भी अच्छा बता दिया। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि, निवेश के लिहाज से अमेरिकी उद्योगपतियों को मप्र ज्यादा रास नहीं आया था। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक 12 विदेश यात्रा की और लौटकर कहा यह देश इतने हजार करोड़ का निवेश करेगा लेकिन निवेश नहीं आया।

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभाग प्रदेश में 21,640 एकड़ जमीन पर विभिन्न औद्योगिक पार्क प्रस्तावित करने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, इंदौर-भोपाल के बीच करीब 25 हजार एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किए जाने की योजना है। इसमें दोनों शहरों के बीच सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनेगा। उधर देवास में बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट क्षेत्र बनेगा। पीथमपुर और रतलाम के बाद यह मप्र का तीसरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट क्षेत्र होगा। इसके लिए देवास के आसपास करीब 12 हजार एकड़ जमीन लेने की तैयारी की जा रही है। एमपीआईडीसी ने सरकार को प्रस्ताव बनाकर भी भेज दिया है। दरअसल, देवास में औद्योगिक क्षेत्र है और यहां कई नामी कंपनियों के प्लांट भी हैं। शुरुआत में देवास ही मप्र का बड़ा औद्योगिक नगर था लेकिन बाद में पीथमपुर के विकसित हो जाने के बाद कंपनियों ने पीथमपुर को तरजीह दी। इसके चलते देवास में आने के बजाय कंपनियां पीथमपुर में चली गई। कुछ साल पहले जलसंकट ने भी देवास के औद्योगिक क्षेत्र पर बुरा असर डाला और कई कंपनियां बंद भी हुईं। अब फिर से देवास के लिए अच्छी खबर है। इंडस्ट्री को जमीन देने के साथ ही पीथमपुर में जिस तरह से सेक्टर डेवलपमेंट हुए हैं, उसी तरह से देवास को भी विकसित किया जाएगा। इससे करोड़ों रुपए का निवेश तो होगा ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के रूप में इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया 400 वर्ग किमी क्षेत्र का हो जाएगा। पीथमपुर, सांवेर रोड, पालदा, बेटमा के साथ अब देवास की सीमा भी औद्योगिक दृष्टि से इंदौर को उन्नत करेगी। इंदौर-भोपाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। इसमें उद्योग नगरी देवास, मेडिकल डिवाइस पार्क की नरवल स्थित जमीन शामिल नहीं है। यदि इसे भी शामिल करें तो मालवा में इंदौर इंडस्ट्री का सेंट्रल जोन होगा। इसके आसपास देवास, उज्जैन, पीथमपुर अलग-अलग विंग होंगे, जिन्हें एमपीआईडीसी ही विकसित करेगा।

● **विकास दुबे**

आदर्श ग्राम योजना ठप

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों के विकास के मद्देनजर आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सांसदों को अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों को गोद लेकर उनमें विकास कार्य करवाना था। शुरुआती वर्ष में तो मप्र के सांसदों ने बड़े जोर और जोश के साथ काम शुरू किया था, लेकिन धीरे-धीरे मामला अधर में लटकता गया और आज आदर्श ग्राम योजना ठप पड़ी हुई है।

केंद्र सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए आदर्श ग्राम विकसित करने की योजना बनाई थी। मकसद यही था कि आदर्श ग्राम में सभी तरह की सुविधाएं हों और अन्य ग्राम पंचायतें उन्हें देखकर प्रेरित हो सकें। जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसकी जिम्मेदारी सांसदों को सौंपी गई थी। शुरुआती दौर में मप्र में बेहतर काम हुआ। अधिकांश सांसदों ने पंचायतों को चयन किया। ग्राम विकास योजना भी बनी और कार्य भी स्वीकृत हुए लेकिन कोरोनाकाल में योजना ठप सी हो गई। 2019 से 2021 के अंत तक एक हजार 394 प्रोजेक्ट ही स्वीकृत हुए। इनमें भी 287 ही पूरे हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दो साल कार्य की गति प्रभावित हुई है।

सड़कों को रौंदते और मुरम (खनिज) की धूल उड़ाते डंपरों से हलाकान ग्रामीणों ने सोचा था कि आदर्श ग्राम होने के बाद उनके गांव को इस समस्या से निजात मिलेगी। कुछ बेहतर होगा, लेकिन डंपरों से मुक्ति मिलने के बजाय हाल ही में गांव में शराब की नई दुकान की अनचाही सौगात मिल गई। यह स्थिति दो साल पहले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा गोद लिए तिल्लौर खुर्द गांव की है। इंदौर शहर की तरह तिल्लौर खुर्द में भी स्वच्छता के लिए कचरा इकट्ठा किया जाने लगा है, लेकिन यह स्वच्छता केवल दिखावा भर है। कचरा इकट्ठा करके गांव के बाहर एक जगह डाला जा रहा है जो उड़कर खेतों में जा रहा है। गीले और सूखे कचरे को छांटने के लिए सेग्रिगेशन शेड बनाया गया है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। गांव में पानी की टंकी बन गई है जिससे घरों में नल का पानी आने लगा है।

इन राज्यों में विकास कार्य पूरा हुआ

इस योजना के तहत राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, असम में 60 प्रतिशत से कम कार्य पूरा हुआ है। योजना के तहत राजस्थान में 55.06 प्रतिशत, झारखंड में 52.63 प्रतिशत, तेलंगाना में 50.38 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 45.46 प्रतिशत, ओडिशा में 43.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 42.11 प्रतिशत, बिहार में 38.68 प्रतिशत, पंजाब में 36.97 प्रतिशत ग्राम विकास का कार्य पूरा हुआ है।

लालवानी का कहना है कि योजना के अनुसार ही विकास के कार्य हो रहे हैं। शराब दुकानें के मामले में अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वहीं, पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने सांवेर क्षेत्र के पोटलोद गांव को जब गोद लिया था तो प्रशासनिक मशीनरी गांव के विकास में जुट गई थी। नए-नए प्रोजेक्ट तैयार किए गए। गांव की मुख्य सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन महाजन का कार्यकाल खत्म होते ही पोटलोद गांव को अफसर भूल गए। जलसंकट की समस्या अभी भी दूर नहीं हो पाई है। भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने योजना के तहत बंगरसिया गांव को गोद लिया था। वर्ष 2019 से 2022 तक ग्राम पंचायत में 27 लाख 49 हजार के कार्य करवाए जा चुके हैं। 34 लाख 80 हजार के स्वीकृत कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। पूर्व सांसद आलोक संजर ने तारासेवनियां गांव को गोद लिया था। यहां 57 लाख 47 हजार रुपए के नाली निर्माण से लेकर अन्य कार्य कराए गए लेकिन अब स्थिति फिर बिगड़ने लगी है।

राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी का कहना है कि करेली जनपद में स्कूल में पानी, बाउंड्रीवाल, श्मशान घाट का विस्तार सहित अन्य कार्य करवाए गए हैं। कोरोनाकाल में सांसद निधि नहीं मिली, इसका असर कामों पर पड़ा है लेकिन अब यह फिर प्रारंभ हो गई है। अब नया गांव गोद लेकर जल संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया का कहना है कि यह सही है कि कोरोनाकाल में विकास और प्रगति धीमी हुई है किंतु प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुन: प्रदेश में विकास कार्य गति पकड़ चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मप्र को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करके धरातल पर उतारा जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है। सभी संसद सदस्यों से आग्रह करेंगे कि वे योजना में पंचायतों का चयन करें।

कहीं सांसदों की शिथिलता तो कहीं लचर स्थानीय प्रशासन के कारण 2015 में घोषित

सांसद आदर्श ग्राम योजना तो खैर अपेक्षित रूप से परवान नहीं चढ़ सकी, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अब तक पिछड़े एससी (अनुसूचित जाति) बाहुल्य गांवों को विकसित करने का एक बड़ा सपना पूरा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का सोच तो 2009 में ही बन गया था, लेकिन काम 2014-15 में शुरू हो पाया। अगले 6 महीनों के भीतर देश के 8 हजार से ज्यादा ऐसे गांव अब आदर्श ग्राम बन जाएंगे जहां लोगों की आम जरूरत से जुड़ी लगभग हर सुविधा मौजूद होगी। साथ ही आम लोगों के विकास से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं का अमल भी दिखेगा।

आदर्श ग्राम घोषित करने का काम इसी महीने शुरू हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत यह बड़ा काम हाथ में लिया है। इसमें वर्ष 2025 तक देशभर के सभी एससी बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनकी संख्या मौजूदा समय में करीब 27 हजार है। पहले चरण में 11 राज्यों के 8,370 एससी बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम के मानकों के अनुरूप तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में राज्यों की हरी झंडी मिलते ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। मंत्रालय ने हालांकि आजादी के अमृत महोत्सव में इसे घोषित करने की योजना तैयार की है, जिसमें जनवरी से शुरुआत होगी और जुलाई तक बारी-बारी से सभी राज्यों के आदर्श ग्रामों की घोषणा की जाएगी। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से होगी, जिसके करीब 800 दलित बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत उप्र के भी करीब 2,500 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया है जिनकी घोषणा जुलाई में होगी।

आदर्श ग्रामों में पंजाब के 550 गांव, मप्र के 1,000 गांव, राजस्थान के 950 गांव, कर्नाटक के 750 गांव, हरियाणा के 215 गांव, झारखंड के 200, हिमाचल प्रदेश के 275 गांव, ओडिशा के 600 गांव और छत्तीसगढ़ के 530 गांव शामिल हैं। इस योजना के तहत देश के दलित बाहुल्य ऐसे गांवों का चयन किया जाता है, जिनकी कुल आबादी कम से कम 500 लोगों की होती है। साथ ही जिनमें कुल आबादी में से करीब आधी आबादी अनुसूचित जाति की होती है।

इस योजना के तहत चयनित गांवों में तय सुविधाओं और योजनाओं को जुटाया जाता है। सुविधाएं पूरी होने के साथ ही गांवों को एक स्कोर दिया जाता है। फिलहाल आदर्श ग्रामों की घोषणा 50 बिंदुओं की परख के बाद ही जाती है। इनमें प्रत्येक बिंदु या काम पूरा होने पर उस गांव को दो अंक मिलते हैं। जैसे ही कोई गांव 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल कर लेता है तो उसे आदर्श ग्राम घोषित कर दिया जाता है।

आदर्श ग्राम में जुटाई जाती है ये सुविधाएं

आदर्श ग्रामों के विकास में जिन पहलुओं पर काम किया जाता है, उनमें पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण मार्ग एवं विकास, बिजली एवं साफ-सुथरा ईंधन, कृषि-खेती से किसानों में सुधार, लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, फोन-इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करना और आजीविका व कौशल विकास शामिल हैं। इसके साथ ही गांवों के जिन व्यक्तियों के पास आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड नहीं होते हैं, उन्हें वह दिया जाता है। पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्कीम का लाभ, गांवों में साफ-सफाई, सड़क, नाली और शौचालय की व्यवस्था रहती है। योजना के तहत ऐसे प्रत्येक गांव को मंत्रालय की ओर से 21 लाख रुपए की मदद भी दी जाती है जो योजनाओं के अतिरिक्त होती है। यानी योजनाओं से जो काम नहीं हो पाए, उसे इस फंड से कराया जाता है।

गौरतलब है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के शुरू होने के 7 वर्ष बाद भी एक चौथाई से अधिक परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2021 तक योजना के तहत 2314 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और ग्राम विकास की योजनाबद्ध 82,918 परियोजनाओं में से 53,352 परियोजनाएं एवं गतिविधियां पूरी हुई हैं जबकि 6,416 ग्राम विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस प्रकार से, योजना के तहत ग्राम विकास की 23,110 परियोजनाओं एवं गतिविधियों पर काम शुरू नहीं हुआ है जो कुल कार्यों का एक चौथाई से कुछ अधिक (28 प्रतिशत) होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के आंकड़ों के अनुसार, योजना के लिए चयनित 2314 ग्राम पंचायतों में से 1,717 ग्राम पंचायतों ने पोर्टल पर ग्राम विकास परियोजना का ब्यौरा अपलोड किया है।

गौरतलब है कि गांवों के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में किया था। 11 अक्टूबर 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत सांसदों को अपने क्षेत्र में एक 'आदर्श ग्राम' का चयन करके उसका विकास करना था। योजना के तहत 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से सांसदों को 3 गांव गोद लेने थे और 2019 से 2024 के बीच 5 गांव गोद लेने की बात कही गई है। योजना के तहत मुख्य रूप से 4 वर्गों (वैयक्तिक विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास) को बढ़ावा देकर ग्राम विकास करने की बात कही गई है। इसके तहत स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक न्याय व सुशासन आदि कार्यों को शामिल किया गया है।

'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है और सांसदों को सांसद निधि (एमपीलैड) के कोष से ही इसका विकास करना होता है। योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत तमिलनाडु (94.3 प्रतिशत), उप्र (89.8 प्रतिशत), गुजरात (84.2 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (79.67 प्रतिशत), कर्नाटक (76.68 प्रतिशत), उत्तराखंड (76.66 प्रतिशत), केरल (69.78 प्रतिशत), मप्र (68.4 प्रतिशत), मणिपुर (67.57 प्रतिशत), मिजोरम (66.32 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (65.25 प्रतिशत), हरियाणा (61.16 प्रतिशत) में आदर्श ग्राम योजना के कार्यों का क्रियान्वयन अच्छा पाया गया है। इन राज्यों में ग्राम विकास की परियोजनों का 60 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है।

● **सुनील सिंह**

कमलनाथ के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल!

मप्र कांग्रेस नेताओं ने पिछले सप्ताह 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान के हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा जैसे निर्णय आमतौर पर गांधी परिवार ही लेता आया है। लेकिन अचानक से राज्य के नेताओं का कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना उनके अधिकार को कम करने के समान देखा जा रहा है। इसे लेकर फिलहाल तो केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहता नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह शायद कमलनाथ के साथ उनके समीकरण हैं।

कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वे इस बात से नाराज हैं कि नाथ ने पार्टी आलाकमान को लूप में नहीं रखा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कार्रवाई की संभावना से इंकार किया क्योंकि नाथ 'गांधी परिवार के प्रति वफादार' हैं। 75 साल के कमलनाथ, मार्च 2020 में अपनी सरकार के बहुमत खोने तक मप्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे थे। वह गांधी और तथाकथित जी-21 (मूल रूप से जी-23) वरिष्ठ नेताओं के एक समूह के बीच एक वार्ताकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर का विपक्ष कहे जाने वाले इस समूह से जुड़े नेता शुरुआत से ही सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की व्यवस्था, हर स्तर पर निर्णय लेने और संगठन में बदलाव की मांग करते आए हैं। हालांकि, कई वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं ने कहा कि नाथ की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर उनके साथ चर्चा नहीं की गई, जबकि अन्य ने कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही इस संबंध में अंतिम फैसला लेंगी। वैसे राज्य के कुछ नेताओं का दावा ये भी है कि नाथ के मुख्यमंत्री चेहरे पर गांधी परिवार पहले से ही एक अनौपचारिक मुहर लगा चुका है।

4 अप्रैल को राज्य इकाई में विभिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले मप्र के वरिष्ठ नेताओं ने अपने मतभेदों को एक तरफ रखते हुए ऐलान किया कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यह फैसला नाथ के आवास पर राज्य इकाई की समन्वय बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और कांतिलाल भूरिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे शामिल थीं। इसके तुरंत बाद अरुण यादव ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी भाजपा के कुशासन के खिलाफ राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

गांधी परिवार के लिए मुश्किल स्थिति

कांग्रेस के भीतर विरोध के उठते स्वर और असंतुष्ट नेताओं के जी-21 समूह के बनने के बीच, कमलनाथ उन कुछ वरिष्ठ नेताओं में से रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को चलाने के लिए गांधी नेतृत्व पर विश्वास जताया है। केंद्रीय पार्टी के एक नेता के अनुसार, इस स्थिति ने आलाकमान को मुश्किल में डाल दिया है। एक अन्य पार्टी नेता ने बताया, 'अगर वे चाहें तो भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटा सकते। एक समय में दो युवा नेताओं के नाम चर्चा में थे, लेकिन एक बार फिर इस पर विराम लग गया है। उन्होंने (केंद्रीय नेतृत्व) इस तरह के मामलों को जब तक नजरअंदाज किया जा सकता है, तब तक अनदेखा करने की नीति को अपनाने का फैसला किया है। मप्र में अगले साल के अंत में चुनाव हैं। केंद्रीय नेतृत्व के पास तब तक का समय है। कई केंद्रीय नेताओं ने गांधी परिवार की इस असमंजस की स्थिति पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए अभी एक साल से ज्यादा का समय है। ऐसी कोई भी घोषणा करने में नाथ को 'जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी।'

मप्र कांग्रेस महासचिव केके मिश्रा ने बताया कि कमलनाथ को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया है। मप्र के लोग उन्हें एक 'दूरदर्शी' नेता के रूप में देखते हैं। मिश्रा ने कहा कमलनाथ एक राष्ट्रीय नेता हैं। वह पार्टी में चौथे नंबर पर आते हैं। असल में वह दूसरे नंबर पर आते हैं क्योंकि वह उम्र और तजुर्बे में राहुल और प्रियंका गांधी से बड़े हैं। उन्हें पार्टी आलाकमान की सहमति की जरूरत नहीं है। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जबलपुर से मौजूदा सांसद तरुण भनोट बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उन्होंने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा, 'हमने उन्हें नेता के रूप में चुना है। जाहिर तौर पर इस पर पार्टी आलाकमान की मंजूरी की मुहर है, तभी तो वह राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं।' अरुण यादव का कहना है कि यह मप्र कांग्रेस की कोर कमेटी का निर्णय है। उन्होंने बताया, 'मैंने ही कमलनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए।'

वैसे अंदरूनी कलह से घिरी राज्य कांग्रेस इकाई में यह कदम 'एकता' का प्रतीक लगता है। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। एक केंद्रीय नेता ने दावा करते हुए कहा, 'सभी जानते हैं कि नाथ के गांधी परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। भले ही राज्य के नेता व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहते कि वह नेतृत्व करें, मगर उनके पास इस फैसले पर अपनी स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से कोई इशारा मिलेगा, तो उन्हें बदलने में एक मिनट नहीं लगने वाला।' पार्टी की मप्र इकाई में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 कांग्रेस विधायक 2020 में भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद राज्य में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई। आपसी खींचतान का मसला टला नहीं है। कुछ दिनों पहले, कमलनाथ को उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस महीने रामनवमीं और हनुमान जयंती मनाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। तब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि उन्होंने रमजान मनाने के लिए इस तरह के दिशा-निर्देश क्यों नहीं जारी किए हैं।

● **राजेश बोरकर**

मप्र में लागू होगी नक्सल नीति!

मप्र में कई जिले नक्सल प्रभावित हैं। अब वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद नक्सली सरेंडर पॉलिसी को कैबिनेट में लाया जाएगा। मप्र में सरेंडर पॉलिसी नहीं होने से नक्सल विरोधी अभियान में परेशानी कैबिनेट में आएगी। मप्र में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए कोई प्रोत्साहन योजना या नीति नहीं है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जीवन-यापन के लिए कृषि योग्य भूमि या अन्य सेवाओं में मौका दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

दरअसल मप्र में बालाघाट, डिंडौरी और मंडला नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण नीति लागू है। लेकिन मप्र में लागू नहीं है। जिलों में सक्रिय नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने और उनके बेहतर पुनर्वास के लिए तैयार की गई सरेंडर पॉलिसी वित्त विभाग की मंजूरी के बाद कैबिनेट में रखी जाएगी। यहां से मंजूरी मिलने के बाद इस पर अमल शुरू होगा।

पुलिस मुख्यालय की नक्सल विरोधी अभियान शाखा ने नक्सल समर्पण नीति का मसौदा गृह विभाग को भेजा था। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही इसे इसी महीने कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्तावित नीति के अनुसार नक्सलियों और उनके द्वारा सरेंडर किए जाने वाले हथियारों के आधार पर पुनर्वास किया जाएगा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जीवन-यापन के लिए कृषि योग्य भूमि या अन्य सेवाओं में मौका दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। एके-47 या इसके समकक्ष हथियार सरेंडर करने पर नकद राशि भी दी जाएगी। सरेंडर के लिए नक्सलियों के कैडर और उन पर घोषित इनाम के आधार पर प्रोत्साहन राशि भी तय की गई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पुलिस को अन्य नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी मिलेगी, जिससे मप्र को नक्सल मुक्त कराने में आसानी होगी।

गौरतलब है कि मप्र में लाल आतंक का खतरा फिर बढ़ता जा रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व के 70 फीसदी इलाके पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है। यहां लंबे समय से कोर और बफर में नक्सलियों के विस्तार दलम और खटिया मोचा दलम की मौजूदगी बताई जाती है। नक्सलियों का प्रभाव बढ़ने से पर्यटक भी घट रहे हैं। 18 फीसदी ही कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटन बचा है। बता दें कि पिछले 2 महीने में 3 कर्मचारियों की नक्सलियों ने हत्या की है। इस कारण सुरक्षा में तैनात कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से अब डरने लगे हैं। वहीं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और ग्लोबल टाइगर फोरम के सेक्रेटरी जनरल राजेश गोपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल, कान्हा टाइगर रिजर्व दो जिलों के अंतर्गत आता है- बालाघाट और मंडला। इन जिलों में नक्सली मूवमेंट बढ़ गया है। जब नक्सलियों पर दबाव पड़ता है तो नक्सली डिंडौरी जिले के गांव में आ जाते हैं। हालांकि पुलिस ने कान्हा के बफर और कोर जोन में सर्चिंग बढ़ा दी है जिससे नक्सली कान्हा के जंगल में घिर गए हैं।

पिछले साल राज्य पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने डिंडौरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया था। बीते दो दशक में यह प्रदेश का तीसरा जिला है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है। इसके पहले बालाघाट और मंडला को इस श्रेणी में रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते मप्र के कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट, डिंडौरी और मंडला में नक्सलियों की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लगातार इस क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है। कान्हा नेशनल पार्क के साथ-साथ वनों की सुरक्षा के लिए गठित पुलिस बल के लिए हर साल 24.9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में देश में सबसे ज्यादा 108 बाघ हैं।

कान्हा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर एके सिंह का कहना है कि कान्हा के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी है, लेकिन उनका कब्जा कहीं नहीं है। पर्यटन बेखौफ जारी है। वनकर्मी अपनी-अपनी बीट में निरंतर गश्त कर रहे हैं। बालाघाट एसपी समीर सौरभ का कहना है कि कान्हा के बफर और कोर जोन में सीआरपीएफ मंडला, सीआरपीएफ गढ़ी और हाकफोर्स व जिला पुलिस बल के जवान नियमित सर्चिंग कर रहे हैं।

पिछले साल राज्य पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने डिंडौरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया था। बीते दो दशक में यह प्रदेश का तीसरा जिला है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है। इसके पहले बालाघाट और मंडला को इस श्रेणी में रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते मप्र के कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट, डिंडौरी और मंडला में नक्सलियों की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लगातार इस क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है।

● **बृजेश साहू**

चरम पर है नक्सलियों का आतंक

मंडला सांसद और केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि यहां ज्यादातर हिस्सों में नक्सली गतिविधियां न केवल बढ़ रही हैं बल्कि कान्हा नेशनल पार्क के क्षेत्र में विकास के कार्य में लगी हुई सरकारी मशीनरी और वाहनों को नक्सलियों के द्वारा आग लगाई जा रही है। कान्हा नेशनल पार्क के कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही हैं, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है। कान्हा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, इस वजह से नक्सलियों को आसानी से प्रवेश मिल जाता है। नक्सलियों के आतंक की जानकारी सरकार को है और ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए सरकार संवेदनशील है, सुरक्षाबलों और कंपनियों को इन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।

मप्र की नदियों पर बांधों की एक बड़ी श्रृंखला है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश बांध आधे दशक पुराने हैं। इन बांधों में यदा-कदा रिसाव और दरार पड़ने की खबरें आती हैं। हालांकि देर से ही सही सरकार ने बांधों की मरम्मत की कवायद शुरु कर दी है।

दरकते और रिसते बांधों ने बढ़ाई चिंता

जर्जर बांधों की जद में मप्र की आधी आबादी

प्रदेश के करीब 91 बांध उम्रदराज हैं और ये कभी भी दरक सकते हैं। मप्र वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के आंकडों के अनुसार प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए 168 बड़े और सैकड़ों छोटे बांध बनाए गए हैं। देखरेख और मेंटेनेंस के अभाव में कई छोटे-बड़े बांध बूढ़े और जर्जर हो चुके हैं। इनमें से कुछ की उम्र 100 साल से ज्यादा है। इन उम्रदराज बांधों को लेकर बेपरवाह प्रशासन ने न तो इन्हें डेड घोषित किया और न ही मरम्मत की कोई ठोस पहल की। ऐसे लबालब ये बांध यदि दरक गए या टूट गए तो कभी भी बड़ी तबाही ला सकते हैं। इन बांधों की वजह से नदियां भी अपनी दिशा बदल सकती हैं। इससे भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इस ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया है। प्रदेश के लगभग आधा सैकड़ा बांधों की उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है। जबकि 18 बांध तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसे में इन बांधों की ठोस मरम्मत नहीं होने से इनके आधार कमजोर हो चले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े बांधों की उम्र 100 वर्ष व छोटे बांधों की उम्र लगभग 50 वर्ष मानी जाती है। इस उम्र तक इन बांधों की मजबूती बनी रहती है। बाद में धीरे-धीरे ये कमजोर होने लगते हैं। साथ ही नदियों के साथ आने वाले गाद भी बांधों को प्रभावित करते हैं। इससे बांधों की क्षमता कम होने लगती है।

बुंदेलखंड के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले के बॉर्डर पर बने बान सुजारा बांध के 6 गेट और गैलरी में बड़ा लीकेज हो गया है। इससे दोनों जिलों के 52 गांवों के ऊपर तबाही का खतरा पैदा हो गया है।

दरअसल, प्रदेश में करीब आधा सैकड़ा बांध ऐसे हैं जो पुराने होने के कारण जर्जर स्थिति में आ गए हैं। दरकते और रिसते बांधों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जल संसाधन विभाग ने 27 ऐसे बांधों को चिन्हित किया है, जिनकी मरम्मत जरूरी है। जल संसाधन विभाग जल्द की निविदा आमंत्रित करके काम शुरू कराएगा।

जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार श्योपुर जिले में वर्ष 1908 में निर्मित वीरपुर, वर्ष 1910 में सिवनी जिले में निर्मित रुमल और 1913 में धार जिले में बने माही सहित प्रदेश के 27 बांधों की सरकार मरम्मत कराएगी। इन बांधों की दीवार में कहीं-कहीं दरार आ चुकी हैं या कहीं-कहीं मिट्टी धंस रही है। मरम्मत कार्य के लिए सरकार ने 551 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब जल संसाधन विभाग निविदा आमंत्रित करके काम शुरू कराएगा।

जल संसाधन विभाग के अफसरों का कहना है कि वर्ष 2019 में गांधी सागर बांध से पानी के रिसाव और पिछले साल ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अतिवृष्टि के बाद सरकार बांधों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई है। प्रदेश में ज्यादातर बांध 35 साल पुराने हैं। जबकि, तीन बांधों (वीरपुर, रुमल और माही) को बने हुए 100 साल से अधिक हो चुके हैं। बांधों की मरम्मत की जरूरत को देखते हुए बारिश से पहले मरम्मत सहित अन्य विकास के काम की कार्ययोजना बनाई गई है। जिन बांधों की मरम्मत होनी है उनमें इंदौर का देपालपुर और चोरल, सागर का चंदिया नाला, मंसूरवारी और राजघाट, खंडवा का भगवंत सागर, मंदसौर का गांधी सागर, काकासाहेब गाडगिल सागर और रेताम, भोपाल का कलियासोत, केरवा और हथाईखेड़ा, बैतूल जिले का चंदोरा, नर्मदापुरम का डोकरीखेड़ा, सीधी का कंचन टैंक, शिवपुरीकाकुडा, टीकमगढ़ का वीर सागर और नंदनवाड़ा, मंडलाका मटियारी, आगर मालवा का पोपलिया कुमार, धार का सकल्दा, रतलाम का रुपनियाखाल, शाजापुर का तिल्लार और कटनीका बोहरीबंद बांध शामिल हैं।

बांधों की वर्तमान स्थिति पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी आपत्ति की थी और सरकार को मरम्मत कराने की सलाह दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध कमजोर हो गया है। बांध के डाउन स्ट्रीम में गहरे गड्ढे हो गए हैं। वर्ष 2019 में इस बांध से पानी का रिसाव भी ज्यादा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बांध की सुरक्षा को लेकर बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल (डीएसआईपी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 12 साल पहले जो सिफारिश की थी, वह पूरी नहीं की गई।

उधर, बुंदेलखंड के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले के बॉर्डर पर बने बान सुजारा बांध के 6 गेट और गैलरी में बड़ा लीकेज हो गया है। इससे दोनों जिलों के 52 गांवों के ऊपर तबाही का खतरा पैदा हो गया है। गैलरी में पानी ज्यादा होने की वजह से सुधार का काम नहीं हो पा रहा है। लीकेज का मामला सरकार तक पहुंच गया है। इसका निर्माण हैदराबाद की जेवीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया। 250 करोड़ की लागत से 2018 में बनकर तैयार हुए। बांध में कुल 12 गेट हैं, जिसमें से 6 गेट में हल्के लीकेज हो गए हैं। गैलरी में बड़ा लीकेज है। गैलरी को खाली कराने के लिए 50 हॉसपावर की मशीन लगाई है, लेकिन पानी खाली नहीं हो रहा है। बांध में शुरू से ही लीकेज है और मिट्टी का कटाव हो रहा है। शुरू में बड़ा लीकेज होने पर बांध को खाली कराकर सुधार किया गया था। लेकिन बांध में लीकेज बना हुआ है। बांध में लीकेज और सुधार का मामला शुरू से सरकार के संज्ञान में है। फिलहाल बांध लबालब भरा है। मरम्मत के लिए बांध के खाली होने का इंतजार है। बानसुजारा बांध ईई वीपी अहिरवार ने बताया कि बांध की गैलरी में लीकेज बड़ा इश्यू है। दो साल से कोरोना के चलते एजेंसी ने लीकेज सुधार का काम नहीं किया। बांध खाली होने पर सुधार हो पाएगा। विभागीय अधिकारी बांध निर्माण एजेंसी द्वारा गुणवत्ता से समझौता करने की बात भी मौन स्वीकार कर रहे हैं।

● **जय सिंह**

रसूखदारों पर अफसरों की मेहरबानी

राजधानी की लाइफ लाइन बड़े तालाब का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है, लेकिन अफसरों की नाफरमानी से तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। बड़े तालाब में अतिक्रमण करने वाले रसूखदारों पर अफसरों की मेहरबानी का ही नतीजा है कि सरकार की सख्ती के बावजूद अतिक्रमणकारी जमे हुए हैं। बड़े तालाब में 300 से अधिक अवैध कब्जों में से मात्र 11 कब्जे हटाए गए हैं। यही नहीं अफसरों ने रसूखदारों को बचाने के लिए बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया के कब्जों की फाइलों को ही दबा दिया और विधानसभा में गलत जानकारी भेजी। गौरतलब है कि शहर में हर साल 6 करोड़ से अधिक की राशि बड़े तालाब के संरक्षण पर खर्च की जाती है। उसके बावजूद तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण होता जा रहा है। बताया जाता है कि इसमें नगर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारियों की मिलीभगत होती है। यही नहीं नगर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारियों की मनमानी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने रसूखदारों को बचाने के लिए बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया के कब्जों की फाइलों को ही दबा दिया और विधानसभा में गलत जानकारी भेजी।

जानकारी के अनुसार बड़े तालाब में हो रहे कब्जों की एक रिपोर्ट नगर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा पिछले साल एनजीटी में पेश की गई थी। इसमें सिर्फ 11 अवैध कब्जों को हटाने की बात कही गई है। जबकि 300 से अधिक अवैध कब्जे अभी भी बरकरार हैं। वहीं, जिला प्रशासन के 2019 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में बड़े तालाब के एफटीएल से 50 मीटर के दायरे में 321 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इसमें से सिर्फ 4 कब्जों को हटाया गया था, बाकी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजनीतिक दबाव में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बड़े तालाब का दायरा कम होता जा रहा है। इसकी वजह कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण हैं। लेकिन साल 1958-59 की खसरा-खतोनी में कैचमेंट एरिया का रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है। यानी बड़े तालाब के कैचमेंट में कब्जे का सरकारी रिकॉर्ड लापता है। ये जानकारी बीते दिनों 10 मार्च 2022 को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा विधानसभा में विधायक प्रदीप पटेल द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई है। बड़ा सवाल ये है कि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में जब कैचमेंट एरिया की जानकारी दर्ज नहीं है, तो फिर तालाब के कैचमेंट में 300 से अधिक पक्के निर्माण को अवैध क्यों करार दिया गया है। तालाब के कैचमेंट का दायरा तय करने के लिए जगह-जगह मुनारें लगाई गई हैं, ताकि उसके भीतर कोई भी पक्का निर्माण न हो सके। बावजूद इसके बड़े तालाब पर कई स्थानों पर कब्जा किया गया है।

झील संरक्षण प्रकोष्ठ मूक दर्शक बना

तालाब के संरक्षण और उसे अतिक्रमणमुक्त बनाए रखने की जिम्मेदारी झील संरक्षण प्रकोष्ठ की है। तकरीबन 40 से अधिक लोगों की फौज इस समय झील संरक्षण प्रकोष्ठ में आराम कर रही है, पर उसको तालाब के आसपास के कब्जे इसलिए नजर नहीं आते हैं क्योंकि वह लेक व्यू फ्रंट के मोह में बिल्डरों को पनपने का मौका दे रहे हैं। यही हाल खानूगांव, भौंरी और कोहेफिजा का भी है। प्रकोष्ठ से जुड़े अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता और इंजीनियर आरके गुप्ता की जुगलबंदी नगर निगम की शान पर बट्टा लगा रही है। गौरतलब है कि तीन साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के निर्देश पर तय किया गया था कि बड़े तालाब से अतिक्रमण हटाने से पहले बिल्डिंग परमिशन की जांच कराई जाएगी। बड़ा तालाब एफटीएल को देखने के लिए डोन से फोटोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा बड़े तालाब की जद में आने वाले निर्माणों को भी चिन्हित किया जाएगा, लेकिन सरकार बदलते ही सारे काम ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। अब सरकारी रिकार्ड के साथ भी छेड़छाड़ कर उसे गायब करा दिया गया है।

राजधानी की जीवन रेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब में बढ़ते अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से इसके अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि वेटलैंड एरिया के 20 वर्ग किलोमीटर तक लोगों ने यहां अतिक्रमण कर लिया है, जो अब एफटीएल के 50 मीटर अंदर तक पहुंच चुका है। ग्रीन बेल्ट के दायरे में बड़े-बड़े शादी हाल और व्यावसायिक इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। नगर निगम अधिकारी इन भू-माफिया के खिलाफ सिर्फ नोटिस जारी कर कार्रवाई से पल्ला झाड़ लेते हैं। बता दें कि बड़े तालाब का जल भराव क्षेत्र 31 वर्ग किलोमीटर और कैचमेंट एरिया 361 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके कैचमेंट एरिया में दो दर्जन से अधिक अवैध शादी हाल संचालित हो रहे हैं। लोगों ने अतिक्रमण कर यहां पक्के गोदाम और फार्म हाउस बना लिए हैं। इनमें शहर के रसूखदार लोगों के साथ सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिए हैं। इनके रसूख के कारण अब तक नगर निगम भी नोटिस भेजने के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया। जबकि तालाब का तकरीबन 26 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खाली हो चुका है। आसपास के लोगों के अलावा भू-माफिया ने भी मौके का फायदा उठाकर अवैध कब्जा कर अधिकांश हिस्से में खेती शुरू कर दी। वेटलैंड के बड़े हिस्से में कब्जा कर पक्के मकान बना लिए गए हैं।

बड़े तालाब के संकट को देखते हुए इसके संवर्धन व संरक्षण को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बड़ा तालाब एक वेटलैंड साइट है। इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व है, इसलिए इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। जिससे इसका संवर्धन व संरक्षण बेहतर हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला एनजीटी से उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। बड़े तालाब के ग्रीन बेल्ट एरिया में मैरिज गार्डन समेत अन्य अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी ने इसके चिन्हांकन व सीमांकन के आदेश दिए थे। जिससे पता चल सके कि एफटीएल की स्थिति में तालाब का जलभराव क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट एरिया कितना है। लेकिन रसूखदारों के दबाव में निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

● **अरविंद नारद**

60 हजार पेड़ों का कत्ल

म प्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले एक साल से अधिक समय से रोजाना पौधारोपण कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आलम यह है कि राजधानी भोपाल में ही हर साल 60 हजार पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। जिस शहर को देश के राज्यों में प्राकृतिक रूप से सबसे सुदंर राजधानी का तमगा मिला हुआ था, आज उसी भोपाल के हाल यह हो गए हैं कि उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने वाली हारियाली तेजी से कम होती जा रही है, फलस्वरूप सुहाने मौसम पर भी अब समाप्ती का खतरा पैदा हो चुका है। प्रकृति की गोद में स्थित राजधानी भोपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। यही कारण है कि सरकार का पूरा फोकस शहर में हरियाली बढ़ाने पर रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन नेताओं और अफसरों पर शहर की हरियाली बढ़ाने और संरक्षण का दायित्व है, उन्होंने ही ग्रीनबेल्ट पर अतिक्रमण कर कहीं पार्किंग और टॉयलेट तो कहीं सर्वेट क्वार्टर तक बना लिए हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो वीआईपी ग्रीनबेल्ट पर अतिक्रमण करने में कोई किसी से कम नहीं है।

इसकी वजह है विकास के नाम पर सरकार व अफसरों द्वारा मिलकर हर साल करीब 60 हजार पेड़ों का औसतन रूप से कराए जाने वाला कत्ल। इसकी वजह से हालात यह हो गए हैं कि शहर में एक दशक के अंदर ही 26 फीसदी हरियाली कम हो चुकी है। इसमें भी खास बात यह है कि 15 फीसदी हरियाली तो महज बीते 5 सालों में ही कम हुई है। इसके बाद भी शहर में अंधाधुंध स्तर पर पेड़ों की कटाई जारी है और जिम्मेदार इस मामले में चैन की नींद में डूबे हुए हैं। इसकी वजह से कभी वनाच्छादित रहने वाला इलाका अब पूरी तरह से बंजर नजर आने लगा है। फलस्वरूप में अब राजधानी की गिनती देश के उन शहरों में होने लगी है, जहां पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण की स्थिति है। इसके बाद भी राजधानी में अधोसंरचना विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई अनवरत रूप से जारी है। हाल ही में बैरागढ़ स्थित एमपी स्टेट रोडवेज परिसर में निर्माण कार्य का बहाना बताकर एक सैकड़ा से अधिक पेड़ो की बलि चढ़ा दी गई है। खास बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से की, लेकिन इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। यहां बीते 5 साल में 3 लाख से अधिक पेड़ काट दिए गए। इससे शहर के तापमान में जहां तेजी से वृद्धि हुई है तो वहीं प्रदूषण के साथ ही हरियाली में भी तेजी से कमी आई है।

हाल ही में एक शोध के हवाले से कहा गया है कि बीते एक दशक में निर्माण कार्यों को लेकर जिस तरह से हरे भरे पेड़ काटे गए हैं, उससे भोपाल की हरियाली में 26 फीसदी की कमी आई है। व्यापक स्तर पर पेड़ों की कटाई वाले 9 स्थानों पर 225 एकड़ हरे भरे इलाके को मिटाकर वहां पर कांक्रीट के जंगल बना दिए गए। भोपाल में बीते कई सालों से शुरू हुई अधिक गर्मी की वजह भी यही है। इससे शहर का औसत तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। शहर में सर्वाधिक पयार्वारण का नुकसान 2014 से 2021 के बीच हुआ है। इन सालों में लगभग 80 फीसदी पेड़ काटे गए। जबकि 20 फीसदी पेड़ों की कटाई 2009 से 2013 के बीच की गई है। प्रोफेसर राजचंद्रन की वर्ष 2016 की रिपोर्ट में प्रकाशित शोध, गूगल इमेजनरी और अन्य सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से तैयार की गई रिपोर्ट के लिए शहर को 15 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया और 3 सड़कों (बीआरटीएस होशंगाबाद रोड, कलियासोत डेम की ओर जाने वाली रोड एवं नॉर्थ टीटी नगर की स्मार्ट रोड) को सैंपल के रूप में लिया गया। इन सड़कों के पास मौजूद प्रमुख 11 इलाकों के 345 एकड़ क्षेत्र का विश्लेषण करने पर पता चला कि 10 वर्ष में यहां की हरियाली पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। सिर्फ 11 क्षेत्रों में ही 50 साल पुराने 1.55 लाख से अधिक पेड़ों का कत्ल कर दिया गया।

विकास के नाम पर पेड़ों की बलि देने के बाद इन पेड़ों को विस्थापित कर कलियासोत, केरवा व चंदनपुरा आदि जंगलों में लगाने के दावे जरूर किए गए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से यह प्रयास अब तक सफल होते नहीं दिख रहे हैं। इन पेड़ों ने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया। जबकि अधिकारी पेड़ों के बदले चार गुना तक पौधे लगाने का दावा करते हैं। लेकिन यह अब तक तो दावे ही नजर आते हैं। सरकार द्वारा राजधानी में चलाई जा रही स्मार्ट सिटी के निर्माण में 6000, बीआटीएस कॉरिडोर बनाने के लिए 3000, विधायक आवास बनाने के लिए 1150, सिंगारचोली सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 1800, हबीबगंज स्टेशन निर्माण के लिए 150 और खटलापुरा से एमवीएम कॉलेज तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 200 पेड़ों की बलि ले ली गई।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

पेड़ों की कटाई के मामले में मप्र तीसरे नंबर पर

देश में पिछले 3 साल में 76 लाख से अधिक पेड़ काटे गए। ये पेड़ विभिन्न विकास कार्यों के लिए काटा जाना जरूरी बताया जाता है। देश में सबसे ज्यादा 12,12,757 पेड़ तेलंगाना में काटे गए हैं। इसके बाद 10,73,484 पेड़ महाराष्ट्र में काटे गए। तीसरे नंबर पर मप्र आता है। मप्र में 9,54,767 पेड़ काटे गए। इसका खुलासा वन एंव पर्यावरण मंत्रालय के एक जवाब में हुआ है। इसमें 2016 से 2019 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। पेड़ों की कटाई की संख्या में 2018-2019 के बीच 30,36,642 की बढ़ोतरी हुई है। यदि देशभर के आंकड़ों को देखें तो पिछले 3 सालों में पेड़ों की कटाई दोगुनी से अधिक हुई है। 2016 से 2019 के बीच कुल 76,72,337 पेड़ काटे गए हैं। वहीं, नागालैंड, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, दमन-दीव और दादर नागर हवेली में एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि सभी पेड़ बेहद जरूरी कार्यों की वजह से काटे गए हैं। इनकी अनुमति फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत दी गई थी। इन पेड़ों को सामान्य पॉलिसी के तहत काटा गया है। साथ ही यह भी बताया कि 7,87,00,000 पेड़ अनिवार्य प्रतिपूर्ति वनीकरण के तहत लगाए जाएंगे।

केन-बेतवा से आएगी सूखे बुंदेलखंड में खुशहाली

44 605 करोड़ बजट वाली केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड की उजड़ी तस्वीर में खुशहाली के रंग भरेगी। मप्र के आठ और उप्र के चार जिलों के सूखे खेतों को पानी मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाई जाएगी। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देश के कई हिस्सों में जल संकट की समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना लेकर आई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत परिकल्पित केन-बेतवा लिंक परियोजना देश में कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने की पहली परियोजनाओं में से एक होगी। परियोजना को बहुउद्देश्यीय परियोजना के रूप में नियोजित किया गया है।

दरअसल, बुंदेलखंड क्षेत्र बार-बार सूखे की स्थिति का सामना करता है, जिसने क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। कठोर चट्टान और सीमांत जलोढ़ इलाके के कारण यह क्षेत्र भूजल में समृद्ध नहीं है। ऐसे में यह परियोजना मानसून के दौरान बाढ़ के पानी के उपयोग में मदद करेगी और कम बारिश वाले महीनों के दौरान पानी की उपलब्धता स्थिर करेगी, खास तौर पर सूखे के हालात में इस परियोजना से जिन जिलों को लाभ होगा उनमें मप्र के छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, पन्ना और उप्र के झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। छतरपुर जिले के ढोढन में बांध बनाकर यहां से जो 220 किमी लंबी नहर निकाली जाएगी वह छतरपुर, टीकमगढ़ जिले से उप्र के महोबा जिले से गुजरेगी, अंत में झांसी जिले के बरुआसागर तालाब में केन के अतिरिक्त पानी को पहुंचाएगी। यहां से यह पानी 20 किमी आगे पारीछा बांध में पहुंचाया जाएगा। परियोजना के दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध, बेतवा की सहायक बीना नदी जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा।

प्रोजेक्ट के दोनों फेज से सालाना करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 62 लाख लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना में 72 मेगावाट के दो बिजली प्रोजेक्ट भी तैयार होंगे। मप्र और उप्र के लिए महत्वाकांक्षी इस परियोजना पर दोनों प्रदेशों की सरकारों के साथ केंद्र सरकार से स्वीकृति से उम्मीद बंध गई है कि अब इस परियोजना के सुखद परिणाम सामने आने में देर नहीं है। अगर यह प्रयोग कामयाब रहा तो देश की अलग-अलग क्षेत्रों की नदियों को आपस में जोड़ने की 30 योजनाओं का रास्ता साफ होगा।

जल संसाधन छतरपुर संभाग के कार्यपालन यंत्री एमके रूसिया ने बताया कि वन पर्यावरण मंत्रालय से दोनों चरणों में स्वीकृति के बाद इस बड़े प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। अभी प्रथम स्टेज की मंजूरी मिल गई है, अब नोटिफिकेशन के अनुसार द्वितीय स्टेज की मंजूरी लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद ही प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना में मप्र के हिस्से में 7 बांध बनाए जाएंगे। पहले फेज में छतरपुर जिले की केन नदी पर ढोढ़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचेगा। केन-बेतवा नदियों को जोड़ने से जिले की 3,11,151 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इससे जिले के राजनगर, बिजावर, लवकुशनगर, नौगांव अनुभाग के ज्यादा हिस्से की भूमि सिंचित होगी। अभी जिले की भूमि पर फिलहाल जौ, बाजरा, दलहन, तिलहन, गेहूं, मूंगफली, चना जैसी फसलें पैदा होती हैं, इन फसलों में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नदियां जुड़ जाने से पूरे इलाके में अधिक पानी वाली और गन्ने की फसलें भी पैदा हो सकेंगीं। इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,000 से अधिक तालाबों को पानी से बारह माह भरा जा सकेगा। कुल मिलाकर इन नदियों के जुड़ जाने से जिले की पूरी आबादी खुशहाल होगी।

इस परियोजना में यमुना नदी की सहायक नदियों सहित मप्र के पन्ना जिले में केन नदी और उप्र में बेतवा नदी को जोड़कर जल संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त पानी वाले नदी के बेसिन से कम पानी वाले बेसिन तक पानी पहुंचाया जाएगा। यह कार्य 8 वर्षों में दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में छतरपुर जिले के ढोढन बांध बनाकर उससे जुड़ी निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, 221 किमी लंबी केन-बेतवा लिंक नहर और बिजलीघर बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में लोअर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज के लिए विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।

● **सिद्धार्थ पांडे**

पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर जताई चिंता

जहां एक ओर केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, वहीं कई कुछ पर्यावरणविदों ने इससे पर्यावरण व वन्य जीवों को नुकसान की आशंका व चिंता जताई है। पर्यावरण विशेषज्ञ अनुपम मिश्र ने पन्ना टाइगर रिजर्व पर इसके दुष्प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर निर्माण कार्य की वजह से 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की संभावना है। टाइगर रिजर्व कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों का घर है, इसके अलावा, केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के विकास से परियोजना के ढोढन बांध के तहत 6,017 हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का भी खतरा है। वहीं इस बड़ी परियोजना में यहां 9,000 हेक्टेयर के जलाशय में पानी रोके जाने से जलाशय क्षेत्र में छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के 10 आदिवासी बहुल वनग्राम सुकवाहा, भोरकुवां, घुघरी, बसुच्च, कुपी, शाहपुरा, ढोढन, पिलकोहा, खरयानी और मनियारी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाने वाले भोपाल के पर्यावरण कार्यकर्ता अजय कुमार दुबे कहते हैं कि वैसे भी पन्ना टाइगर रिजर्व एक बार पहले भी अपने सारे बाघ खो चुका है और वहां अब नए सिरे से बाघों को बसाया जा रहा है। वर्तमान में यहां करीब 70 से अधिक बाघ हैं।

आखिर इतना आक्रोश क्यों?

देश में अचानक एकसाथ एक जैसी वारदात की वजह क्या?

सांप्रदायिक हिंसा के पीछे विदेशी ताकत या चुनावी षड्यंत्र?

सत्य, धर्म, दया और मर्यादा के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम बने भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमीं पर इस बार आधा दर्जन से अधिक राज्यों में जिस तरह की हिंसक वारदातें हुईं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना आक्रोश क्यों? क्योंकि अभी तक धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमीं मनाई जाती थी, लेकिन इस बार सभी जगहों पर हिंसा का पैटर्न एक जैसा था। हिंसा की इन घटनाओं ने संविधान, लोकतंत्र और बहुलतावाद में विश्वास रखने वाले शांतिप्रिय भारतवासियों की चिंता बढ़ा दी है।

● राजेंद्र आगाल

भारत की गंगा-जमुनी तहजीब को न जाने किसकी नजर लग गई है कि यहां की फिजा में सांप्रदायिकता का जहर घुल गया है। यह जहर इतना जहरीला हो गया है कि हमेशा धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने वाले पर्व रामनवमीं के मौके पर भी इस बार आधा दर्जन से अधिक राज्यों में हिंसा हुई। सभी जगहों पर पैटर्न एक जैसा था- मसलन हुड़दंग, उकसाने वाली नारेबाजी और फिर पत्थरबाजी, जिसने दंगे का रूप ले लिया। हिंसा की इन घटनाओं ने संविधान, लोकतंत्र और बहुलतावाद में विश्वास रखने वाले शांतिप्रिय भारतवासियों की चिंता बढ़ा दी है। लोग अपने जान-माल और बच्चों के भविष्य को लेकर सहम गए हैं। देशभर में अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले मप्र के खरगोन जिले में उपद्रव और आगजनी का ऐसा तांडव मचा कि आज तक उसका डर लोगों के मन में समाया हुआ है। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और दीवारों, सड़कों पर सांप्रदायिक हिंसा के निशान दिख रहे हैं। आखिर इतना आक्रोश क्यों?

मप्र में बेहद शांत स्वभाव के माने जाने वाले इलाके मालवा-निमाड़ में पिछले करीब एक साल से सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। क्षेत्र के आमजन भी इस बात को लेकर चिंतित दिखते हैं कि आखिर इस इलाके में पिछले दो साल में ऐसी क्या बात हो गई जो यहां इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। वहीं देशभर में पिछले 8-10 दिनों के भीतर जो कुछ देखने को मिला है, उसके बारे में आमतौर पर माना जा रहा है कि यह तो महज ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी आनी बाकी है, क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा के आम चुनाव हैं, जबकि उसके पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मप्र व कर्नाटक समेत 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भयभीत लोगों को प्रशासन की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। इसके बाद भी कई इलाकों से पलायन की खबर भी सामने आ रही हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि गंगा-जमुनी तहजीब वाले इस देश में एक साथ रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोग एक-दूसरे के दुश्मन बन गए। क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है या चुनावी षड्यंत्र? वजह कोई भी हो, सांप्रदायिक हिंसा से भारत माता का सीना छलनी हुआ है।

सारे मुद्दे जमींदोज

मप्र सहित आधा दर्जन से अधिक राज्यों में रामनवमीं को जो सांप्रदायिक उन्माद देखने को मिला उसकी जड़ में कौन है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए सांप्रदायिकता एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। उप्र चुनाव में जो 'अस्सी बनाम बीस' व बुलडोजर की राजनीति शुरू हुई थी, वह आगे भी जारी रहेगी। ऐसा इसलिए कि चुनाव जीतने का यह एक ऐसा अचूक फॉर्मूला साबित हुआ है, जिसके सामने प्रचंड बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, समाज के कमजोर तबकों का उत्पीड़न और सरकार की तमाम नाकामियां जैसे मुद्दे जमींदोज हो जाते हैं। राजस्थान में करौली के बाद मप्र के खरगोन का दंगा काफी चर्चित रहा। हालांकि यहां तत्परता दिखाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दंगा करने वाले दंगाईयों के मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिए। लेकिन उसके बाद भी खरगोन सहित अन्य क्षेत्रों में भय का माहौल है। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। ऐसे में यह दंगा किसी सुनियोजित साजिश का अंग माना जा रहा है। आजादी से पहले जिस तरह अंग्रेज धर्म और जाति के नाम पर हम भारतीयों को लड़ाते रहते थे, आज उसी तर्ज पर हम आजादी के 74 साल बाद भी लड़ रहे हैं।

इसी तरह चुनाव वाले राज्य गुजरात के हिम्मतनगर और खम्भात आदि जगहों से भी हिंसा की खबरें आईं हैं। करीब 7 माह पहले ही वहां विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। गुजरात भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि उप्र में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया था। कर्नाटक में भी पिछले वर्ष जुलाई में येदियुरप्पा की जगह बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद से ही यह राज्य हिजाब विवाद, हलाल मीट, मुस्लिम दुकानदारों, कारीगरों व ऑटो वालों का बहिष्कार आदि के कारण चर्चा में बना हुआ है। यहां भी रामनवमीं के मौके पर कोलार व कुछ अन्य जगहों पर हिंसा हुई है। दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता राज्य है, जहां भाजपा की सरकार है। वर्ष 2019 में कांग्रेस व जद (एस) के विधायकों को तोड़कर उसने वहां सत्ता पर कब्जा किया था। इसे बचाए रखना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बहरहाल उपरोक्त मुद्दों से तैयार हुए माहौल के बीच पार्टी ने राज्य में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि हिंसा व घृणा किसी भी देश और समाज के लिए बेहद घातक हैं, लेकिन भारत में यह तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। हालत यह हो गई है कि गाली-गलौज और यहां तक कि बलात्कार की खुली धमकी को भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर उचित ठहरा रहे हैं। स्थिति दिनों-दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई अंकुश नहीं है।

सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर चलवा देने से दंगे के जख्म भर जाएंगे? सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही न आए कि दंगा-फसाद हो। लेकिन देखा यह जाता है कि दंगे और हादसे होने के बाद लाठी पीटी जाती है। सालों साल हो रहे दंगों से सरकारों ने अभी तक कोई सबक भी नहीं लिया है। क्या सरकार ने यह जानने की कभी कोशिश की है कि आखिर किसी एक समुदाय के त्यौहार पर दूसरे समुदाय के लोग इस तरह हमलावर कैसे हो जाते हैं। अगर वाकई सरकार ने इन तथ्यों पर होमवर्क किया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती।

बुलडोजर चलवाना समाधान नहीं

मप्र के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार ने दंगाईयों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया है। लेकिन यह समस्या का समाधान बिलकुल नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो साफ-साफ कह दिया है

खरगोन दंगे में जिनके घर जले, उनके घर सरकार बनाएगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन दंगे को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दंगे में जिन लोगों के घर जले हैं, उन्हें सरकार बनवाएगी। उन्होंने कहा कि किसी ने दंगा फैलाया, तो मामा छोड़ेगा नहीं। कुछ लोग हैं, जो गड़बड़ करते हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खरगोन में गरीबों के घर जल गए। उनमें अनुसूचित जाति के लोग भी थे। छोटे-छोटे मकान जला दिए। अब बताइए जिन्होंने घर जलाए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिनके घर जले हैं, वो चिंता नहीं करें। मामा फिर से घर बनाएगा। हम फिर से घर खड़ा करेंगे। जिन्होंने घर जलाए हैं, बाद में उनसे ही वसूल करूंगा। छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब दिग्विजय सिंह को उसमें भी दर्द होता है। कार्रवाई कैसे हो गई। झूठे फोटो पोस्ट कर रहे हैं। अरे झूठों कुछ तो शर्म करो। यह प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। लोगों को भड़का के शांति भंग करना चाहते हैं, ताकि अच्छे काम से लोगों का ध्यान हट जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार सबको सम्मान और सुरक्षा देगी। भाईचारा कायम रखिए। गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। त्योहार धूमधाम से मनाएं, लेकिन भाईचारे से मनाएं। आने वाले समय हनुमान जयंती, गुड फ्राइडे, ईद को प्रेम से मनाएं।

कि बुलडोजर चलवाने का अधिकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास नहीं है, बल्कि कोर्ट के पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारें बुलडोजर चलवाने का निर्णय कैसे ले लेती हैं। अगर वाकई दंगे-फसाद रोकने हैं तो अपराधियों पर नकेल कसने की जरूरत है। क्षेत्र में अपराधी प्रवृत्ति के कौन-कौन से लोग हैं, उनकी पूरी सूचना पुलिस के पास रहती है। अगर पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसकर रखे तो दंगा-फसाद होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि क्षेत्र के बदमाश या तो पुलिस के लिए कमाई का जरिया रहते हैं, या फिर नेताओं के लिए वोट का। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो सरकार कितना भी बुलडोजर चलाए अपराधियों के हौंसले पस्त होने वाले नहीं हैं।

दरअसल, शासन-प्रशासन के साथ आम आदमी भी दंगे-फसाद का आदी हो गया है। जब मामले ताजे रहते हैं तो उस पर बड़े-बड़े दावे और वादे किए जाते हैं और बाद में भुला दिया जाता है। अगर शासन-प्रशासन पहले से चुस्त-दुरुस्त रहे और अपराधियों पर नकेल कसे रहे तो घटना के बाद लाठी पीटने की नौबत नहीं आएगी। और न ही सरकार को बुलडोजर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर सुशासन की जगह वाहवाही लूटने का दौर चल रहा है। बड़े-बड़े मंचों से बुलडोजर चलाने का बखान किया जा रहा है। बैनर-पोस्टर लगाकर बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सरकार कितनी तत्पर है। फिर ऐसे में रामनवमीं या अन्य जुलूस पर हमले और पत्थरबाजी कैसे हो जाती है। सरकारों को सोचना चाहिए कि अपराध होने के बाद इस तरह की कार्रवाई का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता। सरकार की वाहवाही की न तो अब लोगों को कोई गरज है और न ही आगे रहेगी। उन्हें सुशासन चाहिए। दंगे-फसाद रोकना है तो शासन और प्रशासन को सालभर सख्त और सतर्क रहना चाहिए। वरना धार्मिक आयोजनों पर ऐसे ही पत्थर बरसते रहेंगे और सांप्रदायिक दंगों में देश-प्रदेश जलता रहेगा।

मुस्लिम समाज के आदर्श ही विवादित लोग

मुस्लिम समाज की त्रासदी यह है कि उसका एक तबका जाकिर नाइक जैसे मौलानाओं और ओवैसी जैसे नेताओं को आदर्श मानता है तो एक अन्य राणा अयूब, शरजील इमाम, उमर खालिद से प्रेरणा लेता है। वह एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, मेजर उस्मान, रहीम, रसखान और यहां तक कि मुगल शासकों में सबसे उदार माने गए अकबर तक को घास नहीं डालता। दारा शिकोह के बजाय उसे औरंगजेब सुहाता है। जो मुस्लिम अपने समाज की कट्टरता या फिर पिछड़ेपन के मजहबी कारणों के खिलाफ बोलते, लिखते या कुछ कहते हैं, उन्हें या तो सरकारी या फिर संघी मुसलमान करार दिया जाता है। हाल ही में उप्र में मंत्री बनाए गए दानिश आजाद अंसारी इसका ताजा उदाहरण हैं। निसंदेह एक त्रासदी यह भी है कि कट्टरता का जवाब कट्टरता से देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह खतरनाक है। यति नरसिंहानंद या फिर बजरंग नाम बदनाम करने वाला तथाकथित मुनि कम खतरनाक नहीं। इन्हें फ्रिंज एलीमेंट कहकर खारिज करने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जहरीले बयान बहुत बुरा असर डालते हैं और उन लोगों का काम आसान करते हैं, जो मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश में रहते हैं कि वे खतरे में हैं।

मालवा-निमाड़ में हुए हालिया सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं

- खरगोन में रामनवमीं के दिन निकल रहे जुलूस में डीजे बजाए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और जमकर पत्थरबाजी हुई पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े तो वहीं पेट्रोल पंप का भी भरपूर उपयोग किया गया। कई घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई। अब तक लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, 15 डीएसपी सहित आरएएफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
- सितंबर 2021 में इंदौर के मुस्लिम बहुल बॉम्बे बाजार में मुस्लिम लिबास में दो लड़कियां एक आदमी के साथ देखी गईं। कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उनसे पहचान पत्र दिखाने की मांग की। पहचान पत्र से पता चला कि वह लड़कियां हिंदू थीं, उनके साथ का पुरुष भी हिंदू था। इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया।
- अगस्त 2021 में इंदौर इलाके में एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के में प्यार हो गया था। समाज के बंधनों के डर से दोनों भाग गए थे। इस घटना को सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से शेयर किया गया था। इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय में बेहद नाराजगी थी।
- अगस्त 2021 में उप्र के हरदोई का रहने वाला तस्लीम चूड़ियां बेचने के लिए इंदौर आता था। वह हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेचता था। इंदौर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि वह व्यक्ति हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेचता था। मंत्री के मुताबिक चूड़ी बेचने वाले के पास से दो फर्जी आधारकार्ड भी मिले थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर खूब चर्चा हुई थी।
- 2020 में महाकाल मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध उज्जैन में भी 25 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों की रैली के दौरान हिंसा हुई थी। 25 दिसंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली पर हुए पथराव के बाद 18 लोगों को अरेस्ट किया गया था। मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि भारत माता मंदिर की तरफ जा रही रैली के दौरान हिंदूवादी युवाओं ने बेगमबाग के सामने रुककर हंगामा किया, खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। इसके बाद मुसलमान बस्ती के लोगों ने रैली पर पथराव किया।
- दिसंबर 2020 में राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के लिए मंदसौर में रैली निकाली गई। आरोप लगे कि इस दौरान मुसलमानों के धार्मिक स्थल और घरों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इस संबंध में 9 लोगों को अरेस्ट किया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।
- मालवा क्षेत्र के तीन जिले उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में पिछले डेढ़-दो साल में सांप्रदायिक हिंसा की छोटी बड़ी 12 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। 2021 में इस तरह की सबसे पहली सांप्रदायिक हिंसा 25 दिसंबर को उज्जैन के बेगमबाग इलाके में हुई थी। 29 दिसंबर को इंदौर के चांदनखेड़ी और मंदसौर के डोराना गांव में रैली के दौरान माहौल खराब हुए। इंदौर के स्कीम 71 के सेक्टर-डी और राजगढ़ के जीरापुर में निकाली गई रैली में हालात बिगड़े। ये दोनों घटनाएं रैलियों के मुस्लिमों बहुल इलाकों से गुजरने के दौरान हुईं।

दंगे के पीछे पीएफआई तो नहीं

मप्र सहित देशभर में जिस तरह एक ही तरीके से रामनवमीं के दिन दंगे हुए हैं, उससे आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ तो नहीं है। प्रदेश में सुरक्षा एजेंसी के रडार पर अब विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी आ गया है। इस संगठन से खरगोन हिंसा के कनेक्शन की जांच भी चल रही है। सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस ने पीएफआई की मप्र में सक्रियता बढ़ने पर सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। अब सरकार जल्द इस संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। इसका गठन 2006 में केरल में हुआ और उसका मुख्यालय दिल्ली में बताया जाता है। खरगोन में हुई हिंसा के बाद आरोप लगे कि इसके लिए फंडिंग पीएफआई ने की थी। इन आरोपों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसके कनेक्शन की जांच शुरू की। हाल ही में मप्र भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोप लगाया था कि पीएफआई ने खरगोन में आगजनी और पथराव के लिए फंड दिया था। प्रदेश में पीएफआई तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस संगठन से प्रदेश को बड़ा खतरा भी बताया जा रहा है। इस पर सिमी से कनेक्शन के आरोप भी लगे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में पीएफआई के 650 से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस संगठन का इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, खरगोन सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में नेटवर्क है। सूत्रों के अनुसार खरगोन हिंसा से तार जोड़ने के साथ प्रदेश में बढ़ रही संगठन की सक्रियता की वजह से इंटेलिजेंस के कान भी खड़े हो गए हैं। उसने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर अब जल्द ही संगठन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर सकती है। इस संगठन की कई अलग-अलग शाखाएं हैं। महिलाओं के लिए नेशनल वीमेंस फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हैं। सूत्रों के अनुसार इन संगठनों के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। रिटायर्ड डीजीपी आरएलएस यादव ने कहा कि हमारा समाज लड़ना नहीं चाहता है, कोई लड़ाना चाहता है। हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है। ये संस्कृति एक साथ रहने की, अच्छा व्यवहार करने की और एक-दूसरे के धर्म को मानने की है। इसके पीछे कुछ लोग और संगठन हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं। यह स्थानीय कारणों से नहीं हो रहा है। यह देश के लिए बड़ा षड्यंत्र है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में दूसरे देश नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। उन्हें लगता है कि उनका सामान फिर कौन खरीदेगा। अंग्रेजों के समय से स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं। ये लोग हथियार नहीं चलाते बल्कि लोगों को भड़काते हैं। उनमें जहर घोलते हैं। पूरे देश में कई वर्षों से शांति थी, लेकिन अब झगड़े शुरू हो गए हैं। इसमें जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस की है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए।

द कश्मीर फाइल्स पर विवाद

इस पर गौर करें कि द कश्मीर फाइल्स के बहाने कश्मीरी पंडितों के दमन और उत्पीड़न का जो सवाल उभरा था, उसे किस तरह यह स्वरूप दे दिया गया कि इस फिल्म के जरिए समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। आज कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल नेपथ्य में है और यह प्रश्न सतह पर कि क्या कश्मीर में मुस्लिम नहीं मारे गए? निसंदेह मारे गए और बड़ी संख्या में मारे गए, लेकिन क्या उसके लिए कश्मीरी पंडित जिम्मेदार थे? यदि देश में सचमुच गंगा-जमुनी तहजीब है तो फिर अयोध्या मामले का समाधान सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ा और क्या कारण है कि कई मुस्लिम नेता उसके फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं? आखिर जिन गंगा-जमुना का उद्गम स्थल एक ही स्थल हिमालय ही है और जिनका प्रयागराज में संगम हो जाता है, वे अलग-अलग तहजीब या संस्कृति की परिचायक कैसे हो सकती हैं? जैसे गंगा-जमुनी तहजीब सवालों के घेरे में है, वैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम... से दिया जाने वाला संदेश भी। क्या यह संदेश सचमुच ग्रहण किया गया? लक्ष्मण आचार्य के भजन रघुपति राघव राजाराम... में गांधीजी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम... की पंक्ति इस नेक इच्छा से जोड़ी थी कि हिंदू और मुस्लिम समाज को यह संदेश दिया जा सके कि ईश्वर-अल्लाह एक ही हैं, बस उनके नाम अलग हैं, लेकिन कई मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। यह स्थिति अभी भी है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं को जब कभी जय श्रीराम नारे का जिक्र करना होता है तो वे जेएसआर कहना पसंद करते हैं। ऐसे नेताओं के लिए भारत माता की जय भी बीएमकेजे है। वंदे मातरम् को लेकर भी उनकी आपत्ति किसी से छिपी नहीं। यह भी कोई नई-अनोखी बात नहीं कि ऐसे मुसलमानों को धमकियां मिलती हैं और उनके खिलाफ फतवे जारी होते हैं, जो कभी सार्वजनिक रूप से जय श्रीराम या फिर भारत माता की जय बोल देते हैं। अब तो यह स्थिति है कि भाजपा को वोट देने वाला मुस्लिम भी निंदा और कुछ मामलों में तो पिटाई, सामाजिक बहिष्कार का भी पात्र है। इस कहर से सेलेब्रिटी भी नहीं बच पाते। क्या यह किसी से छिपा है कि विभिन्न मौकों पर इरफान, सारा अली खान और मोहम्मद कैफ को किस तरह लांछित किया गया?

विपक्षी पार्टियां मौन

हैरत की बात यह है कि विभिन्न राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं व उन्मादी माहौल को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शांति व भाईचारे की अपील करते हुए एक ट्वीट किया, जबकि सपा नेता अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तृणमूल की मुखिया ममता बनर्जी समेत अन्य विपक्षी नेता खामोश हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता अलग बात है, लेकिन देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसमें अमन-चैन व भाईचारे के लिए इन पार्टियों के नेताओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि तक कुछ कदम का मार्च करना ही चाहिए था। यदि यह संभव नहीं था, तो कम से कम संयुक्त बयान तो

जारी ही किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

देश में तेजी से बढ़ रही हिंसा और घृणा के मसले पर विपक्षी दलों की उदासीनता समाज में भारी बेचैनी पैदा कर रही है। इस खामोशी के बहुत सारे मतलब भी निकाले जा रहे हैं। हद तो यह है कि जब विभिन्न शहरों में हिंसक झड़प हो रही थी, तो कांग्रेस और बसपा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त दिखे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव उप्र में होने वाली आपराधिक घटनाओं की खबरें ट्वीट कर रहे थे। वे शायद अपने राजनीतिक कैरियर में दूसरी बार बड़ी गलती कर रहे हैं। वर्ष 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो अखिलेश उप्र के मुख्यमंत्री थे और उस समय दंगा भड़काने वालों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी, वह उन्होंने नहीं की थी। अब यह दूसरा मौका है, जब जनता ने उन्हें प्रदेश में मजबूत विपक्ष बनाया है तो भी वे खामोश हैं। क्या 'भाईचारा' और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे सिर्फ चुनाव के लिए थे?

भाईचारे को किसकी नजर

पिछले 7 सालों से देशभर में शांति और भाईचारे का माहौल था। ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाईचारा दुश्मनी में बदल गया है। रामनवमीं के जुलूस के दौरान आधा दर्जन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा चौंकाने वाली है। जेएनयू में खाने की पसंद को लेकर हुई झड़प भी हालात के बिगड़ने का एक और संकेत है। यह भारत की छवि को धूमिल करता है और इसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर प्रभाव डालता है। श्रीराम सेना के खिलाफ कर्नाटक सरकार की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं होगा अगर यह महज दिखावा भर हो। इस बार भारत में हमने रामनवमीं कैसे मनाई? हमने रामनवमीं को रावणनवमीं में बदल दिया। देश के कई शहरों और गांवों में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से भिड़ गए। यहां तक की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, जिन्हें देश में अत्यंत प्रबुद्ध माना जाता है, वे भी आपस में भिड़ गए। कई शहरों में लाठियां, ईंट और गोलियां भी चलीं। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की ज्यादती के भी शिकार हुए। यह सब हुआ है, उसके जन्मदिन पर, जिसे अल्लामा इकबाल ने 'इमामे हिंद' कहा है। इकबाल का शेर है- है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज। अहले-नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद!! राम को भगवान भी कहा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भी। लेकिन राम के नाम पर कौनसी मर्यादा रखी गई? राम को सांप्रदायिकता के कीचड़ में घसीट लिया गया। इसके लिए हमारे देश के वामपंथी और दक्षिणपंथी तथा हिंदू और मुसलमान, दोनों जिम्मेदार हैं। यदि रामनवमीं का उत्सव मना रहे

दिग्विजय-विजयवर्गीय का ट्वीट विवादित

खरगोन में भड़की हिंसा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विवादित ट्वीट कर विवाद में फंस गए हैं। अपने बयानों से कई बार विवाद पैदा करने वाले कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह ने बिहार का एक फोटो शेयर कर उसे खरगोन का बताया था। हालांकि गलती का अहसास होते ही खुद दिग्विजय सिंह ने उसे हटा दिया। दूसरी तरफ भाजपा लगातार उन्हें घेरने में लगी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदेश का माहौल खराब करने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले की धाराओं में कई शहरों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अभी दिग्विजय सिंह का मामला थमा भी नहीं है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि ये है खरगोन में चाचा जान दिग्विजय सिंह के शांतिदूत, पुलिस इन पर कार्रवाई ना करे तो क्या करे। आस्तीन के सांप कोई भी हो फन कुचलना जरूरी है। वीडियो में एक मुस्लिम युवक कह रहा है कि 4 गाड़ियां हमारे एरिया में हैं, हम जरा कुछ करें तो तहलका मचा देते हैं ये लोग। इतना डर काफी है तुम्हारे लोगों के लिए। समझ गए न। जबकि वह तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित स्टार होटल के सामने बना यह वीडियो 2019 का है।

पूजा-पाठी छात्र कह रहे हैं कि पूजा-स्थल के तंबू के पास ही छात्रावास में मांस पकाया और खिलाया जा रहा है तो उससे हमें दुर्गंध आती है तो उनका दिल रखते हुए मांसाहार कहीं और भी उस समय करवाया जा सकता था और यदि मांसाहारी छात्र चाहते तो पूजा के घंटे भर पहले या बाद में भी भोजन कर सकते थे लेकिन यह झगड़ा तो न राम से संबंधित था और न ही मांसाहार से! इसके मूल में संकीर्ण राजनीति थी। वामपंथ और दक्षिणपंथ की!

मांसाहार का समर्थन करने वालों में हिंदू छात्र भी थे। हिंदू मांसाहारी तो अपना औचित्य ठहराने के लिए भवभूति के ग्रंथ 'उत्तरराम चरित्रम', प्रसिद्ध तांत्रिक मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ और चार्वाक के मद्यं, मांसं, मीनश्च, मुद्रा, मैथुनमेव च श्लोक तथा उपनिषदों के कई प्रकरणों को भी उद्धृत कर डालते हैं। वे वेदमंत्रों के भी मनमाने अर्थ लगा डालते हैं लेकिन वे वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के उन तथ्यों और तर्कों को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते कि मांसाहार स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए घाटे का सौदा है। इसी तरह कुछ शहरों में मंदिरों और मस्जिदों के आगे भी बम फोड़े गए, पत्थर मारे गए और गोलियां तक चलीं। आप क्या समझते हैं कि यह काम किसी सच्चे ईश्वरभक्त या अल्लाह के बंदे का हो सकता है? बिल्कुल नहीं! यदि कोई सच्चा ईश्वरभक्त या अल्लाह का बंदा है तो उसके लिए ईश्वर और अल्लाह अलग-अलग कैसे हो सकते हैं? वह तो एक ही है। बस, उसकी भक्ति के रूप अलग-अलग हैं। ये रूप देश-काल और परिस्थितियों से तय होते हैं। यदि सारे विश्व में देश-काल और परिस्थितियां एक-जैसी होतीं तो इतने सारे धर्म, मजहब, रिलीजन होते ही नहीं। इस विविधता को धर्मांध लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए वे रामनवमीं को रावणनवमीं बना डालते हैं।

कर्ज लेकर घी पी रहे राज्य

कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होने वाला

देश का हर अर्थशास्त्री यह बात लगातार कहता रहा कि कृषि कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होने वाला और इससे बैंकिंग तंत्र भी ध्वस्त हो जाता है। इसी से समझा जा सकता है कि कृषि कर्ज माफी कितना बड़ा चुनावी कार्यक्रम था और इससे किसानों का कतई भला नहीं होता था। वरना तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम तो खुश होते कि इस पर तीन प्रश्न ही क्यों, पूरा साक्षात्कार ही इसी पर होना चाहिए। कृषि कर्ज माफी की ही तरह ढेर सारे ऐसे लोक लुभावन ऐलान चुनावी लड़ाई जीतने के लिए नेता कर जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव राज्य के खजाने पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले मुफ्त दिले बेरहम वाली राजनीति को काफी हद तक काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन यह जिन्न एक बार फिर बाहर निकलता दिख रहा है। कुछ भारतीय राज्यों के हालात श्रीलंका जैसे बन सकते हैं, यह केवल सचिवों की चिंता नहीं है। एक ऐसा भयावह सच है, जिसमें सुधार न हुआ तो उस खतरनाक सच का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा।

प्राचीन भारतीय दार्शनिक चार्वाक का एक दर्शन सूत्र है, जिसका उल्लेख बहुतायत भारतीय गाहे-बगाहे करते ही रहते हैं या सुना तो लगभग सबने होगा। याव जीवेत सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। यानी एक बार मृत्यु हो गई तो श्मशान में जलकर राख ही हो जाना है तो जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। अब चार्वाक का यह दर्शन व्यक्ति के तौर पर हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए प्रेरक हो जाए, लेकिन किसी समाज या राष्ट्र के लिए यह दर्शन कतई प्रेरक नहीं हो सकता, क्योंकि समाज या राष्ट्र की आयु नहीं होती।

प्रधानमंत्री के साथ देश की अलग-अलग योजनाओं पर चर्चा, समीक्षा, सुधार की बैठक में करीब दो दर्जन सचिवों ने कहा कि कर्ज लेकर घी पीने वाली प्रवृत्ति से देश के कई प्रदेश बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। देश के वरिष्ठ सचिवों की राज्यों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर व्यक्त की गई चिंता यूं ही नहीं है। उप्र में कांग्रेस कहीं किसी लड़ाई में दूर-दूर तक नहीं थी, लेकिन ढेर सारी नौकरियों से शुरुआत करके मुफ्त स्कूटी, बिजली और ढेर सारे लुभावने वादों का दिवास्वप्न दिखाने में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस पीछे नहीं रही। कमाल की बात यह भी थी कि यही कांग्रेस पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी से पूछ रही थी कि महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने के लिए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए रकम कहां से लाएगी।

गोवा में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस भी किसी लड़ाई में भले नहीं थी, लेकिन चुनाव के समय भला कौन किसी पार्टी की दावेदारी खारिज कर सकता है। इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई। सरकार आई तो लगा कि सरकार में आने के लिए अपने वादों को मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरा करेंगे, लेकिन वादों को पूरा करने के बजाय भगवंत मान दिल्ली आए और प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य के लिए अगले दो वर्षों तक 50 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की मांग कर डाली। जबकि चुनावों के दौरान भगवंत मान बार-बार यही कह रहे थे कि राज्य में पैसे की कमी नहीं है, बस माफियाओं के खजाने का मुंह सरकारी खजाने की ओर मोड़ना है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को दूसरे नेता बार-बार याद दिला रहे थे कि कर्ज के मामले में पंजाब के हालात देश में सबसे ऊपर हैं। कर्ज और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के मामले में सबसे खराब हालात पंजाब के हैं। राज्य में कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 53.3 प्रतिशत है। इसके बाद राजस्थान 39.8, बंगाल 38.8, केरल 38.3 और आंध्र प्रदेश का अनुपात 37.7 प्रतिशत है। राज्य की इतनी खराब आर्थिक स्थिति होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने माले मुफ्त दिले बेरहम वाली राजनीति ही की।

पंजाब ही नहीं, कर्ज में डूबे कई अन्य राज्य जैसे राजस्थान, बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश केंद्र से मिल रहे अनुदान के ही भरोसे चल पा रहे हैं। कमाल की बात यह भी है कि कोरोनावायरस के संकट काल में भी राज्य अपनी आर्थिक संरचना दुरुस्त करने को तैयार नहीं हैं। केरल में एक अनोखा मामला सामने आया कि केरल की वामपंथी सरकार अपने कैडर को पीए, पीएम जैसी नियुक्ति पर दो साल के लिए रखती है और फिर उन्हें पेंशन का हकदार बनाकर त्यागपत्र दिलाकर पार्टी के लिए काम करने पर लगा देती है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान नहीं होते तो शायद यह देश के सामने आ ही नहीं पाता। कोरोनाकाल में देश के 31 में से 21 प्रदेशों का कर्ज और घरेलू उत्पाद का अनुपात आधा प्रतिशत से 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। यह चिंताजनक स्थिति है, जिसकी बात देश के वरिष्ठ सचिवों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की।

यह अच्छी बात है कि देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल महाराष्ट्र और गुजरात ने कर्ज और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात संभाल रखा है। महाराष्ट्र 20 प्रतिशत और गुजरात 23 प्रतिशत अनुपात के साथ एनके सिंह की अगुवाई वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम समिति की शर्तों के लिहाज से आर्थिक संरचना दुरुस्त कर रखी है। राजकोषीय घाटे के प्रबंधन और उसमें पारदर्शिता के लिए इसे 2003 में लाया गया था, लेकिन तय अवधि के लक्ष्य न तय कर पाने से इसका कोई लाभ नहीं हुआ। वर्ष 2016 में एनके सिंह की अगुवाई में समीक्षा की गई कि तय किए गए लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हैं या नहीं। वर्ष 2021 में इस समिति ने लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए हैं।

ऐसे में जब राज्य आर्थिक संरचना दुरुस्त करने के बजाय माले मुफ्त दिले बेरहम वाले अंदाज में अनाप-शनाप मुफ्त की घोषणा करते हैं तो आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से बिगड़ते हालात को दुरुस्त करना दूभर होने लगता है। लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए चुनाव जीतने की एक कोशिश कृषि कर्जमाफी और सब्सिडी के जरिए भी होती थी। वर्ष 2008 के बजट में तत्कालीन यूपीए सरकार के वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कृषि कर्ज माफी का सबसे बड़ा ऐलान किया। बजट के बाद वित्तमंत्री लगभग सभी टीवी चैनलों को साक्षात्कार देकर बजट के बारे में बताते हैं।

● **कुमार विनोद**

आखिर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? कई जानकारों के अलावा अब पार्टी के भीतर भी इसके लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह निष्कर्ष सच तो है, किंतु यही पूरी सच्चाई नहीं। क्या इस संदर्भ में केवल गांधी परिवार को ही दोषारोपित करना उचित होगा? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। राहुल गांधी परोक्ष रूप से पार्टी के निर्णायक फैसले ले रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा उप्र में कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार नहीं कर पाईं।

कांग्रेस की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है?

करीब 8 साल पहले देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस आज संकट के मुहाने पर खड़ी है। कांग्रेस की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? जानकारों के अनुसार परिवारवाद कांग्रेस की समस्याओं की जड़ है तो उसके बीज भी पार्टी ने ही बोए थे। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के दौर में हो गई थी। परिणामस्वरूप विगत साढ़े सात दशकों में एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गांधी परिवार ही काबिज रहा है। इसमें पिछले ढाई दशकों के दौरान पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसकती ही गई। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन से ही पार्टी का कायाकल्प संभव है?

हाल के वर्षों का राजनीतिक रुझान दर्शाता है कि जहां भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंची, वहां वह दोबारा नहीं उभर पाई। दिल्ली इसका सबसे ताजा उदाहरण है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही अब दो ऐसे राज्य हैं, जहां कांग्रेस की अपने दम पर सरकार बची है। राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या सिमटकर 33 रह गई है। अपने आरंभिक काल में कांग्रेस में विविध विचारधारा वालों के लिए स्थान था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और गांधीजी, ये सभी भारत की सनातन संस्कृति से प्रेरणा पाते थे। गांधीजी की नृशंस हत्या के बाद जब कांग्रेस पर नेहरू का एकाधिकार हुआ, तो पार्टी के मूल सनातनी और बहुलतावादी चरित्र को धीरे-धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। इसमें रही-सही कसर इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी। 1969 में जब कांग्रेस दो फाड़ हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आई, तब संसद में उन्हें अपनी सरकार बचाने हेतु 41 सांसदों की आवश्यकता थी। इस कमी को वामपंथियों ने बाहरी समर्थन देकर पूरा किया। इंदिरा ने उन कम्युनिस्टों के सहारे अपनी सरकार बचाई, जिनका अपने उद्भव काल से एकमात्र एजेंडा भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली पर प्रहार करना रहा। अपने इसी दर्शन के कारण वामपंथियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। गांधीजी, **नेताजी आदि** देशभक्तों को अपशब्द कहे। पाकिस्तान के जन्म में मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ मिलकर महती भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता को अस्वीकार करके उसे 17 देशों का समूह माना। 1948 में भारतीय सेना के खिलाफ हैदराबाद के जिहादी रजाकरों के साथ, तो 1962 के भारत-चीन युद्ध में वैचारिक समानता के कारण चीन के पक्ष में खड़े रहे। इसके अतिरिक्त, 1967 में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवाद को जन्म दिया।

जब 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, तब तमाम वामपंथी न केवल कांग्रेस में शामिल हुए, बल्कि उन्हें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। इसी दौर में कांग्रेस ने अपनी मूल गांधीवादी विचारधारा को वामपंथियों को आउटसोर्स कर दिया, जो अब भी उससे केंचुली की भांति चिपकी हुई है। कांग्रेस का सार्वजनिक-व्यवहार उस घिसे-पिटे वामपंथी व्याकरण से निर्धारित हो रहा है, जिसमें उसका भी कोई दृढ़ विश्वास नहीं है। कांग्रेस ऐसा केवल इसलिए करने को विवश है, क्योंकि विचारधारा के मामले में वह पहले ही शून्य हो चुकी है। मैकाले चश्मा पहनी कांग्रेस जाने-अनजाने में तभी से वामपंथियों के साथ मुस्लिम लीग के अधूरे एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। वह चाहे देश पर आपातकाल थोपना हो या शाहबानो मामले में मुस्लिम समाज में सुधार के प्रयासों को रोकना हो, परमाणु परीक्षण का विरोध करना हो या **भगवान श्रीराम** को काल्पनिक बताना हो, उनमें कांग्रेस की हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता प्रत्यक्ष होती है। मानो इतना ही काफी नहीं। 2005-2011 के बीच केवल हिंदुओं को लक्षित करता सांप्रदायिक एवं लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम लाया गया। जेएनयू परिसर में भारत विरोधी नारों का समर्थन करने से लेकर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह किया गया। ऐसे अंतहीन उदाहरणों की सूची लंबी है।

यदि कांग्रेस के सिकुड़ते जनाधार के लिए केवल गांधी परिवार ही जिम्मेदार है, तो क्या यह

कांग्रेस के पास अभी भी 20 प्रतिशत वोट

पता नहीं कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करेगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि देश के लोकतंत्र के लिए इस पार्टी का पुनर्जीवन आवश्यक है। कांग्रेस के पास अभी भी लगभग 20 प्रतिशत वोट हैं। कांग्रेस का फिर से उद्धार वही नेता कर सकता है, जो आम जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम कर सके। फिलहाल कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता। पंजाब गंवाने के बाद जिन दो राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, उनमें से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार की कृपा पर आश्रित हैं। उनके लिए सचिन पायलट की चुनौती का सामना करना कठिन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य से बाहर कोई जनाधार नहीं रखते।

सत्य नहीं कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे आदि ने हिंदू/भगवा आतंकवाद का हौवा खड़ाकर वामपंथी एजेंडे के अनुरूप विमर्श नहीं गढ़ा था? क्या सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर के खिलाफ पैरवी करने वालों में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल नहीं थे? क्या स्वदेशी कोविड-19 रोधी टीके की दक्षता पर सवाल उठाने वालों में शशि थरूर जैसे कांग्रेस नेता अग्रणी नहीं थे? द कश्मीर फाइल्स का विरोध करते हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को प्रोपेगंडा और हत्याओं के आंकड़ों को फर्जी बताने की शुरुआत क्या कांग्रेस की केरल इकाई ने नहीं की?

मई 2014 में मिली करारी हार की पड़ताल के लिए गठित एके एंटनी समिति ने भी माना था कि पार्टी की छवि हिंदू विरोधी हो गई है। इसके बाद आधे-अधूरे मन से कांग्रेस ने अपनी इस गलती का सुधार बहुत भोंडेपन के साथ किया। एक ओर चुनाव प्रचार में पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिर-मंदिर घूमकर स्वयं को सच्चा हिंदू स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर उनके कार्यकर्ताओं ने केरल में सरेआम गाय के बछड़े को मारा। स्वाभाविक है कि इससे पार्टी को न ही कोई वांछनीय फल मिला और न ही जनमानस प्रभावित हुआ।

5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही इसके आसार उभरे कि कांग्रेस की शर्मनाक हार के लिए गांधी परिवार पर अंगुलियां उठेंगी, वैसे ही कई कांग्रेस नेता परिवार के बचाव में आ गए। इसी कारण सोनिया गांधी की ओर से नेतृत्व छोड़ने की पेशकश करते ही चाटुकार कांग्रेस नेताओं में उनमें आस्था जताने की होड़ मच गई। गांधी परिवार ने 5 राज्यों में हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय जिस तरह इन राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से त्यागपत्र मांग लिए, उससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि परिवार पार्टी पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। अभी यह कहना कठिन है कि कांग्रेस को संचालित करने के तौर-तरीकों से नाखुश जी-23 समूह के नेताओं ने जो दबाव बनाया हुआ है, वह कुछ रंग लाएगा या नहीं, लेकिन यदि कांग्रेस इसी तरह चलती रही तो उसका कोई भविष्य नहीं। इस समूह के नेताओं में केवल कपिल सिब्बल ही हैं, जिन्होंने पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार से इतर अन्य किसी को सौंपने की मांग की है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी अभी भी उसी मनोदशा में हैं, जिसमें वे तब थे जब संप्रग सरकार सत्ता में थी।

यह ठीक है कि 2004 से लेकर 2014 तक सोनिया गांधी ने पर्दे के पीछे से मनमोहन सरकार को संचालित किया, लेकिन उसके बाद से हालात बहुत बदल चुके हैं। गांधी परिवार की भक्ति में डूबे कांग्रेस नेता यह समझने को तैयार नहीं कि संप्रग शासन के समय भी सोनिया गांधी कांग्रेस को जमीनी स्तर पर सशक्त नहीं कर पाईं। इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष बने, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ने में असफल साबित हुए। अध्यक्ष बनने के बाद तो वह और अधिक नाकाम रहे। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सोनिया गांधी ने भले ही राजनीतिक सक्रियता सीमित कर दी हो, लेकिन राहुल के प्रति अनुराग के कारण वह वैसे निर्णय नहीं ले पा रही हैं, जैसे आवश्यक हो चुके हैं। कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व से इतर कुछ सोच नहीं पा रही हैं। गांधी परिवार की चाटुकारिता कर रहे नेताओं को लगता है कि वे इस परिवार के बिना न तो चुनाव जीत सकते हैं और न ही एकजुट रह सकते हैं। इसी कारण वे सोनिया, राहुल और प्रियंका में ही अपना भविष्य देखते हैं, बिना यह समझे हुए कि आज के भारत की राजनीति और आम जनता की आकांक्षाएं बदल गई हैं। राहुल और प्रियंका में लगन और राजनीतिक समझ का भी अभाव है। कांग्रेस राहुल को अपनी सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में देख रही है, लेकिन उन्होंने यही साबित किया है कि उनकी पूरी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसने तक सीमित है। जब राहुल की यह राजनीति **आत्मघाती सिद्ध** हुई तो उन्होंने नरम हिंदुत्व की राह पकड़ी। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर पुराने ढर्रे पर आ गए। वास्तव में वह तब तक इसी तरह विफल होते रहेंगे, जब तक ऐसा कोई वैकल्पिक विचार सामने नहीं रखते, जो जनता को आकर्षित करे।

राहुल एक अनिच्छुक और अगंभीर नेता के रूप में सामने आते रहते हैं। उन्होंने सरकार में शामिल होने के मनमोहन सिंह के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। लोकसभा में सक्रियता नहीं दिखाई और एक बार तो एक अध्यादेश की प्रति सबके सामने फाड़कर मनमोहन सिंह को अपमानित किया। बीते 8 साल से विपक्षी नेता के रूप में वह कोई सार्थक भूमिका निभाने के बजाय खुद को गरीबों का मसीहा और मोदी सरकार को चंद उद्यमियों की सरकार बताने के अलावा और कुछ नहीं कर सके हैं। राहुल जैसा हाल प्रियंका गांधी का भी है, जिनमें एक समय इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती थी। उप्र के चुनाव में उनके कथित करिश्मे की पोल खुल गई।

● **विपिन कंधारी**

कांग्रेस का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं

लोकतंत्र के लिए यह शुभ नहीं कि कांग्रेस सरीखा राष्ट्रीय दल लगातार कमजोर होता जाए। उसकी कमजोरी का लाभ आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल उठा रहे हैं। कई क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर भाजपा को चुनौती तो देना चाहते हैं, लेकिन वे देश के समक्ष कोई ठोस एजेंडा नहीं रख पा रहे हैं। यदि सोनिया गांधी को कांग्रेस और देश की चिंता है तो उन्हें और उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी को राजनीति से किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि जो गांधी परिवार कभी कांग्रेस की ताकत हुआ करता था, वह अब उसके लिए बोझ बन गया है। सामंती सोच से ग्रस्त गांधी परिवार पार्टी के साथ-साथ देश को भी अपनी निजी जागीर की तरह समझने लगा है। गांधी परिवार को उद्धारक के रूप में देख रहे कांग्रेस नेताओं को यह समझना होगा कि देश की जनता परिवारवादी दलों से मुंह मोड़ रही है। कांग्रेस और अन्य परिवारवादी दल जितनी जल्दी यह समझ लें तो बेहतर होगा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए विष की तरह है।

5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस के साथ ही कई आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के कसकर बांध रखे गए दाम अब हमारी जेबें ढीली करने के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं, जबकि सरकार अपना यह भोथरा हो चुका तकनीकी तर्क फिर से रटने लगी है कि इनमें कम से कम डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस की मूल्यवृद्धि में अब उसकी कोई भूमिका ही नहीं है क्योंकि उनके निर्धारण का अधिकार तेल कंपनियों के पास है। तो, कई महानुभाव समझ नहीं पा रहे कि वे महंगाई के इस अलबेले त्रास को समझें तो किस तरह समझें?

मुफ्त की रेवड़ियों का बोझ

आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंचे श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए भारत के नौकरशाह अपने यहां भी कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंकाओं के प्रति क्रेंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं। नौकरशाहों को लगता है कि देश में नागरिकों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला बंद होना चाहिए लेकिन वोट की राजनीति ऐसा नहीं होने दे रही है।

नौकरशाहों को तो अब यह खतरे का अहसास हो रहा है लेकिन संभवत: न्यायपालिका ने करीब नौ साल पहले ही इस खतरे को भांप लिया था और उसने मुफ्त की सुविधाएं देने के वादे करने की राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए उचित कानून बनाने का सुझाव दिया था लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया क्योंकि सत्ता पर काबिज होना ही राजनीतिक दलों की प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री के साथ दो अप्रैल को हुई सचिवों की बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि राज्य सरकारें कर्ज लेकर मुफ्त की योजनाएं चला रही हैं और अगर इस ओर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो भारत में भी श्रीलंका जैसी स्थिति बन सकती है। अब तो ऐसा लगता है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दलों में मुफ्त की सुविधा देने के वादे करने की होड़ लग गई है और स्थिति यह है कि चुनाव के दौरान लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए मुफ्त बिजली पानी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा और हर महीने नकद राशि से लेकर ना-ना प्रकार के प्रलोभन मतदाताओं को देते हैं।

सत्ता में आने के बाद इन दलों के लिए इन वादों को पूरा करने के लिए धन की समस्या पेश आती है जैसा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में आप सरकार के सामने आ खड़ी हुई। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की खराब आर्थिक स्थिति की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री से हर साल 50,000 करोड़ की मदद मांगी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर अमल नहीं होने का मुद्दा राज्य में असंतोष का कारण बनने लगा है।

दिल्ली में भी **बिजली और पानी मुफ्त** प्रदान किया जा रहा है जबकि बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। मुफ्त में प्रदान की गई इन सेवाओं की वजह से दिल्ली का राजस्व भी प्रभावित हुआ है। बताते

उपभोक्तावाद को बढ़ावा

विडम्बना यह है कि विपक्षी दलों को, जो अब सत्ता दलों के नीतिगत नहीं बल्कि संख्या आधारित विपक्ष भर रह गए हैं, इस स्थिति से कोई असुविधा है तो सिर्फ यही कि वे इस उपभोक्तावाद में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे। फिर भी उनके सपने बरकरार हैं कि एक दिन अपनी विफलता को सफलता में बदल डालेंगे। यही कारण है कि केंद्र सरकार और भाजनपा ने मान लिया है कि अब विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद वह अगले चुनावों तक सुभीते से अपनी प्रजा को मूल्यवृद्धि के हवाले किए रह सकती है क्योंकि मतदान कर चुकने के बाद वह उन्हें फिलहाल कोई राजनीतिक नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में नहीं रह गई है। इस कारण प्रजा के तौर पर वह उनकी आज्ञाओं के अनुपालन के लिए ही होकर रह गई है और उसे समझा दिया गया है कि उनके द्वारा दी गई कई सहूलियतों की कृतज्ञ उपभोक्ता बने रहने में ही उसका भला है। इसीलिए सोशल मीडिया पर सरकार या महंगाई के समर्थकों के तर्क पढ़िए या कुतर्क, इन्हें इस हद तक पहुंचा दिए गए हैं कि अब महंगाई का मुद्दा उठाने या रोना रोते जाने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि चुनाव में मदाताओं ने उसे नोटिस में नहीं लिया और भाजपा उसको शिकस्त देकर चार राज्यों में चुनाव जीतकर वहां अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही है।

हैं कि इस समय दिल्ली जल बोर्ड पर भी हजारों रुपए का कर्ज है। कमोवेश, कई अन्य राज्यों में भी बेरोजगारी भत्ता, किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और किसानों के बकाया बिल माफ करने की मांग जोर-शोर से उठती है। इस संबंध में देश के विभिन्न राज्यों में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की ओर भी सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कुछ राज्यों में इन मांगों पर विचार के बाद किसानों को एक निश्चित मात्रा में मुफ्त बिजली और उनके कर्ज माफी और बिजली के बिल माफी का सिलसिला शुरू हो गया है। निश्चित ही इस तरह की रियायतों का असर राज्य के राजस्व पर पड़ता है, लेकिन ऐसे वादे करते समय राजनीतिक दल राज्य की आर्थिक स्थिति का आंकलन नहीं करते हैं और बाद में पैसा नहीं होने का रोना रोते हैं।

बेहतर हो कि इस तरह की मुफ्त सुविधाओं के जाल में नागरिकों को उलझाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने की बजाय उनकी समस्याओं के निदान के लिए ठोस उपाय किए जाएं ताकि मुफ्त की सुविधा देने की वजह से राज्यों के राजस्व पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित नहीं हो। समस्या यही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति का आंकलन किए बगैर ही राजनीतिक दल मुफ्त सुविधाएं देने के वादे करते हैं और सत्ता में आने पर इन वादों को पूरा करने में असफल हो जाते हैं जो आगे चलकर कई बार अशांति और तनाव के कारण बन जाते हैं।

इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति पर न्यायपालिका लंबे समय से चिंता व्यक्त कर रही है। बल्कि न्यायपालिका की ओर से ही एक बार सुझाव दिया गया था कि इस तरह के अव्यावहारिक वादे करने वाला दल अगर सत्ता में आता है तो उसे इन वादों पर खर्च होने वाली राशि का एक हिस्सा स्वयं वहन करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तारूढ़ दलों द्वारा इस तरह के लोकलुभावन लेकिन आर्थिक रूप से अव्यावहारिक इन वादों को पूरा करने की वजह से राज्यों के विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। नागरिकों को सत्ता में आने पर मुफ्त की रेवड़ियां देने के वादों पर अंकुश लगाने

और उचित कानून बनाने पर विचार करने के लिए न्यायपालिका बार-बार केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को सुझाव भी दे रही है। लेकिन किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। निर्वाचन आयोग ऐसी दंतविहीन संस्था है जिसने आदर्श आचार संहिता में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वादे पर अंकुश लगाने के बारे में कुछ प्रावधान किए लेकिन वे ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और उसने 25 जनवरी, 2022 को अश्विनी कुमार उपाध्याय और यूनियन ऑफ इंडिया जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए थे। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा था कि रिकार्ड में पेश की गई सामग्री के सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद से यह मामला अभी तक सूचीबद्ध ही नहीं हुआ है। अब कंप्यूटर से तैयार होने वाली न्यायालय की 18 मई की कार्यसूची के लिए इसे दर्शाया गया है। यह सही है कि चुनावी वादे के रूप में मुफ्त की रेवड़ियां देने की घोषणा जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है लेकिन शीर्ष अदालत भी चुनावों में इस तरह से रेवड़ियां बांटने के वादे करने की प्रवृत्ति उचित नहीं समझता है।

शीर्ष अदालत ने तो इस प्रवृत्ति पर अंकुश पाने के लिए जुलाई, 2013 में एस. सुब्रमण्यम बालाजी और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाड और अन्य में इस संबंध में अलग से कानून बनाने का भी सुझाव दिया था लेकिन केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों ने इस समस्या पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। यही नहीं, हाल ही में न्यायपालिका ने **लोकलुभावन वादों** से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी की थी कि राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करते समय इनकी व्यावहारिकता और राज्य के राजस्व की स्थिति को भी ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रीलंका की गंभीर स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से नौकरशाहों ने कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को आगाह किया है, उसके मद्देनजर केंद्र सरकार अव्यावहारिक योजनाओं की घोषणाओं और मुफ्त में आर्थिक लाभ देने की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए शीर्ष अदालत के 9 साल पुराने न्यायिक सुझाव के अनुरूप उचित कानून बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे।

● **इन्द्र कुमार**

चुनावी घोषणाओं ने बढ़ाई महंगाई

गौर कीजिए, देश में दूध व खाद्य तेल वगैरह के दाम मतदान के फौरन बाद ही बढ़ चुके थे, जबकि होली जैसा त्यौहार सर पर था। अब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए संकट के बहाने डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस के दाम भी बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में एक झटके में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद कई शहरों में उसकी कीमत एक हजार के आसपास या पार पहुंच गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का जो सिलसिला चुनावी गहमागहमी वाले 137 दिनों के बाद शुरू हुआ है। इस बात की पूरी आशंका है कि वह इस साल के अंत में प्रस्तावित अगले विधानसभा चुनावों तक जारी रहे। उसके बाद 'राजनीतिक उपभोक्ताओं' को फिर से खुश करने की मजबूरी आ पड़े तो शायद वह थोड़ा थम जाए। इससे पहले डीजल की थोक खरीदारी में सीधे 25 रुपए लीटर की बढ़त कर दी गई थी। तब रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न स्थितियों को इसका कारण बताते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि इस वृद्धि का खुदरा कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जाहिर हो चुका है कि वह बात लोगों को गुमराह करने या झांसे में रखने मात्र के लिए कही गई और निरंतर शातिर व चालाक होते जा रहे राजनीतिक उपभोक्तावाद का नया नमूना थी।

बस्तर पर भाजपा की नजर

दिल्ली में कुर्सी का रास्ता उप्र से होकर गुजरता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में किसी राजनीतिक दल को सत्ता हासिल करनी है तो उसे बस्तर फतह करना जरूरी होता है। लेकिन बस्तर की आबोहवा कांग्रेस के पाले में बह रही है। इसलिए लगातार भाजपा के सीनियर लीडर बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं। उप्र समेत 5 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल के अंत में चुनाव प्रस्तावित हैं, लिहाजा भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा की रणनीति की बात करें, तो वह इस समय मैदानी इलाकों की जगह आदिवासी अंचलों में ज्यादा फोकस करती दिख रही है। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी के बस्तर में हो रहे लगातार दौरे इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा बस्तर के रास्ते सत्ता की चाबी तलाशने में लग चुकी है।

कहते हैं कि देश की राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए उप्र में किसी पार्टी के लिए जीत हासिल करना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में यह बात प्रचलित है कि राज्य की सत्ता की चाबी बस्तर से होकर निकलती है। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रदेश प्रभारी पद संभालने के बाद से भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री डी. पुरंदेश्वरी लगातार बस्तर के दौरे कर रही हैं। बीते कुछ दिनों में ही उन्होंने बस्तर के 2 बार दौरे कर लिए हैं। पुरंदेश्वरी सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर जैसे घोर नक्सल प्रभावित जिलों का दौरा करके बस्तर की सियासी फिजा को भांपने की कोशिश कर रही हैं। यह बात गौर करने योग्य है कि उनके बस्तर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ भाजपा का कोई भी दिग्गज नेता साथ नहीं होता है। जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बस्तर में कार्यकर्ताओं की जुबानी ही पार्टी की जमीनी स्थिति को जांचने में लगी हुई हैं। क्योंकि अगर उनके साथ प्रदेश का कोई बड़ा नेता होगा, तो शायद दबाव में कार्यकर्ता अपने मन की बात उनसे कह नहीं पाएंगे, इसलिए पुरंदेश्वरी ने साफ मना कर रखा है कि उनके साथ कोई बड़ा पदाधिकारी दौरे नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग भाजपा का गढ़ बना हुआ था। 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कब्जे में बस्तर संभाग की 12 में से 9 सीटें थी, 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 11 सीटें जीतीं। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाने लगा। इस बार बस्तर में कांग्रेस ने 12 विधानसभा सीटों में से 8 पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि भाजपा को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश पाने वाली कांग्रेस आज की स्थिति में बस्तर को पूरी तरह साध चुकी है। कांग्रेस के पास फिलहाल बस्तर की सभी 12 सीटें हैं।

छत्तीसगढ़ में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और स्थानीय स्तर पर भाजपा को कोई भी बड़ा नेता जमीनी स्तर पर मेहनत करता नजर नहीं आ रहा है। पुरंदेश्वरी इस बात को शायद बेहतर समझती हैं, इसलिए वह खुद ही मेहनत करने में जुट चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वह बस्तर में हो रही भाजपा की समीक्षा बैठकों में कार्यकर्ताओं से सीधे यह सवाल पूछ रही हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना क्यों करना पड़ा? और अगर चुनाव जीतना है, तो आगे क्या करना होगा?

इधर भाजपा के अचानक बस्तर में बेहद सक्रिय नजर आने से कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए हैं। बीजापुर सीट से कांग्रेस के विधायक विक्रम शाह मंडावी का कहना है कि भाजपा ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में शासन किया, इस दौरान बस्तर में आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, जिसे बस्तर की जनता भूली नहीं है। रमन सिंह सरकार ने प्रदेश में विकास की जगह भ्रष्टाचार किया था, जबकि कांग्रेस की सरकार का ध्यान पूरी तरह विकास पर ही केंद्रित है। पुरंदेश्वरी को भाजपा की हार का कारण समझ में आ जाना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी का कहना है कि भाजपा ने हाल ही में 4 राज्यों में जो सफलता पाई है, इसका फायदा बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जरूर मिलेगा।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि बस्तर पर जिस पार्टी ने फतह कर ली, छत्तीसगढ़ उसका है। राज्य गठन के समय बस्तर संभाग भाजपा का गढ़ माना जाता था। 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बस्तर संभाग की 12 में से 9 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन आज की स्थिति की बात की जाए तो बस्तर संभाग आज कांग्रेस का गढ़ हो गया है। 12 विधानसभा सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है। 15 साल सत्ता में रहे भाजपा बस्तर में क्यों अपनी पकड़ खोती जा रही है। यह भाजपा के लिए चिंता का विषय है।

● **अक्स ब्यूरो**

बस्तर संभाग में सीटों की स्थिति

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लगभग 18 महीने का समय बचा है। बस्तर के आदिवासी वोट बैंक पर प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों की नजर है। साल 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में 9 सीटों पर भाजपा काबिज थी। 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। 1 सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर में अपनी पकड़ बनाई और चुनावी नतीजों को पूरा उलट कर दिया। 2013 में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 4 सीटें भाजपा के हिस्से में आईं। साल 2018 में भी स्थिति लगभग यही रही कि 12 विधानसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1 सीट भाजपा की झोली में आई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा ही एक ऐसी सीट थी, जहां से भाजपा के भीमा मंडावी ने चुनाव जीता था। उन्होंने देवती कर्मा को 2,172 वोटों से हराया था। भीमा 4 महीने ही विधायक के तौर पर काम कर सके। 9 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से कुछ घंटे पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के 9 महीने बाद हुए उपचुनाव में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के पास आ गई।

पायलट और वसुंधरा की बैचेनी

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की खामोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बैचेनी से राज्य की सियासत में उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। सचिन पायलट की खामोशी को आने वाले तूफान का संकेत माना जा रहा है। बागी तेवरों के चलते पिछले साल उपमुख्यमंत्री के पद से हटाए गए सचिन पायलट दो साल से बिना किसी पद के हैं। कांग्रेस हाईकमान पायलट की खामोशी को समझ नहीं रहा है। खामोशी में सचिन पायलट की नाराजगी छिपी है। सचिन पायलट की खामोशी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा में भी कमोबेश कांग्रेस जैसे ही हालात हैं। भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत-पूनिया गुट आमने-सामने हैं।

राजस्थान में साल 2023 में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को एडजस्ट नहीं करता है तो कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस आलकमान के सामने सचिन पायलट को एडजस्ट करना चुनौती बना हुआ है। पायलट राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि मुख्यमंत्री गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति में सकिग्रय रहने की बात कहकर सचिन पायलट ने अपने इरादे साफ कर दिए है कि उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री का ही पद चाहिए। पिछले वर्ष बगावत के समय पायलट ने कांग्रेस महासचिव के पद को ठुकरा दिया था। पायलट मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़े हैं। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस **आलाकमान असमंजस** की स्थिति में है। गहलोत-पायलट गुट की खींचतान का नुकसान कांग्रेस को विधानसभा 2023 के चुनावों में उठाना पड़ सकता है। पांच राज्यों में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ को बचाना बड़ी चुनौती है। देश में सिर्फ दो ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट की हर बात को तवज्जों दे रहा है।

गहलोत कैबिनेट के फेरबदल में पायलट समर्थक विधायकों को शामिल किया गया। राजनीतिक नियुक्तियों में भी पायलट समर्थकों को पर्याप्त संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों को दिया गया है, लेकिन पायलट इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पायलट की नजर सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर टिकी है। मुख्यमंत्री पद से पायलट कोई समझौता करना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस रणनीतिकार गहलोत-पायलट की जिद की वजह से दुविधा की स्थिति में हैं। कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेता अपनी-अपनी जिद पर अड़े हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने पर सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को 14 जुलाई 2020 को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से ही पायलट के हाथ खाली हैं। हालांकि इस दौरान गहलोत और पायलट कैंप में सुलह भी हो गई। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने पायलट समर्थक विधायकों को मंत्री भी बना दिया। वहीं समर्थकों को बंपर राजनीतिक नियुक्तियां भी दी गई लेकिन पायलट के हाथ खाली रहे।

राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ही वसुंधरा गुट और शेखावत गुट में खींचतान चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर वसुंधरा समर्थकों की बयानबाजी से भाजपा की अंदरूनी खींचतान भी सड़क पर आ गई है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला संसदीय बोर्ड करता है। पूनिया के इस बयान को वसुंधरा राजे पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राज्य की राजनीति का मोह छोड़ने का अनुरोध किया था। आहूजा ने कहा कि वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। जबकि वसुंधरा समर्थक विधायक लगातार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वसुंधरा समर्थकों की मांग से भाजपा नेता असहज महसूस कर रहे हैं। अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन करने के बाद वसुंधरा राजे ने हाल में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए मेल मिलाप का दौर शुरू किया है। राज्य में जितने भी वसुंधरा विरोधी खेमे थे, उन सबने गोलबंदी कर ली थी और उन्हें किसी न किसी रूप में दिल्ली से ताकत भी मिल रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जब एक साल से भी कम वक्त बचा है तो केंद्रीय नेतृत्व इस नतीजे पर पहुंचता दिख रहा है कि वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखकर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

वसुंधरा से केंद्रीय नेतृत्व ने बढ़ाया संवाद

इसी के मद्देनजर केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे से संवाद बढ़ाया है। खुद प्रधानमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि तत्काल उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके लिए किसी बड़ी भूमिका की तलाश हो रही है, जिसके जरिए वसुंधरा की नाराजगी खत्म की जा सके और वह 2023 के चुनाव के लिए सक्रिय भागीदारी निभाएं। मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर राजस्थान में सचिन पायलट ने भी बगावत की थी। लेकिन पार्टी वहां अपनी सरकार बनाने वाला करिश्मा इसलिए नहीं दिखा पाई थी कि वसुंधरा राजे इस पूरे घटनाक्रम से अपने आपको अलग किए हुए थीं। 2018 के बाद से राज्य में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें अब तक भाजपा को सिर्फ एक पर ही जीत मिल पाई है। अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि सतीश पूनिया पर भरोसा महंगा भी पड़ सकता है।

राज ठाकरे का हिंदुत्व

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति दो चीजों पर केंद्रित होती है- एक मराठी मानुष और दूसरा कट्टर हिंदुत्व। मौका देखकर राज ठाकरे का फोकस बदलता भी रहता है। राज ठाकरे की ताजा दिलचस्पी हिंदुत्व की राजनीति में लग रही है, तभी तो मुस्लिमों को नए सिरे से टारगेट किया है। एमएनएस नेता की ताजा मांग है कि महाराष्ट्र सरकार आदेश जारी कर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटा दे। ऐसा न किए जाने पर राज ठाकरे ने धमकी दी है कि वो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे।

मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई राज ठाकरे की नई घोषणा का ट्रेलर भी मनसे दफ्तर में देखने को मिल चुका है। मनसे मुख्यालय परिसर में काफी ऊंचाई पर एक पेड़ पर लाउडस्पीकर लगाया गया और फिर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया गया। अपनी पब्लिक मीटिंग में राज ठाकरे ने कहा, मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं... आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउडस्पीकर हटाने पर फैसला लेना चाहिए... मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं... लाउडस्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को निशाना बनाने के लिए राज ठाकरे ने उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ तो की ही, लगे हाथ एनसीपी नेता शरद पवार को भी निशाना बनाया। फिर तो शिवसेना और एनसीपी से तगड़े रिएक्शन आने ही थे। राज ठाकरे के योगी सरकार की तारीफ करने पर शिवसेना को लगता है कि वो भाजपा के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश रहे हैं, लिहाजा संजय राउत ने एमएनएस नेता को भाजपा और शिवसेना के झगड़े से दूर रहने की सलाह दी है। शरद पवार तो राज ठाकरे की बातों को ये कहते हुए खारिज कर रहे हैं कि वो तो फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं ही नहीं।

राज ठाकरे ने शरद पवार पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एमएनएस नेता का कहना है कि 1999 में एनसीपी की स्थापना के बाद से महाराष्ट्र में जातिवाद को बढ़ावा मिला है और इसके लिए राज ठाकरे ने शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया है। राज ठाकरे का आरोप है कि शरद पवार ने जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है। और फिर जाति की राजनीति को राज ठाकरे हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। कहते हैं, अगर हम जाति की राजनीति से बाहर नहीं आते हैं तो फिर हिंदू कैसे बनेंगे? हिंदुत्व का कौनसा झंडा हम पकड़ेंगे?

अब सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे को ये राजनीतिक पाठ कहां से हासिल हो रहा है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉलिटिकल लाइन है जिसमें सभी जातियों को एकजुट करने की कोशिश होती है। एक कुआं, एक श्मशान और एक मंदिर का फॉर्मूला सुझाया जाता है, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं होता। उप्र चुनाव में संघ की तरफ से जमीनी स्तर पर जोरदार मुहिम चलाई गई थी और लोगों को सारी बातें भूलकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने के लिए समझाने की कोशिश की गई थी। एक तरफ संघ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे, नतीजा भी सामने आ गया। मायावती की बसपा महज एक सीट जीत सकी और अखिलेश यादव तमाम कोशिशों के बावजूद बहुमत से काफी दूर रह गए।

मोदी-योगी की बदौलत उप्र से जातीय राजनीति पर हिंदुत्व के हावी होने से संघ को काफी राहत मिली होगी और आगे की राजनीतिक मुहिम भी उसी हिसाब से तैयार की जाएगी, ऐसा लगता है। एनसीपी पर राज ठाकरे के हमले का काउंटर शरद पवार ने उनकी राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाकर किया है। शरद पवार ने राहुल गांधी और राज ठाकरे की राजनीति को एक ही तराजू पर तौल दिया है। याद रहे एक इंटरव्यू में शरद पवार का कहना था कि राहुल गांधी के अंदर राजनीतिक स्थिरता की कमी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे लोग मनसे के रूप में भी जानते हैं, के चुनावी प्रदर्शन को लेकर शरद पवार कहते हैं, राज ठाकरे की पार्टी लोगों से घुलती-मिलती नहीं है...उनका वोट शेयर इस बात का सबूत है। दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी के पास एक ही विधायक है।

● **बिन्दु माथुर**

भाजपा के लिए शिवसेना नहीं बन सकते राज ठाकरे

महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के विधायकों की तुलना छोड़ दें तो मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे भारी पड़ते हैं। इसलिए भी क्योंकि भाजपा के लिए अटैक करना मुश्किल होता है। जैसे उप्र और बिहार में भाजपा नेतृत्व अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को लेकर कुछ भी बोल देता है, महाराष्ट्र में जोखिम उठाने से पहले सौ बार सोचना पड़ता होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाजपा को महाराष्ट्र में एक गठबंधन पार्टनर की सख्त जरूरत है, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी शिवसेना का विकल्प बन पाएगी, ये कहना भी मुश्किल है। अभी तो ये असंभव ही लगता है, बाद की बात और है।

2006 में मनसे के गठन के बाद से राज ठाकरे का झुकाव और दुराव भी बदलता रहा है। 2019 के आम चुनाव से पहले राज ठाकरे महाराष्ट्र में घूम-घूम कर मोदी विरोधी मुहिम चला रहे थे। राज ठाकरे के मंच से स्क्रीन पर मोदी के पुराने भाषण दिखाए जाते और लोगों को ये समझाने की कोशिश होती कि मोदी कितना झूठ बोलते हैं। राज ठाकरे के रुख को चुनावों में उतरे कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन के पक्ष में माना गया और तब मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधे-सीधे बोल दिया था कि राज ठाकरे बारामती की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बारामती एनसीपी नेता शरद पवार का इलाका है।

योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर मिनिस्ट्री

देश की राजनीति में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर हो चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये नाम भाजपा ने नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था। लेकिन, अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि योगी आदित्यनाथ पर किया गया बाबा बुलडोजर का तंज उन पर ही भारी पड़ जाएगा। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा बुलडोजर के नाम को कुछ इस तरह भुनाया कि उप्र में योगी सरकार 2.0 का आगाज हो चुका है और, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट भी बांट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन मोड में आते हुए मंत्रियों को 100 दिनों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। इन सबके बीच ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप्र में एक अलग बुलडोजर मिनिस्ट्री बना दी है। क्योंकि, योगी सरकार 2.0 में भू-माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति पर गरज रहा बाबा का बुलडोजर इशारा तो यही कर रहा है।

उप्र विधानसभा चुनाव के दौरान बाबा का बुलडोजर कुछ ऐसा मशहूर हुआ है कि अब प्रशासन को अवैध निर्माण और कब्जे को तोड़ने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। बल्कि, लोग खुद से ही अर्जी देकर अपने अवैध कब्जे को तोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। रामपुर के शाहबाद में अवैध **कब्जों की जांच के लिए** पहुंचे एसडीएम के सामने युवक ने खुद ही अपने अवैध कब्जे को तोड़ने की अर्जी दी। दरअसल, क्षेत्र के मित्तरपुर अहरौला गांव के युवा किसान अहसान खां ने अपने अवैध तरीके से बने पुश्तैनी मकान समेत गांव के अन्य अवैध कब्जों को गिराने की शिकायत की थी। अहसान खां समेत कई लोगों का मकान तालाब की सरकारी जमीन पर बना था।

अगर उप्र प्रशासन का बुलडोजर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर चल रहा है, तो अपराधी पुलिसवालों पर भी बाबा का बुलडोजर वैसा ही कहर बरपा रहा है। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के लखनऊ में अवैध रूप से बने मकान पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। लखनऊ के चिनहट में मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह ने बिना नक्शा पास कराए तीन मंजिला भवन खड़ा कर लिया था। जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 900 वर्गफीट में बने इस अवैध निर्माण की कीमत करीब एक करोड़ थी। मनीष गुप्ता हत्याकांड में जगत नारायण सिंह को बर्खास्त किया जा चुका है और फिलहाल जेल में हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा का बुलडोजर किसी धर्म, जाति, पंथ के खिलाफ निशाना बनाकर चलाया जा रहा हो। उप्र प्रशासन का बुलडोजर हर उस भू-माफिया के खिलाफ चल रहा है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाला हो। फिर वह हिंदू हो या मुसलमान, इससे प्रशासन को फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्रूखाबाद में करीब चार दशक से कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर किए गए मकानों और कारखाने के निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। फर्रूखाबाद के श्याम नगर स्थित कब्रिस्तान के मुतबल्ली मो. हुसैन रिजवी को कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद कब्जा दिलाने के लिए उप्र प्रशासन ने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया। कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जेदारों कृष्ण कुमार और उनके भाई शिवम मकान बनाकर रह रहे थे और कारखाना भी चला रहे थे।

उप्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले कई नेताओं को लग रहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। खैर, उनका ये विश्वास धराशायी हुआ, तो उनमें से कुछ नेताओं ने खुद ही अपने अवैध निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में एटा के सपा नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की तूती बोलती थी। रसूख के दम पर इन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बहुतायत में अवैध निर्माण कराया था। लेकिन, योगी सरकार 2.0 में बदले तेवरों के आगे इनका रसूख भी ठंडा पड़ गया है। बाबा बुलडोजर का खौफ रामेश्वर सिंह यादव और जुगेंद्र सिंह यादव पर इस कदर हावी हुआ कि सालों से कर रखे अवैध निर्माण गिराने के लिए इन्होंने खुद ही लेबर लगवा दी। रामेश्वर के भतीजे विक्रांत यादव ने भी अवैध कब्जा करके बनाए गए अपने कोल्ड स्टोरेज को तुड़वा दिया है। बताना जरूरी है कि ये नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के रिश्तेदार हैं।

वैसे, बुलडोजर बाबा के नाम के साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि उप्र विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तक भाजपा और मुख्यमंत्री योगी भी सभाओं में इसका कुछ खास जिक्र नहीं करते थे। लेकिन, अखिलेश यादव के तंज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मैं भी चौकीदार जैसे कैंपेन में बदल दिया। एक वीडियो में मुख्यमंत्री योगी खुद अपनी चुनावी सभा में बुलडोजर दिखाते हुए नजर आए थे। वैसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड जीत ने कई अंधविश्वासों और मिथकों पर भी बुलडोजर चलाया था। और, बाबा का बुलडोजर जितनी तेजी से गरज रहा है, वो सीधे तौर पर एक नई बुलडोजर मिनिस्ट्री की ओर ही इशारा है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री

उप्र में अभी तक अपराधियों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब उप्र में डायनामाइट की एंट्री हो गई है। डायनामाइट के जरिए भू-माफिया के घरों को गिराया जाएगा। इसके लिए बाकयदा विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में डायनामाइट का प्रयोग ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में किया जाएगा। क्योंकि बड़ी मंजिलों को गिराने में बुलडोजर के दबने के साथ ही काफी समय बर्बाद होता है। लिहाजा अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके लिए भोपाल से टीम बुलाई जा रही है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी अक्षय त्रिपाठी के मुताबिक जो बिल्डिंग छोटी होती हैं, उन्हें बुलडोजर के जरिए आसानी से गिरा दिया जाता है। लेकिन बड़ी बिल्डिंग को गिराने में काफी समय लगता है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि अब इस काम के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा।

जंगलराज और सुशासन

नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन बाबू की छवि बना रखी है। लेकिन ये छवि इतनी नाजुक है कि श्रेष्ठता साबित करने के लिए हमेशा ही जंगलराज का नाम लेना ही पड़ता है। पहले चुनाव से लेकर 2020 तक। अब नीतीश कुमार को एक बार भी इतना भरोसा नहीं हुआ कि बगैर जंगलराज का नाम लेकर डराए वो सफल हो सकते हैं। बीते बिहार चुनाव में भी नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा दिलाने के लिए रांची जेल में बंद लालू यादव और राबड़ी देवी शासन की बार-बार याद दिलानी पड़ी थी और ये काम सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ऐसा ही करते रहे। भले ही ताली और थाली बजाकर लालू यादव का परिवार अपना विरोध प्रकट करता रहा। अंत भला तो सब भला - नीतीश कुमार ने यही बोलकर अपनी आखिरी चुनावी रैली खत्म की थी और तरह-तरह से समझाए जाने के बाद बिहार के लोगों ने आखिरकार जदयू नेता के सुशासन को ही तरजीह दी। भाजपा के मुकाबले जदयू की सीटें जरूर कम हो गईं, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने। लब्बोलुआब ये है कि ये सुशासन बाबू वाली ही नीतीश कुमार की छवि है जो उनका सरमाया है। भाजपा नेतृत्व भी बार-बार यही बताता रहा है कि बिहार में सुशासन नीतीश कुमार की बदौलत ही है और नीतीश कुमार का यही सबसे मजबूत पक्ष भी है जो अब तक उनको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए हुए है।

जंगलराज के लिए तेजस्वी यादव कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। निश्चित तौर पर एयरपोर्ट के मच्छर किसी को अगवा नहीं कर सकते या रनवे के ट्रैक्टर चालक सरेआम किसी को गोली नहीं मार देते, लेकिन राह चलते परेशान तो करते ही हैं। हां, सड़कें ज्यादातर शानदार हैं। मिलाजुला अनुभव भी ज्यादातर बेहतर हो तो बेहतरीन ही माना जाना चाहिए क्योंकि आदर्श स्थिति तो कुदरत भी नहीं दे पाती और हर व्यवस्था टीम वर्क का नतीजा होती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज पर भी ये चीज लागू होती है। ये तो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार की ताजा पारी काफी मुश्किलों भरी हो गई है क्योंकि भाजपा नेतृत्व ने चुनावों से पहले ही ये प्लान कर लिया था लेकिन ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार घबराहट में सारा फ्रस्टेशन इधर-उधर निकालने लगें। अब भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर शराबबंदी को भूलकर नीतीश कुमार चाहें तो सुशासन पर फोकस कर सामने खड़ी चुनौतियों से आराम से उबर सकते हैं।

शराबबंदी के आगे जहां और भी है!

मोदी सरकार की नोटबंदी और नीतीश सरकार की शराबबंदी में मामूली फर्क ही लगता है। दोनों ही के फायदे नुकसान अपनी जगह हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि नोटबंदी लागू करने से भी भाजपा को चुनावों में कोई नुकसान नहीं हुआ और नीतीश कुमार को शराबबंदी से चुनावी फायदा जरूर मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क नजर आता है वो ये कि भाजपा के किसी भी नेता के मुंह से अब नोटबंदी का नाम तक सुनने को नहीं मिलता और नीतीश कुमार हैं कि शराबबंदी को सही साबित करने के लिए पूरी जिंदगी की राजनीतिक कमाई ही दांव पर लगा देने पर आमादा देखे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार के सिद्धांत शुरू से एक जैसे ही रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी कहा करते थे कि जिसे पीना है पिए, जो पैसे मिलेंगे उसे उनकी सरकार लड़कियों को साइकिल बांटने में लगा देगी।

लेकिन नीतीश कुमार के हाल के बयानों से ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या नीतीश कुमार भूल चुके हैं कि सुशासन बाबू कहकर उनको ही संबोधित किया जाता है! हैरानी ठीक है, लेकिन अफवाह किसने फैलाई। नीतीश कुमार की बिहार से विदाई की खबरें मीडिया में आने पर जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने हैरानी जताई है। संजय झा के दावे के मुताबिक, ये सब शरारत भरी हरकत और अफवाह मात्र है। संजय झा ने अपनी ये हैरानी ट्विटर पर जताई है। वे लिखते हैं, मैं इस अफवाह से हैरान हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं... ये शरारत और सच्चाई से बहुत दूर है। बहुत अच्छी बात है। ये कहने और बताने का उनका हक है। लेकिन ट्वीट करने से पहले क्या संजय झा ने एक बार ये समझने की कोशिश की कि इस शरारत के पीछे कौन है? ये अफवाह फैलाई किसने है? ये तो नीतीश कुमार के मंत्री को भी मालूम होगा ही कि उनके मुख्यमंत्री ने ही अपने चेंबर में मीडिया के सवाल-जवाब के दौरान अपने मन की बात शेयर की थी। और नीतीश कुमार कोई जीतनराम मांझी जैसे मुख्यमंत्री तो हैं नहीं कि कुछ भी बोल देंगे।

नीतीश कुमार के ज्यादातर राजनीतिक संदेश तो ऐसे ही होते हैं। वो तो जब पटना में बाढ़ से लोग बेहाल होते हैं तब भी खामोशी अख्तियार कर आगे बढ़ जाते हैं। मीडिया के सवालों की परवाह तक नहीं करते। वरना, न पूछे जाने पर भी जातीय जनगणना जैसे अपने मनमाफिक मुद्दों पर अपडेट देते रहते हैं। आखिर किसलिए जदयू के नेता नीतीश कुमार को चाणक्य बताते रहते हैं? अब तक राज्यसभा सदस्य न होने की बात किसने कही थी? अगर नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा होता तो ये खबर बाहर कैसे आती? ये तो नीतीश कुमार पहले भी बताते रहे हैं कि कितनी मजबूरी में वो सरकार चला रहे हैं। शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तो नीतीश कुमार ने देर की वजह भी तो ऐसी ही बताई थी। नीतीश कुमार का कहना था कि जब उनके हाथ में सब होता रहा तो फटाफट कर देते रहे, लेकिन अब वो बात नहीं रही।

● **विनोद बक्सरी**

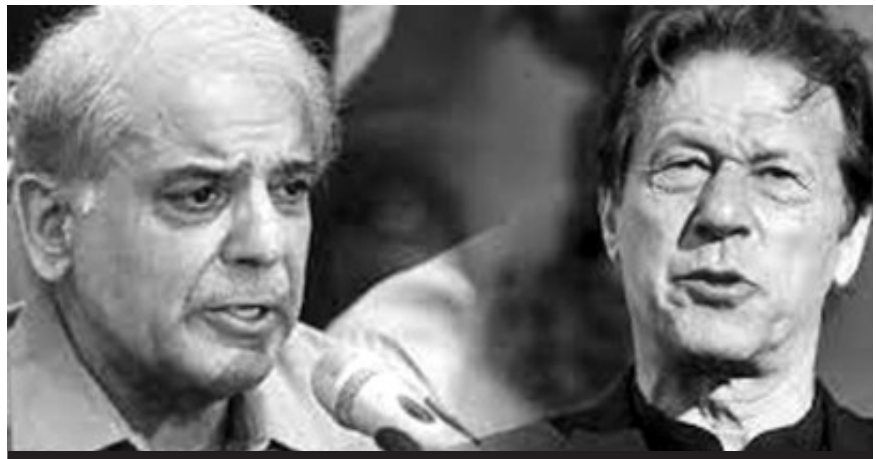

एक नई शुरुआत की उम्मीद

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही शाहबाज शरीफ ने अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत की पेशकश की और कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को हल करना चाहिए ताकि दोनों देश गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठा सके। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी शहबाज शरीफ को बधाई देने वाले वर्ल्ड लीडर्स की फेहरिस्त में सबसे ऊपर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। ताकि हम अपनी विकास से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के जवाब में शाहबाज शरीफ ने ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग-पूर्ण संबंध चाहता है।

कश्मीर का जिक्र करते हुए शाहबाज ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सहित सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान की कुर्बानी जगजाहिर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आइए शांति सुनिश्चित करें और अपने लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान दें। तीन बार पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ के सत्ता में आने से भारत-पाक रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। इमरान खान के दौर में भारत-पाकिस्तान रिश्तों में नई गिरावट देखी गई जिसमें 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय एयर स्ट्राइक और 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई का भारत का **मुंह तोड़ जवाब देना शामिल है।** वहीं 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते निचले स्तर पर चले गए। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी, वहीं पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को नई दिल्ली से वापस बुला लिया था। लेकिन अब पड़ोसी मुल्क में सत्ता के बदलाव के बाद एक नई शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। शाहबाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना का करीबी माना जाता है, और वहीं शरीफ को एक कुशल प्रशासक के तौर पर देखा जाता है। देखना यह भी दिलचस्प है कि पाकिस्तान में अगले साल चुनाव से पहले शहबाज शरीफ के रहते भारत-पाक संबंध कितने मजबूत हो सकते हैं। इमरान खान से अलग शाहबाज शरीफ का रवैया भारत के प्रति थोड़ा नरम रहा है। जहां इमरान खान लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे जुबानी हमले करते आए, वहीं शाहबाज शरीफ भी कश्मीर का मुद्दा उठाते आए हैं लेकिन उनका रवैया इमरान खान से जुदा रहा। शाहबाज शरीफ ने होली के मौके पर हिंदू समुदाय को बधाई दी, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हत्या पर भी वो चिंता जताते आए हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर भी जहां उन्होंने शोक जताया और कहा कि भारत ने ऐसा नेता खो दिया है जिसकी क्षेत्रीय शांति के लिए की गई सेवाओं को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं लता मंगेशकर के निधन पर भी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लता मंगेशकर के निधन से संगीत की दुनिया ने ऐसी गायिका को खो दिया है जिसने अपनी सुरीली आवाज से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। 2020 अगस्त में केरल में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश को लेकर भी शाहबाज शरीफ ने अफसोस जताया था। वहीं शाहबाज शरीफ ने कई बार भारत पर जुबानी हमला भी किया, जिसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद शाहबाज शरीफ ने भाजपा सरकार की निंदा की थी। वहीं भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर भी शहबाज शरीफ टिप्पणी करते आए हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर भी शाहबाज शरीफ ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी। गत दिनों पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मसले को हल किए बिना स्थाई शांति मुमकिन नहीं होगी। हालांकि पाकिस्तान की विदेश नीति में कश्मीर मुद्दा हमेशा बना रहेगा लेकिन शाहबाज शरीफ के चुने जाने से रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का एक नया मौका मिल सकता है।

पाकिस्तान के साथ रिश्तों में पिछले 1 साल में कुछ गर्माहट देखने को मिली है। पिछले साल फरवरी में दोनों देशों के बीच सीमा पर सीजफायर पर सहमति बनी, जो अभी भी बरकरार है। वहीं दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन को लेकर भी कदम उठाए गए हैं जिसमें करतारपुर कॉरिडोर का दोबारा खोला जाना, पाकिस्तान से श्रद्धालुओं का जत्था भारत आना और वैसाखी के मौके पर सिख श्रद्धालुओं के लिए पाकिस्तान उच्चायोग का वीजा जारी करना शामिल है। वहीं भारत से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन चावल भेजने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति हुई।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पाकिस्तान के सामने एक बड़ा मौका

माना जाता है कि शरीफ परिवार भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करता आया है। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल हुए थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया और नवाज शरीफ की पोती की शादी में शामिल हुए थे। आखिरी बार शाहबाज शरीफ दिसंबर 2013 में भारत दौरे पर आए थे जब उनकी मुलाकात उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई थी। दिल्ली दौरे पर उन्होंने मेट्रो से यात्रा भी की और दिल्ली के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का दौरा किया। उस दौरे पर वह पंजाब भी गए और उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। चर्चा इस बात पर भी हुई कि कैसे दोनों देशों के पंजाब आपस में सहयोग कर सकते हैं। जब शाहबाज शरीफ भारत आए थे तब उन्होंने कहा था कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने शांतिपूर्ण बातचीत की बहाली पर जोर दिया था जिसमें सियाचिन, सर क्रीक और कश्मीर शामिल है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि वह भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को ठीक करे।

तबाही की जिद

रूसी-यूक्रेनी संघर्ष में हजारों भाड़े के सैनिकों की उपस्थिति और रूस के खिलाफ कभी न खत्म होने वाले एंग्लो-अमेरिकन जुनून ने न केवल पूर्वी यूरोप में शांति को मायावी बना दिया है। और अगर चीन भी ताइवान पर कब्जा करने का फैसला करता है, तो यह दुनिया के अन्य हिस्सों में शांति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस जटिल युद्ध में अपनी तटस्थता बनाए रखने के भारतीय रूख को मार्च के तीसरे सप्ताह में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोहराया गया था कि 'संघर्ष के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति के मार्ग के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।' रूस के खिलाफ ब्रिटिश-अमेरिकी जुनून का पता जार हुकूमत के दौरान मध्य एशिया में रूसी विस्तारवाद के पिछले इतिहास और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों को इसके प्रारंभिक समर्थन से लगाया जा सकता है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दोनों पक्षों में बड़े पैमाने पर भाड़े के सैनिकों के शामिल होने से, शांति के मायावी बने रहने की संभावना है। नतीजतन त्वरित युद्धविराम भी इस युद्ध में स्थायी शांति सुनिश्चित नहीं कर सकता, जिसे टाला जा सकता था।

यदि कोई रूसी संगठन संघर्ष क्षेत्र में निजी सैनिकों को लुभाने के लिए यूक्रेन की एक लोकप्रिय पोर्क वसा 'सैलो' की पेशकश करता है, तो विपरीत पक्ष, जिसे उदारतापूर्वक पश्चिमी शक्तियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कथित तौर पर इन सशस्त्र स्वयंसेवकों को कहीं भी लड़ने के लिए तैयार करने के लिए प्रतिदिन 2,000 अमेरिकी डॉलर (1.40 लाख रुपए) तक की पेशकश कर रहा है। वैगनर समूह, जिसने कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की **हत्या करने की कोशिश** की थी, अब दो बार कथित तौर पर डोनबास क्षेत्र में सक्रिय हो गया है, जिसे हाल ही में रूस द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है। इस बीच चेचन मुसलमान दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। जबकि रमजान कादिरोव के लड़ाकों के नेतृत्व में पुतिन समर्थक समूह ने कथित तौर पर कीव के उत्तर में एक हवाई क्षेत्र ले लिया है और रूसी सेना का एक हिस्सा राजधानी की ओर बढ़ रहा है। रूस विरोधी चेचन भी कथित तौर पर युद्ध में शामिल हो गए हैं। सन् 1994 से 1996 और सन् 1999 से 2009 तक रूस के खिलाफ दो चेचन युद्धों के दिग्गज अब कथित तौर पर यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे पहले शेख मंसूर और द्जोखर दुदायेव बटालियन के नाम से जाने वाले दो चेचन स्वयंसेवक 2014 से डोनबास में रूसी समर्थित अलगाववादियों और नियमित रूसी सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे पहले 27 फरवरी को द्जोखर दुदायेव बटालियन के कमांडर एडम ओस्मायेव, यूक्रेन को जीतने में मदद करने की कसम खाई थी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में घोषणा की कि 'मैं यूक्रेनियन को बताना चाहता हूं कि असली चेचन आज यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं।'

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अशांति, संघर्ष और युद्धों ने निजी सैन्य कंपनियों के लिए बड़ी व्यावसायिक संभावनाओं को जन्म दिया है। वे खुफिया जानकारी इकट्ठी करते हैं, अमीर और शक्तिशाली को सुरक्षा प्रदान करते हैं और दुनियाभर में भाड़े के सैनिकों की आपूर्ति भी करते हैं। ऐसा अनुमान है कि उनका कारोबार साल 2030 तक 475 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मुख्यालय वाली कई निजी सुरक्षा कंपनियां हैं, जैसे साइलेंट प्रोफेशनल, मोजेक, सैंडलाइन इंटरनेशनल युद्धग्रस्त यूक्रेन में सक्रिय हो गए हैं। यह 90 के दशक के दौरान अंगोला और सिएरा लियोन की ओर से सक्रिय रहे हैं। अमेरिका स्थित खुफिया कंपनी मोजेक, 2014 से यूक्रेन में पहले से ही काम कर रही है। यह खुफिया जानकारी इकट्ठी करने और राजनीतिक रूप से उजागर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर मदद करने में बेहतरीन संगठनों में से एक के रूप में जाना जाता है।

एक अन्य निजी संगठन ब्लैकवाटर ने यूगोस्लाविया में गृहयुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खुफिया जानकारी एकत्र करने के अलावा इसने बोस्नियाई और निर्माण बलों को अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने में मदद की थी। इससे पहले जब रूसी सेना ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में यूक्रेन में मार्च किया था, तो यह अनुमान लगाया गया था कि यूक्रेन रूसी आक्रमण का कोई प्रभावी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि चार सप्ताह के सैन्य अभियानों के बाद भी यूक्रेनियन ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इस प्रकार युद्ध यूरोप में एक लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष बन गया है। यह क्षेत्र विशेष रूप से यूक्रेनियन, पहले के युद्धों में हमेशा अग्रणी राज्य रहा है। 8 दशक बाद वे फिर से एक युद्ध में हैं, जो कोई नहीं चाहता था। इससे पहले यूएसएसआर और नाजी जर्मनी ने मोलोटोव-रिबेंट्रोप के बीच समझौते के रूप में ख्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जब इसका सामना करना पड़ा था। इसने जर्मनी और यूएसएसआर के बीच पूर्वी यूरोप के विभाजन को जन्म दिया था।

● **कुमार विनोद**

चीन-रूस शिखर सम्मेलन

अमेरिकी राष्ट्रपति, जो बिडेन और चीनी राष्ट्रपति के बीच महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने जोर देकर कहा था कि रूसी-यूक्रेनी संघर्ष पर चीन की स्थिति हमेशा सुसंगत रही है। और इस प्रेक्षण को खारिज कर दिया कि इसमें कोई असंगति है। उनका बयान काफी सार्थक था, जब उन्होंने कहा- 'यह वे देश हैं, जो यह सोचकर खुद को भ्रमित करते हैं कि वे शीत युद्ध जीतने के बाद इसे दुनिया पर हावी कर सकते हैं, जो अन्य देशों की सुरक्षा की अवहेलना में नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को 5 बार चलाते रहते हैं। चिंताओं और जो दुनियाभर में युद्ध छेड़ते हैं, जबकि अन्य देशों पर जुझारू होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें वास्तव में असुविधाजनक महसूस करना चाहिए।'

विकास में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम

राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का प्रदर्शन कमजोर

महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं व पोषण की उपलब्धता उनके सशक्तिकरण का एक अनिवार्य कारक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय महिलाओं की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। दरअसल महिला सशक्तिकरण के उपायों को एकांगी रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कुल बजट का 3.4 फीसदी है, जबकि भूटान 7.7, नेपाल 4.6 फीसदी बजट स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध गरीबी के रूप में सामने आता है। लैंगिक समानता के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ानी होगी। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण की मांग पर राजनीतिक दलों की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है। विश्व लैंगिक भेद रिपोर्ट-2021 के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत का प्रदर्शन लगातार कमजोर हो रहा है।

दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महिला आरक्षण विधेयक देश के राजनीतिक परिदृश्य में विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। जाहिर है, लैंगिक समानता की इस ठोस कवायद के लिए न सिर्फ सभी राजनीतिक दलों को, बल्कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। विकास को समावेशी आवरण देने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक समानता से अंतर-संबंधित है। हमारे यहां महिलाओं को वैदिक काल से शक्ति का स्रोत माना गया है। महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र से लेकर विज्ञान तक में अपनी काबिलियत साबित की है।

मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र के सशक्तिकरण का प्रतीक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भावी नीतियों के निर्माण और योजनाओं को गति देने में महिलाओं की भूमिका को अहमियत दी जा रही है। इसका एक मकसद अर्थव्यवस्था को टिकाऊ स्वरूप देना भी है। यह अर्थ तंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से ही संभव होगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था की उत्पादकता से है। सामाजिक न्याय का कोई भी प्रयास महिलाओं की आत्मनिर्भरता से ही सुदृढ़ होता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी लैंगिक भेद सूचकांक (जीजीआई-2020) में भारत 112वें पायदान पर है, जबकि 2018 में यह स्थान 108वां था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार देश में महिला श्रमबल की भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 23.3 फीसदी है। श्रम क्षेत्र में महिला कार्यबल की भागीदारी कम होने के प्रभावों को लेकर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट हमें आगाह करती है। विश्व बैंक के अनुसार भारत के श्रमक्षेत्र में 2019 में महिलाओं का अनुपात 20.3 फीसदी था। यह पड़ोसी देश बांग्लादेश के 30.5 और श्रीलंका के 33.7 फीसदी से काफी कम है। आर्थिक मंदी हो या फिर कोरोना जैसी आपदा, इनका सबसे अधिक असर महिलाओं पर ही पड़ा।

गौरतलब है कि मार्च-अप्रैल 2020 में लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था, जो कुल महिला कार्यबल का 37 फीसदी था। ऐसे में हमें महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को नए सिरे से प्रभावी बनाना होगा। तभी हम लैंगिक असमानता खत्म कर महिलाओं को आगे ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आधी आबादी की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का कोई भी जतन शिक्षा के जरिए ही पूरा होगा। इसके लिए होने वाले बजटीय आवंटन के समय लैंगिक संवेदनशीलता को वरीयता देनी होगी। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को भी हासिल किया जा सकेगा। हमारे यहां स्कूलों में पुनः नामांकन, उपस्थिति आदि के तथ्यों में पारदर्शिता का नितांत अभाव बड़ी चुनौती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की दर 17.3 फीसदी रही। प्राथमिक स्तर पर यह 4.74 फीसदी रही। कर्नाटक, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक है। कोरोना महामारी ने छात्राओं और स्कूलों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार महिलाओं को शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। कौशल विकास के नाम पर अब भी हम सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाओं का एक बड़ा अनुपात असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। कुल कामकाजी महिलाओं में से लगभग 63 फीसदी खेती-बाड़ी के काम में लगी हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में महिलाओं की चुनौतियों का परिदृश्य अलग है।

2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार जब कैरियर बनाने का समय आता है, उस समय अधिकांश लड़कियों की शादी हो जाती है। विश्व बैंक के आंकलन के अनुसार भारत में महिलाओं की नौकरियां छोड़ने की दर बहुत अधिक है। यह पाया गया है कि एक बार किसी महिला ने नौकरी छोड़ी, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों व अन्य कारणों से पुनः श्रमबल का हिस्सा बनना कठिन होता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर रोजगार केंद्रित नीतियों में उद्योग जगत की जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका एक समाधान तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (वैज्ञानिकी) विषयों के अध्ययन के लिए महिलाओं के प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जाता है। देश में उच्च शिक्षा अर्जित करने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है। लेकिन विज्ञान व नवाचार से जुड़े विषयों में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व काफी कम है। स्कूली स्तर पर हैकथान कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर शोध व समस्या समाधान के प्रति छात्राओं में नवोन्मेषी दृष्टिकोण विकसित करना होगा।

आज रोजगार के अधिकांश अवसर सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र में उद्यमशीलता के बिना महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ाई जा सकती है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2019-20 के अनुसार भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.1 फीसदी हो गया। 2018-19 में यह 26.3 फीसदी था। इस दशक के अंत तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें जीईआर को 50 फीसदी के स्तर पर ले जाना होगा।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

अहंकार मत पालिए

मनुष्य को कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, जहां से वह अपनी भूल को समझकर बुरी वृत्तियों से वापसी कर सकता है, लेकिन कई बार अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि संकोच वश वह पुण्य के मार्ग पर वापसी नहीं कर पाता है। रामचरित मानस के उत्तरकांड में एक विशेष चौपाई है,

तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान।
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपासिंधु भगवान॥

इसका भाव है कि हे प्रभु! यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान! उस पर क्रोध न कीजिए।

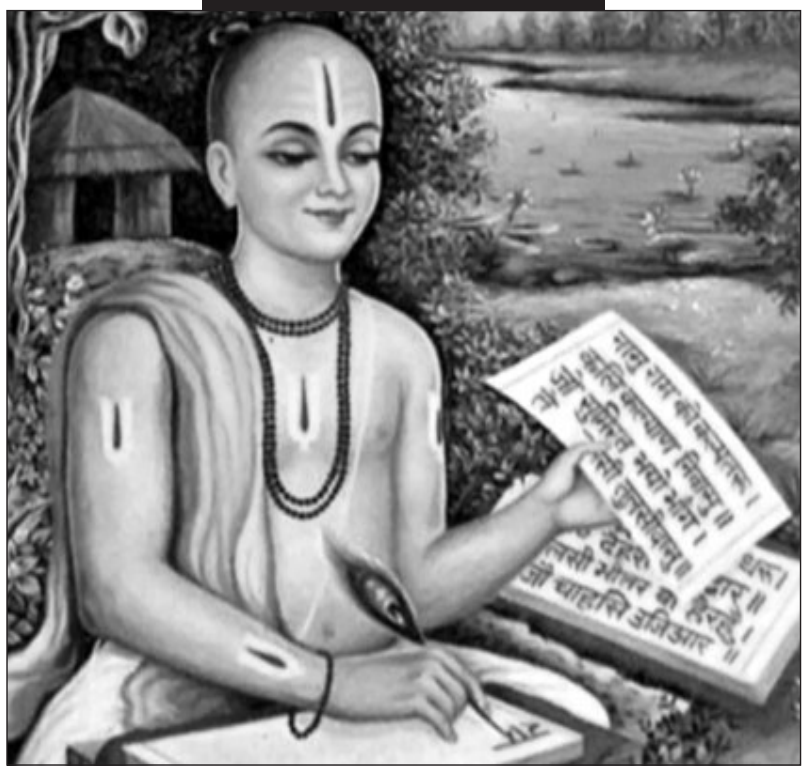

वस्तुतः यह प्रसंग कागभुशुंडि जी के लिए है, जिन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया था और उन्होंने प्रभु की परीक्षा लेनी चाही थी। गोस्वामी तुलसी दास जी ने यह चौपाई भले ही प्रसंगवश लिखी, लेकिन यह मानव समाज की सचाई है। मनुष्य चार पैसे कमा लेता है, धन का संचय कर लेता है, उसके सारे काम बनने लगते हैं तो इसके बाद वह खुद को ही सर्वे सर्वा समझने लगता है।

संसार में यहीं से माया के असर की वृत्ति का जन्म होता है, जो कभी मद और लोभ का आवरण चढ़ाकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष से पापकर्म करवाती है तो कभी महाभक्त और महाज्ञानी रावण से भी स्त्री हरण जैसा कृत्य करा डालती है। मनुष्य को कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, जहां से वह अपनी भूल को समझकर बुरी वृत्तियों से वापसी कर सकता है, लेकिन कई बार अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि संकोच वश वह पुण्य के मार्ग पर वापसी नहीं कर पाता है।

प्रहलाद के रूप में हिरण्यकशिपु को कई अवसर मिले, रावण को हर सेनापति की हार से अवसर मिला, अंगद और हनुमान के रूप में भी अवसर मिला, यहां तक की दुर्योधन को 18 दिन तक और हर भाई की मृत्यु के साथ अवसर मिलता रहा, लेकिन वही माया के वश में होकर जीव जड़ हो जाता है, अर्थात् मूर्ख हो जाता है।

आज के युग की भी यही समस्या है। समाज से लेकर प्रांत और पड़ोसी देशों और अन्य राष्ट्रों के साथ सीमाओं पर हो रही समस्या इसी माया का व्यापक खेल है।

तुलसीदास महाराज मानस में इस नाजुक पक्ष की ओर बड़ा ही करारा चोट करके इंगित करते हैं। जो भक्त माया के फेर को जल्दी समझ जाते हैं वह गरुण जी और कागभुशुंडि की तरह ही महान भक्त बनते हैं।

कौवे के रूप में जन्म लेने वाले कागभुशुंडि जी को श्रीराम का बाल स्वरूप देखकर संदेह हो गया था। प्रभु बाललीला में खिलौने के लिए रोते, पांव पटकते, भोजन में आना-कानी करते और चांद खिलौना मांगते। यह देखकर कागभुशुंडि जी को संदेह हो गया कि क्या यही त्रिलोक के स्वामी हैं। क्या ही श्री राम शेषशायी महाविष्णु के अवतार हैं? ऐसा संदेह करते हुए काग जी ने भगवान के हाथ से रोटी छुड़ा ली और आकाश में उड़ चला। कुछ दूर उड़ान भरने पर देखता क्या है कि एक नन्हा हाथ उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। काग जी घबराए और उड़ान तेज की लेकिन वह हाथ उनके बराबर पहुंच गया। ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, कैलाश, सूर्य-चंद्र सभी के पार और सभी से बड़ा वह नन्हा हाथ दिख रहा है। ऐसा देखकर कागभुशुंडि जी का संदेह दूर हुआ और वह त्राहिमाम करते हुए श्रीचरणों में जा गिरे। इसके बाद प्रभु ने उन्हें क्षमा कर अपनी भक्ति का वरदान दिया।

ऐसा ही संदेह गरुण जी को हो गया। जब प्रभु श्रीराम रण में अनुज लक्ष्मण समेत नागपाश में बंध गए थे। अचेत प्रभु की स्थिति देखकर हनुमान जी तुरंत ही गरुण जी को लिवा लाए। गरुण जी ने नाग बंधन तो काट दिया, लेकिन उनके मन में संदेह हो गया कि भव बाधा के बंधन काट देने वाले इस तुच्छ से नागपाश में बंधे कैसे?

ऐसा संदेह पहले उन्होंने नारद मुनि पर प्रकट किया, लेकिन नारद ने उन्हें ब्रह्म लोक भेज दिया। ब्रह्म देव ने गरुण जी को कैलाश भेजा और कैलाश पति ने पावन भक्ति का वरदान देते हुए गरुण जी को कागभुशुंडि जी के पास भेजा।

यहां काग जी ने गरुण जी को सविस्तार प्रभु की कथा सुनाई, अपने संदेह की कथा बताकर गरुण जी का संदेह दूर किया। मानस कई इस चौपाई का मर्म है कि मनुष्य प्रगति के पथ पर जरूर बढ़े, लेकिन उस प्रगति का घमंड न करे। किसी और की प्रगति में बाधक न बने। जिए और जीने दे का विचार रखे। तभी मानस का पाठ सार्थक होगा।

भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में युगों-युगों से मानव सभ्यता के प्रेरणा श्रोत रहे है। हमारी सनातन मान्यता के अनुसार श्रीराम विष्णु भगवान के अवतार हैं, वे आदिपुरुष हैं, जो मानव मात्र की भलाई के लिए मानवीय रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। मानव अस्तित्व की कठिनाइयों तथा कष्टों का उन्होंने स्वयं वरण किया ताकि सामाजिक व नैतिक मूल्यों का संरक्षण किया जा सके तथा दुष्टों को दंड दिया जा सके। रामावतार भगवान विष्णु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवतारों में सर्वोपरि है।

गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार श्रीराम नाम के दो अक्षरों में 'रा' तथा 'म' ताली की आवाज की तरह हैं, जो संदेह के पंछियों को हमसे दूर ले जाती हैं। ये हमें देवत्व शक्ति के प्रति विश्वास से ओत-प्रोत करते हैं। इस प्रकार वेदांत वैद्य जिस अनंत सच्चिदानंद तत्व में योगिवृंद रमण करते हैं उसी को परम ब्रह्म श्रीराम कहते हैं, जैसा कि राम पूर्वतापिन्युपनिषद में कहा गया है-

रमन्ते योगिनोअनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि।
इति रामपदेनासौ परंब्रह्माभिधीयते।

● **ओम**

फिक्र

चलो न मां हमारे साथ सरगुजा। एक साथ रहेंगे हम सब। मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं तुम्हें मिलने बार-बार नहीं आ सकता। तुम यहां अकेली रहती हो। यह मुझे अच्छा नहीं लगता।

मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी रहती है। वहां तुम्हारे लिए हर सुविधा है मां। हर चीज उपलब्ध है। राजेश के कहने पर सत्तरवां बंसत देख चुकी रूकमणी बोली- राजू! बेटा! मैं तो यहां बिल्कुल अच्छी हूं। तुम लोग वहां खुश हो; मैं भी यहां खुश हूं। मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पर अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो इस घर की क्या हालत होगी। इसकी देखभाल कौन करेगा। इसे मैं और तुम्हारे बाबूजी बड़ी मेहनत से बनाए हैं। बड़ी मुश्किल से यह छोटा सा आशियाना बना है बेटा। जाते-जाते उन्होंने मुझे इसकी देखभाल करने को कहा है। कहा है मुझसे कि अपने जीते-जी इस देहरी को कभी मत छोड़ना। रोज घर भर को बुहारती हूं। हर कमरे और आंगन को रोज लिपती हूं। हर आठवां दिन हर दीवार के नीचे को पींवरी छुई से खुंटियाना पड़ता है। दीवार पर टंगे तुम्हारे बाबूजी के फोटो पर मकड़ी जाल बना लेती है; उसे रोज साफ करती हूं। तभी मुझे चैन आता है। अगर मैं तुम्हारे पास चली जाऊंगी तो तुलसी में जल कौन डालेगा बेटा। पानी के बिना तुलसी मुरझा जाएगी; मर जाएगी। कभी-कभी बाड़ी के दौना के पौधे पर भी पानी डालना पड़ता है। बेटा, ये गइया जो है ना; शाम को घर आते ही मुझे नहीं देख खूब रम्भाती है। इसका बछड़ा दिन भर में चार-पांच बार अपने शरीर को खुजलवाने मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। मुझे तरिया में नहाना अच्छा लगता है राजू। एक और खास बात यह बेटा कि इस घर में मुझे तुम्हारे बाबूजी के होने का एहसास होता है। आज तो रूकमणी बस बोलती ही जा रही थी; और राजेश उनकी बातों को सुनता जा रहा था। मां-बेटा दोनों बड़े फिक्रमंद लग रहे थे।

- टीकेश्वर सिन्हा गब्दीवाला

अजनबी

वो सड़क पर कब से खड़ा भींग रहा है बारिश भी जोर की हो रही है, क्यूं न बारिश बंद होने तक उसे अपने बरामदे में बुला लाएं...

रघु अपनी बेटी मनू से कहता है...

न बाबा! ना..ना..ऐसे ही समय ठीक नहीं..किसी को भी सहारा देना खतरे से खाली नहीं... चोरी की घटना कितना सुनने को मिल रही है...

अरे अपने घर में चोरी के लिए क्या है...यही दो -चार बर्तन... ? इसके अलावा क्या मिलेगा किसी को... हाँ बोल...बुलाता हूं उसे...

चलो आ जाओ भाई! कुछ देर हमारी गरीब की झोपड़ी में शरण ले लो...बारिश थम जाएगी तो चले जाना...

राहगीर दौड़ता हुआ झोपड़ी में आता है..

मनू!..कोई कपड़ा तो दे दे...शरीर पोछनें को...

अभी आई बाबा...ये लो...

राहगीर पानी पोंछता हुआ एक भरी निगाह से झोपड़ी का मुआयना कर बैठा...

अरे बाबा!...ये यहां-वहां से टपकता है...कैसे रह लेते हो... ?

और कौन -कौन है तुम्हारे घर में... ?

क्यूं भाई... ? चोरी करने का इरादा तो नहीं...जो जानना चाहते हो...

मैं पहले ही बता देता हूं...हम बाप-बेटी के अलावा कुछ बर्तन है जो शोर करते है...बाकि हम गरीब के पास और कुछ नहीं...

कैसी बात करते हो बाबा तुम तो कीमती हीरा संभाल कर रखे हो...गरीब कहां... ?

बाबू तुम्हारी नजर में हम गरीब नहीं हैं ये अच्छी बात है और हम गरीब किसी अजनबी निगाह से हीरे को हमेशा बचाकर रखते है...

- सपना चन्द्रा

मेरी यात्रा

एक मां की कोख से
दूसरी मां की कोख तक है
मेरी यात्रा

एक मां ने
मुझे जन्म दिया है
एक मुझे अंत में देगी विश्रांति
एक ने मुझे जीवन सिखाया
दूसरी मुझे सोना सिखायेगी

इसके बीच
जो कुछ मैंने जिया
जो भी मैं जीऊंगा
जो भी मैंने सीखा
या सीखूंगा
वह मैं विसर्जित कर दूंगा

मां मुझे
पवित्र ही स्वीकार करेगी
एक मां से दूसरी मां
के बीच की यात्रा
जीवन के दो छोर
जन्म और मृत्यु हैं

मां मैं
तुम्हारी ओर आ रहा हूं
निरंतर
मेरे लिए अपनी गोद
में आश्रय रखना
मेरी पहली मां ने कहा है
कि तुम मेरी प्रतीक्षा
कर रही हो
तुम मेरे सारे दुख-दर्द
दूर करोगी
ऐसा उसने कहा है
और मैं जानता हूं कि
मेरी मां सच बोलती है

मां मैं
तुम्हारी ओर आ रहा हूं
अपनी गोद में
मेरे लिए
आश्रय रखना।

- अभिषेक सिंह

लाजवाब महिला क्रिकेटर

हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल नहीं धर्म की तरह है। इसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है। तभी तो कई क्रिकेटर भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्रिकेट देखने के लिए लोग अपना बहुत कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वक्त क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। एक तरफ बेंगलुरु में पुरुष क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच खेल रही है, तो दूसरी तरफ महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेल रही है। वैसे तो पुरुष टीम के मुकाबले महिला टीम की चर्चा लोगों के बीच बहुत कम होती है, लेकिन इस बार तीन महिला खिलाड़ी अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के जरिए सुर्खियों में बनी हुई हैं। इन तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धि ऐसी है कि जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए।

मिताली राज: इन तीनों खिलाड़ियों के बीच सबसे पहले बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के बारे में, जो हमेशा की तरह अपने परफॉर्म में नजर आ रही हैं। इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए मिताली ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो बतौर कप्तान सर्वाधिक आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने सेडॉन पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्डकप के तीसरे और ओवरऑल 24वें मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेलिंडा क्लार्क के नाम था, जिन्होंने 23 वर्ल्डकप मैच खेले थे। क्लार्क ने साल 1997 से 2005 तक के अपने कैरियर के दौरान 21 मैच जीते, एक हारा और एक मैच बेनतीजा रहा था। वहीं अपना आखिरी वर्ल्डकप खेल रही मिताली ने इस मैच को मिलाकर 24 में से 15 मैच जीते हैं, 8 हारे और एक बेनतीजा रहा है।

लेडी सचिन के नाम से मशहूर 39 साल की मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज के दौरान लखनऊ में बनाया था। उनसे पहले इंग्लैंड की शॉरलॉट एडवर्ड्स ये कारनामा कर चुकी हैं। मिताली अपना छठा वर्ल्डकप खेल रही हैं। वो साल 2005 के वर्ल्डकप में पहली बार टीम की कप्तान बनी थीं, तब भारतीय टीम उपविजेता रही थी। उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं।

स्मृति मंधाना: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दमदार पारी खेलते हुए शतक ठोका है। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में स्मृति मंधाना के बल्ले से निकली शतकीय पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थान पर पहुंचा दिया। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ा स्कोर हासिल करने के लिए एक बड़ी पारी की जरूरत थी, जो मंधाना के शतक की वजह से संभव हो पाया। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 108 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया। वर्ल्डकप में मंधाना का ये पांचवां शतक है, जिसमें से दो शतक तो उन्होंने इसी वर्ल्डकप में बनाए हैं। इस तरह महिला वर्ल्डकप के इतिहास में मंधाना के बल्ले से दूसरी बार शतकीय पारी निकली है। इससे पहले उन्होंने साल 2017 के वर्ल्डकप में शतकीय पारी खेली थी। देखा जाए तो इस बार का शतक ऐसे समय लगा है, जब टीम को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी।

साल 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू करने वाली स्मृति मंधाना ने साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। साल 2017 में मंधाना इंग्लैंड के खिलाफ फिर मैदान में उतरीं। इस बार उन्होंने 90 रन बनाए थे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्वकप के फाइनल तक पहुंच गई थी। बताते हैं कि स्मृति ने बचपन से ही अपने भाई को क्रिकेट खेलते देखा है। उनके भाई श्रवण महाराष्ट्र के लिए अंडर-15 टीम में खेलते थे। क्रिकेट में भाई की लगन और उनकी बनती पहचान को देख स्मृति मंधाना भी क्रिकेट की ओर आकर्षित हुईं। उन्होंने क्रिकेट में ही कैरियर बनाने की ठान ली। 11 साल की उम्र में स्मृति का अंडर-19 टीम में सिलेक्शन हो गया था। साल 2013 में स्मृति घरेलू मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आई थी। उस दौरान स्मृति ने गुजरात के खिलाफ 150 गेंदों पर 224 रन बनाए थे।

● आशीष नेमा

झूलन गोस्वामी ने लिए वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा विकेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने भी इस वर्ल्डकप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए इतिहास रच दिया है। वर्ल्डकप के 10वें मुकाबले में वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद का विकेट लेने के बाद वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं हैं। उन्होंने वर्ल्डकप में 40 विकेट लिए हैं। चकदा एक्सप्रेस नाम से मशहूर इस गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी लिन फुलस्टन को पछाड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फुलस्टन ने साल 1982 से 1988 के बीच खेलते हुए वर्ल्डकप में कुल 39 विकेट लिए थे। जबकि झूलन को ये रिकॉर्ड बनाने में 20 साल लग गए हैं। उन्होंने साल 2002 में 19 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था। झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल के साधारण कस्बे चकदा में पली-बढ़ी हैं। वो भी एक ऐसे परिवार में, जो लड़कियों के खेलकूद की बजाय उनकी पढ़ाई-लिखाई और शादी-विवाह के बारे में ज्यादा सोचता है। 15 साल की उम्र तक झूलन ने सपने में भी क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा नहीं था। वो क्रिकेट की बजाय फुटबॉल की प्रशंसक थीं। लेकिन इत्तेफाक ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में खींच लिया। साल 1997 में महिला क्रिकेट वर्ल्डकप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के इडेन गार्डन में खेला जा रहा था। उस मैच में झूलन भी मैदान पर एक बॉल गर्ल के रूप में मौजूद थीं। यहीं उन्होंने फैसला किया कि वो भी क्रिकेटर बनेंगी। हालांकि, उनकी सोसायटी में लड़कियों का लड़कों के साथ खेलना तक मना था।

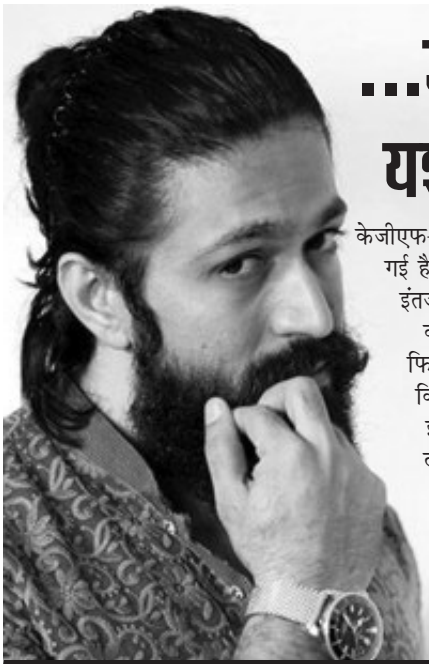

...जब फिल्मों में जाने की बात पर पिता ने यश को दी थी घर से निकालने की धमकी

केजीएफ-1 की बेहतरीन पॉपुलैरिटी के बाद 14 अप्रैल को केजीएफ चैप्टर-2 रिलीज हो गई है। कन्नड़ एक्टर यश के फैंस को पिछले कई महीनों से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। केजीएफ चैप्टर 1 ने 250 करोड़ का कलेक्श कर नया रिकॉर्ड कायम किया था। ये पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इस फिल्म के बाद एक्टर यश भी कन्नड़ इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर बने। एक इंटरव्यू के दौरान यश ने बताया था कि एक बार घर में उन्होंने फिल्मों में जाने की इच्छा जाहिर की थी। जिसके बाद उनकी फैमिली का रिएक्शन ठीक नहीं था। उनके पिता ने तो उन्हें घर से निकालने तक की धमकी दे दी थी। इसके बाद एक दिन यश अपने घर से 300 रुपए लेकर फिल्मों में हाथ आजमाने चले गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते आज वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं।

300 रुपए लेकर घर छोड़ा आज कन्नड़ के सबसे बड़े स्टार...

यश के फैंस ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड... केजीएफ ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और इसमें पूरा योगदान यश के फैंस का है। दरअसल यश के फैंस ने 23,400 किताबों की मदद से उनका सबसे बड़ा मोजेक पोट्रेट बनाया है। ये काम अखिल कर्नाटक रॉकिंग स्टार यश फैंस एसोसिएशन मालुर, कोलार ने किया है।

...अभिषेक बच्चन को देखने के लिए गांव के लोग ट्रैक्टर में भरकर आए थे

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, तब उन पर अपने पिता की पॉपुलैरिटी की वजह से काफी प्रेशर था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी के पहले सीन की शूटिंग को देखने के लिए पूरी स्टार कास्ट उनके काम को देखने के लिए आई थी, जिसकी वजह से वो काफी घबरा गए थे।

ढेर सारे लोग आ गए थे, अभिषेक को देखने

अभिषेक से जब पूछा गया कि उनके पिता की पॉपुलैरिटी की वजह से क्या उन पर ज्यादा प्रेशर था? इस पर अभिषेक ने कहा, सच कहूं तो हां। शुरुआत में ऐसा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मुझे याद है मैं रिफ्यूजी के लिए शूट कर रहा था। ये मेरी पहली फिल्म थी और मेरा पहला शूट था। उस समय वहां ढेर सारे लोग आ गए थे, मुझे देखने के लिए क्योंकि सबको सुनने में आया था कि बच्चन का बेटा जो है वो शूटिंग कर रहा है। अभिषेक ने आगे कहा, आस-पास के गांव के लोग ट्रैक्टर में भरकर आए थे। पूरी स्टार कास्ट, अनुपम खेर अंकल फोटो में मौजूद थे और वो मेरे एक्टिंग टीचर थे, जिन्हें मैं बचपन से जानता था। करीना, कुलभूषण खरबंदा जी, पद्मिनी कपाड़िया जी, यह सब लोग उस सीन में थे। रीना रॉय और बाकी एक्टर्स ये सोचकर आए थे कि अरे बच्चे का पहला शॉट है। देखते हैं क्या करता है।

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू आखिर क्यों नहीं करना चाहते बॉलीवुड में काम...?

महेश बाबू ने बॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया है। हाल ही में एक्टर ने एक इवेंट अटेंड किया, जिसके दौरान उनसे हिंदी फिल्मों में काम करने के बारे में पूछा गया। जिस पर एक्टर ने कहा कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने की जरूरत नहीं है। साथ ही महेश बाबू ने कहा कि वो एक तेलुगु फिल्म कर सकते हैं और वही फिल्म दुनिया भर के लोग देखेंगे। आजकल हिंदी फिल्मों से ज्यादा, लोग साउथ की फिल्में देख रहे हैं।

मुझे हिंदी फिल्मों में काम करने की जरूरत नहीं

तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू हैदराबाद में एक पब्लिक इवेंट अटेंड करने पहुंचे थे। इवेंट में जब उनसे हिंदी फिल्मों में काम करने को लेकर पूछा गया, तो एक्टर ने कहा, मुझे हिंदी फिल्मों में काम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक तेलुगु फिल्म करुंगा और आजकल वही पूरे देश में देखी जा रही है। इसलिए मुझे खास तौर पर हिंदी फिल्मों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां एक तरफ कई साउथ के स्टार्स बॉलीवुड में अपनी डेब्यू फिल्म साइन कर रहे हैं, वहीं महेश बाबू के इसको लेकर अलग विचार हैं। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महेश बाबू ने आरआरआर के डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ एक फिल्म भी साइन की है। इवेंट में जब महेश से राजामौली के साथ काम करने को लेकर पूछा गया तो एक्टर ने कहा, मैं राजामौली के प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हूं।

त्रिया चरित्रं बनाम पुरुष चरित्रं

साहित्य मानव-चरित्र का जीवंत इतिहास है, तो इतिहास मानव-चरित्र का मुर्दा साहित्य है। 'महाभारत' में भी कहा गया है- 'नृपस्य चित्तं, कृपणस्य वित्तम, मनोरथाः, दुर्जन मानवानाम। त्रिया चरित्रं, पुरुषस्य भाग्यं, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः।।' यही कारण है कि हमारे पुराण, महाभारत, रामायण, कथा साहित्य (कहानी, उपन्यास आदि), नाटक, एकांकी, काव्य (मुक्त, प्रबंध काव्य, खण्ड काव्य आदि), संस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि में मानव-चरित्र को विभिन्न कोणों और आयामों से प्रदर्शित और व्याख्यायित किया गया है। स्त्री और पुरुष के सर्वांगीण चरित्र का आख्यान मानव जाति के आदि काल से अद्यतन और सृष्टि के अंत तक भी नहीं हो सका और न ही हो सकेगा। अपने अनन्त आयामों और स्वरूपों में वह अपने विविध रूप बदलता रहेगा। जैसे कोरोना का वायरस अपने नए स्वरूपों में सामने आ रहा है। 'तू डाल-डाल मैं पात-पात' की कहानी की पुनरावृत्ति कर रहा है। उसी प्रकार मानव-चरित्र के विविध नहीं, अनंत आयाम हैं; जिन्हें विश्व की विविध भाषाओं के साहित्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार आदि सभी को अपनी कला-साधना का कच्चा माल मिलता रहेगा।

मानव (स्त्री और पुरुष) विधाता की सृष्टि के विलक्षण सृजन हैं। विधाता कदाचित एक मानव को बनाने के बाद उसका सांचा तोड़कर फेंक देता है। जितने स्त्री पुरुष, उतने ही सांचे। एक साथ पैदा होने वाले जुड़वाओं के रूप-स्वरूप, आकार-प्रकार, गुण-दोष, चरित्र आदि सब विचित्र से विचित्र ही हैं। कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं, पुनराकृति नहीं। समानता नहीं। धन्य हैं विधाता!

इतना सब वैविध्य होने के बावजूद कुछ ऐसे तत्व भी शोधित गए हैं, जिनके आधार पर यह मान लिया जाता है कि अरे! वह त्रिया है; ये सब चरित तो उसमें होगा ही। इसी प्रकार पुरुष की प्रकृति के प्रति भी स्थाई धारणा बन गई है। ऐसी की कतिपय उभयनिष्ठ कलाकारिताओं को दिग्दर्शन किया जाना यहां दृष्टव्य है।

अब प्रश्न उठता है कि पहले कौन? स्त्री या पुरुष? तो दुनिया के प्रचलित नियम के आधार पर स्त्री ही आगे है; तभी तो 'लेडीज फर्स्ट' कहा गया है। उसे सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि उसे मूर्ख बनाकर ठगने के लिए। भले ही उसकी उत्पत्ति पुरुष की बायीं पसली से हुई हो; पुरुष की एकांतिक नीरसता-निवारण, मनोरंजन, सृष्टि के विकास आदि के लिए वह बाद में आई हो। तुलसी बाबा तो अपने रामचरित मानस में कह गए हैं- 'नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं। अवगुण आठ सदा उर रहहीं।' 'साहस, अनृत, चपलता, माया। भय, अविवेक, अशौच अदाया।' तुलसी बाबा भी बहुत कहना चाहकर भी सब कुछ नहीं कह पाए। त्रियाओं के पेट में बात नहीं पचती, इसलिए पति को भी उसे रहस्य की बात नहीं बतानी चाहिए। नौ मास के लिए ढाई किलो के टाबर (शिशु) को पेट में रख लेगी, किंतु एक रहस्य की बात हजम नहीं कर पाती। इससे पुरुष को एक लाभ यह है कि जो बात कहने में स्वयं कोई भय हो, शंका हो; उसे अपनी पत्नी या किसी भी नारी को बता दें, सवेरा तब होगा, जब वह रहस्य की बात जन-जन की जुबान पर इस शर्त के साथ होगी कि 'किसी को बताना मत।' और वह बात किसी को बताना मत के मंत्र के बाद जंगल की आग बन जाएगी। अगर यही गुण पुरुष में हो तो उसे स्त्रीत्व से असम्मानित करते हुए यही कहा जाता है कि औरतों जैसी बात क्यों करते हैं।

स्त्रियां अपने रूप सौंदर्य, उसकी देखभाल, स्व सजावट, घर की सजावट आदि के प्रति आशा से भी ऊपर तक चैतन्य रहती हैं। इसलिए शृंगार तो मानो उनका स्वभाव ही बन गया है। इसलिए पुरुष ने नारी को सोने-चांदी की शृंखलाओं में कैद करने में सफलता पा ली। नारी में निर्लज्जता का भाव पुरुष से आठ गुना अधिक बताया गया है।

स्त्रियां अपने रूप सौंदर्य, उसकी देखभाल, स्व सजावट, घर की सजावट आदि के प्रति आशा से भी ऊपर तक चैतन्य रहती हैं। इसलिए शृंगार तो मानो उनका स्वभाव ही बन गया है। इसलिए पुरुष ने नारी को सोने-चांदी की शृंखलाओं में कैद करने में सफलता पा ली। नारी में निर्लज्जता का भाव पुरुष से आठ गुना अधिक बताया गया है। भले ही पुरुष में नारी से 100 गुना अधिक विद्यमान हो। इसको नारी का सहज आभूषण भी बताया गया है। यदि ये नहीं, तो कुछ भी नहीं। मानवेतर जीवों मोर, मुर्गा, मेंढक, शेर, गौरैया आदि में नर-नारी से अधिक सुंदर माना गया। इसके विपरीत पुरुष नारी सौंदर्य पर मरता मिटता हुआ देखा गया।

त्रिया चरित्र और चाल अपने हर रंग में पुरुष से अलग ही हैं। स्त्री चाहे जैसे वस्त्र धारण कर ले, जाते हुए पीछे से ही जाना जा सकता है, गमन करने वाला पुरुष नहीं, नारी है। उसके हाथ, पैर और कटि का विशेष हिल-डुल संचलन उसकी एक अलग ही छवि बनाता है। यही छवि उसकी पहचान बन जाती है। विधाता ने नारी कंठ को एक अलग पहचान दी है। पुरुष का कंठ भारी और भर्राया हुआ। वह कोकिल कंठी है, यद्यपि कोकिल नर है; मादा नहीं। पर सुंदरता के नाम पर कोयल को नारी बना दिया गया है।

जब चरित्र की बात होती है तो पुरुष ने नारी को ही चरित्र की मालिकीयत प्रदान कर रखी है। यद्यपि पुरुष सौ गुना अवगुण संपन्न हो, किन्तु उसकी चरित्र हीनता के चर्चे भी नहीं होते। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दुनियाभर के चकला घर पुरुषों के ही कारण फूल-फल रहे हैं। यदि चरित्र की शिथिलता की बात आती है, तो पुरुष स्त्री से मीलों आगे हैं। लड़की वो अचार की मटकी हाथ लगे कीड़े पड़ जाएं! पुरुष लगाए दाग देह पर और स्वयं सीधे बच जाएं। क्या बिना पुरुष कोई भी नारी दूषित हो सकती है? कदापि नहीं। पूरक जैविक अनिवार्यता से पुरुष साफ बचकर निकल जाता है। पुरुष का हर ढोंग प्रत्येक अर्थ में नारी को अधोगामी बनाता आया है। आज भी बना रहा है। इसीलिए उसने नारी पर अनेक प्रतिबंध- घूंघट, हिजाब, पर्दा, गहने, बिंदी, सिंदूर, क्रीम, पाउडर, लिपिस्टिक, मांग, हाई हील उपानह; सब ठगी के उपकरण। मानो वह दोयम दर्जे की नागरिक हो। पुरुष हजार गुनाह करे, फिर भी दूध धुला। नारी आंशिक भी अपने खूंटे से हिल जाए, तो पापिन, दुष्चरित्र, वेश्या, कुलक्षणी, नगरवधू और न जाने क्या-क्या? पुरुष के खुलेआम अत्याचार की इन्तहां। पैर की जूती, किसने बनाया, पुरुष ही ने न?

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

आजादी का अमृत महोत्सव

बेहतर कल के लिए हर-घर नल से जल

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

"मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुँचाने का अभियान पूरी गति से चल रहा है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता वाले ग्राम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 4258 ग्राम इस श्रेणी में शामिल, जिनके 48 लाख 69 हजार से अधिक परिवार स्वच्छ पेयजल की सुविधा पा रहे हैं। वर्ष 2024 तक 122 लाख ग्रामीण परिवारों के घर तक जल पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के तहत सभी जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये जाएं"

2024 तक 'हर घर जल' वाला राज्य बनाने की योजना

जल-प्रदाय योजनाओं के लिए
30 हजार 668 करोड़
रुपए स्वीकृत

पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था

39.62% ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन से पेयजल की उपलब्धता

स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में भी नल कनेक्शन से दिया जा रहा है पेयजल